राजस्थान विधान सभा

तृतीय बैठक, बुधवार, २ मार्च, सन् १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन जयपुर में ८ बज कर ३७ मिनिट (मध्यान्होत्तर) पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ७

महात्मा गांधी हॉस्पीटल, जोधपुर के डा० सोनी का अपहरण तथा उस संबंधी शासकीय कार्यवाही

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. क्या यह सच है कि महात्मा गांधी हॉस्पिटल, जोधपुर के डॉक्टर सोनी, का अपहरण किया गया ?

२. यदि हां, तो अपहरण करने वाले कौन-कौन हैं और उनके खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

३. उक्त अपहरण कब किया गया ?

४. क्या यह सच है कि उक्त डाक्टर के अपहरण के पूर्व उक्त डॉक्टर के जेर इलाज किसी राजा की मृत्यु हो गई थी ?

५. यदि हां, तो उक्त राजा कौन थे ?

६. क्या यह सही है कि मृतक राजा के परिवार वालों ने डॉक्टर सोनी का अपहरण करो कर उसको मार डाला ?

७. उक्त डॉक्टर के परिवार को सरकार द्वारा क्या सहायता की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—

Page No.2

[श्री रामकिशोर व्यास]

१. यह सत्य है कि डा० सोनी का अपहरण हुआ।

२. रावतसिंह नामक व्यक्ति पर अपहरण का शक किया गया था किन्तु उसके विरुद्ध पूर्ण सबूत न होने से कोई कार्यवाही नहीं की गई।

३. ता० २६.६.५१ को रात के ६ बज कर १५ मिनट पर।

४. जी हां, यह सत्य है।

५. जैसलमेर के भूतपूर्व महारावल श्री गिरधारीसिंहजी।

६. यह असत्य है क्योंकि तफतीश से यह जाहिर नही हुआ।

७. सरकार ने डॉ० सोनी के परिवार की सहायता के लिये राजस्थान सर्विस रूल्स में विशेष तौर से निम्न मात्रा तक शिथिलतायें प्रदान कर दी हैं :

(क) आर. एस. आर. की धारा १६८ के आधीन पेन्शन के लिये अपेक्षित अनौपचारिक वैकल्प की शर्त हटा दी जाय।

(ख) आर. एस. आर. को धारा २५७ के प्रयोजनों के लिये ५ साल पूरे होने में रहने वाली कमी को क्षमा कर दिया जाय।

(ग) मृत्यु के समय डा० सोनी के वेतन से १२ गुनी मृत्यु ग्रेच्युटी दी जाय। इसमें से उनके प्रोवीडेन्ट फन्ड क्रेडिट में से सरकार का हिस्सा कम कर लिया जायेगा।

श्री चांदमल मेहता—डा० सोनी के अपहरण का क्या कारण था?

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो मैं कुछ नहीं बता सकता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उसका अपहरण पैसे के लालच से नहीं किया गया?

श्री रामकिशोर व्यास—यह मेरे ख्याल से सही नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—तफतीश के दौरान में आपको उसके अपहरण का क्या कारण मिला?

श्री रामकिशोर व्यास—इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कोई खास बात नहीं कही जा सकती, मगर सस्पीशियन ऐसा होता है कि कुछ लोगों ने उसको उठाने का षड़यंत्र किया हो।

श्री चांदमल मेहता—वे कौन लोग थे और सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की?

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो सस्पीशियन की बात है।

श्री चांदमल मेहता—आप वास्तविक बात बतावें, वह क्या है ?

श्री खेतसिंह—क्या यह सही है कि डा० सोनी ने जैसलमेर के भूतपूर्व महारावल को एन्टी वेनम का इन्जेक्शन बिना सोचे समझे दिया था ?

श्री रामकिशोर व्यास—हां, एन्टी वेनम का इन्जेक्शन दिया गया था। बिना सोचे-विचारे दिया, यह नहीं कह सकते।

श्री खेतसिंह—क्या उसी इंजेक्शन की वजह से महारावल की मृत्यु हुई ?

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि पुलिस ने तफतीश में अच्छी तरह से जांच नहीं की ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह सही नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह—क्या प्रश्नकर्त्ता सबूत दें तो सरकार कुछ कार्यवाही करेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास—अवश्य।

श्री खेतसिंह—क्या सरकार को यह मालूम हो गया है कि वह मर गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—हमने प्रिज्यूम किया कि मृत्यु हो गई।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सरकार ने वास्तव में दोषी व्यक्ति को नहीं पकड़ा और जो रावतसिंह छूटा है तो क्या सरकार वास्तविक दोषी व्यक्ति को पकड़े......

श्री रामकिशोर व्यास—उसके खिलाफ कोई सुबूत नही था।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि पुलिस सुबूत इकठा करने में असफल रही ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह सही नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—पुलिस ने क्या सबूत पैदा किया ?

श्री रामकिशोर व्यास—पुलिस से, जितनी कोशिश हो सकी, किया गया; फिर भी उसके खिलाफ कोई सुबूत नहीं मिला।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस मामले में जांच की गई कि पुलिस ने तहकीकात में कोई कमी रखी है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—पुलिस की ओर से कोई कोताई नहीं की गई।

श्री चांदमल मेहता—किसने जांच की ?

श्री रामकिशोर व्यास—जो इन्चार्ज था।

श्री चांदमल मेहता—कौन था ?

श्री रामकिशोर व्यास—एस, पी., डी. वाई. एस. पी.।

श्री चांदमल मेहता—तफ़तीस करने वाला कौन था ?

श्री रामकिशोर व्यास—अलग से प्रश्न पूछें तो बता सकता हूं।

श्री खेतसिंह—क्या यह सही है कि डा० सोनी जोधपुर से मर्जी से मोटर में बैठ कर तशरीफ़ ले गये ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह मैं नही बता सकता।

श्री जवानसिंह—जो सस्पीशियन बताया जाता है उसका क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास—तफ़तीश के दौरान में जो जाहिर हुआ वह बताया।

श्री जवानसिंह—में यह जानना चाहता हूं कि सस्पीशियन्स है, सुबूत नहीं।

श्री रामकिशोर व्यास—यह अलग से सवाल पूछिये।

श्री जवानसिंह—आपने बताया कि सस्पीशियन्स हैं, तो वे क्या हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने बताया कि रावतसिंह के लिए कोई प्रमाण नहीं मिला है इसलिए उसको छोड़ दिया गया हैं। फलां गवाह ने क्या कहा और क्या नहीं कहा तथा किसकी क्या शाहदत है, यह अलग से प्रश्न है।

श्री जवानसिंह—इस प्रश्न छः के जवाब में पूछा जाने वाला सप्लीमेन्टरी वाजिब है; सस्पीशियन्स हैं वे क्या हैं ? प्रश्न ६ को देखिये।

श्री रामकिशोर व्यास—जी हां, मैंने देखा है। उसका जवाब मैंने दिया था कि यह बात सही नहीं है, असत्य है।

श्री जवानसिंह—जवाब दिया है कि सरकार को सस्पीशियन मालूम हुआ है, बल्कि सुबूत नहीं मिला है। हम यह जानना चाहेंगे कि वे सस्पीशियन्स किस आधार पर मान बैठे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—६ के उत्तर में है।

श्री जवानसिंह—प्रश्न ७, उसका दूसरा भाग ६।

Page No.5

श्री रामकिशोर व्यास—जवाब दिया कि कोई सबूत नहीं है ।

श्री जवानसिंह—किसी रेस्पेक्टेबल सिटीजन के दिमाग में सस्पीशियन लगाये, तो सदन जानना चाहेगा कि वे सस्पीशियन्स क्या हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—हमने महारावल के सक्सेसर (Suceessor) के लिए नहीं कहा है ।

श्री जवानसिंह—मैं सस्पीशियन्स के लिए जानना चाहूंगा कि वे किस आधार पर हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—तफतीश के दौरान में शहादतें आयीं......

श्री जवानसिंह—वे क्या शहादतें आईं, हम जानना चाहेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास—ये डिटेल्स की बातें हैं । शहादतें जानना चाहेंगे तो बता सकता हूं, लेकिन इसके लिए अलग से सवाल पूछिये ।

श्री अध्यक्ष—Facts which are not onfirmed are suspicions.

प्रश्न संख्या ८

यज्ञनारायण हॉस्पिटल, किशनगढ़ में डेड बॉडी रूम की व्यवस्था

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि किशनगढ़ के यज्ञनारायण होस्पिटल में Dead Body Room नहीं है ?

(२) यदि हां, तो सरकार कब तक बनाने का विचार रखती है ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मंत्री)—

(१) जी हां ।

(२) मार्च १९५५ के अन्त तक बना दिया जायगा ।

श्री चांदमल मेहता—अब तक नहीं बना देने का क्या कारण है ?

श्री कुम्भाराम—अब तक आवश्यकता महसूस नहीं हुई ।

(हंसी)

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि मृतक व्यक्ति को १२ बजे, २ बजे रात को भी डेड बोडी रूम नहीं होने से, हॉस्पिटल से बाहर ले जाना पड़ता है ?

श्री कुम्भाराम—ऐसी घटना नहीं घटी।

श्री चांदमल मेहता—क्या ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि रात को हॉस्पिटल में कोई नहीं मरा ?

श्री कुम्भाराम—मरने वाला कभी भी मर जाता है।

श्री चांदमल मेहता—रात को मरने पर भी क्या डेड बॉडी को वहीं रखा जाता है ?

श्री कुम्भाराम—उस हॉस्पिटल में ऐसी घटना नहीं घटी।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्रीजी को मालूम है कि मरने वालों के लिए कोई पाबन्दी नहीं कि रात ही को मरे ?

श्री कुम्भाराम—यह मैंने पहले ही बता दिया।

श्री जवानसिंह—यह तारीख बतावें कि उस तारीख को रात को मरने वाला है ?

श्री कुम्भाराम—सदस्य महोदय से पूछिये।

श्री चांदमल मेहता—इसकी मंत्रीमण्डल के माननीय मंत्री जी के पास भी शिकायत नहीं पहुँची कि फलां मुर्दा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है ?

श्री कुम्भाराम—नहीं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या ६

राजस्थान के निर्माण के पूर्व तथा पश्चात् इन्डोर पेशेन्ट्स के रहने की व्यवस्था

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान के निर्माण के पूर्व सवाई मानसिंह अस्पताल में कितने इन्डोर पेशेन्ट्स के रहने की व्यवस्था थी ?

(२) राजस्थान के निर्माण के बाद उसमें कितनी वृद्धि हुई ?

(३) वर्तमान समय में जनरल वार्ड व किराये के कमरों में कितने-कितने मरीजों के रहने की व्यवस्था है ?

(४) क्या यह सही है कि किराये के कमरों में जनसाधारण को बहुत कम स्थान मिलता है ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मंत्री)

(१) ४१४.

(२) १५१ पलंगों की वृद्धि की गई।

(३) ५२८ पलंग जनरल वार्ड के बीमारों के काम आते हैं और ३७ किराये के कमरों के लिये हैं।

(४) जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किराये के कमरों की संख्या अपर्याप्त है ?

श्री कुम्भाराम—कम तो नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो कमरे हैं उनमें से अधिकतर राज्य कर्मचारियों के लिये वे काम में आते हैं और जनसाधारण को नहीं मिलते ?

श्री कुम्भाराम—ऐसा कोई कानून नहीं है। बीमार हो जाये तो उनके काम आते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या किराये के कमरों में और वृद्धि करने का विचार है ?

श्री कुम्भाराम—जी हां।

श्री चांदमल मेहता—कब तक ?

श्री कुम्भाराम—मुट्ठी में पैसा होगा जब।

श्री चांदमल मेहता—पैसा होने की आशा कब तक रखनी चाहिये ?

श्री कुम्भाराम—आशा रखनी चाहिये।

श्री चांदमल मेहता—पैसा रोकने की क्या तजवीज है ?

श्री कुम्भाराम—मैं समझा नहीं।

श्री राज हिम्मतसिंह—क्या राज्य कर्मचारी ज्यादा बीमार पड़ते हैं ?

श्री कुम्भाराम—यह सदस्य महोदय से ही पूछिये, यह उनकी शंका है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या १८

सन् १९५४-५५ में विभिन्न जिलों में कम्प्रेशर्स द्वारा कार्य

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनकि निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) सन् ५४-५५ के वर्ष में ऑफिसेज़ की इमारतें बनाने के लिये जयपुर डिस्ट्रिक्ट के लिये कुल कितने रुपये स्वीकृत किये गये ?

(२) उक्त रकम में से कहां-कहां ऑफिसेज़ बन चुके हैं और उन पर कितना रुपया खर्च किया जा चुका है ?

(३) क्या यह सही है कि रूपनगर तहसील की इमारत बनाने के लिये इस वर्ष रकम स्वीकृत की गई है; लेकिन इमारत नहीं बनाई गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

१. सन् १९५४–५५ में डिस्ट्रिक्ट जयपुर में ऑफिसेज़ की इमारतों के लिये ४, ७६, ९७५ रु० रक्खे गये हैं।

१. उक्त रकम में से निम्नलिखित ३ जयपुर शहर की और १ सांभर की इमारतों के कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं और इन पर जो व्यय जनवरी १९५५ तक हो चुका है वह साथ में बताया गया है—

१.	डाइरेक्टर पब्लिकरिलेशन मुख्य सचिवालय, जयपुर	रु० ४३४१७
२.	मौजूदा हाईकोर्ट बैन्च में नये कमरे बनना, जयपुर	रु० ४१३४९
३.	सबॉर्डिनेन्ट कोर्ट में रद्दोबदल, जयपुर	रु० १८०४
४.	सिविल सेशन्स जज साँभर के कोर्ट की लेबोटॉरी में रद्दो बदल, सांभर	रुपयों का पेमेण्ट होना बाकी है।

३. रूपनगर तहसील के लिये इस वर्ष कोई रकम स्वीकृत नहीं की गई।

श्री चांदमल मेहता—क्या आयन्दा वर्ष के लिये रूपनगर तहसील की इमारत के लिए सरकार रकम स्वीकृत करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह अलग सवाल है।

श्री चांदमल मेहता—पिछले साल यह अश्वासन दिया गया था कि इस वर्ष रूपनगर तहसील की इमारत बन जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मुझे इसका पता नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—जो रकम स्वीकृत हुई उनमें से कौन कौन से काम होने बाकी हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जो काम चल रहे थे वे काम कम्प्लीट हो गये। उनका १ लाख का पेमेन्ट हो चुका है और १ लाख का पेमेन्ट मार्च तक हो जायगा।

श्री चांदमल मेहता—इन चार कामों के अलावा जयपुर डिस्ट्रिक्ट में और कोई काम करने की योजना नहीं थी ?

श्री गुप्ता—इस साल नहीं थी।

प्रश्न संख्या ११

सन् १९५४-५५ में विभिन्न जिलों में कम्प्रेशर्स द्वारा कार्य

श्री चांदमल मेहता—क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

१. कृषि विभाग में कितने कम्प्रेशर्स है ?

२. ५४-५५ के वर्ष में किस किस डिस्ट्रिक्ट में कम्प्रेशर्स द्वारा कितना काम किया गया ?

श्री रामनिवास मिर्धा—(कृषि मंत्री)

(क) कृषि विभाग में १७ कम्प्रेशर्स हैं।

(ख) माह दिसम्बर के अन्त तक ५४-५५ में ६८० कूए खोदे गये। जहां जहां कूए खोदे गये उनकी जिलेवार संख्या निम्न प्रकार है—

(१)	जयपुर	६८.
(२)	सीकर	२०.
(३)	भीलवाड़ा	१४३.
(४)	टोंक	३३.
(५)	चित्तौड़	३०,
(६)	उदयपुर	३५
(७)	अलवर	६३.
(८)	झालावाड	१९३.
(९)	कोटा	५०.
(१०)	डूंगरपुर	४५.

श्री चांदमल मेहता—जिन कुओं का होना बताया गया है क्या वे नये खोदे गये या गहरे किये गये ?

श्री रामनिवास मिर्धा—ये कुए ज्यादातर गहरे किये गये हैं। कम्प्रेशर्स, कुए गहरे करने के ही काम आते हैं।

श्री खेतसिंह—क्या खास वजह है जिससे जोधपुर डिविजन के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी कुआ किसी भी विभाग की तरफ से नहीं खोदा गया ?

श्री मिर्धा—अभी तक कम्प्रेशर्स का वितरण कुछ ही जिले के हैडक्वार्टर्स पर हुआ है। जब वितरण में हेर-फेर हो जायगा तो जोधपुर के डिस्ट्रिक्ट्स में भी कम्प्रेशर्स दे दिये जायेंगे।

श्री खेतसिंह—कब तक दे दिये जावेंगे ?

श्री मिर्धा—बहुत शीघ्र।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन जिलों में इनको दिया गया उनमें इसका उपयोग पूरी तरह से नहीं हो पाया ?

श्री मिर्धा—उपयोग पूरी तरह से होता है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत है कि जहां कम्प्रेशर्स से काम किया गया वहां लोगों का पैसा व्यर्थ में खर्च हुआ ?

श्री मिर्धा—ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास नहीं है।

श्री जेलिया—क्या सरकार के पास कोटा डिविज़न के किसानों की शिकायत इस संबंध में आई है कि कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट की तरफ से जो काम किया गया वह अच्छा नहीं हुआ ?

श्री मिर्धा—ऐसी कोई शिकायत सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

श्री धूलजी भाई—बांसवाड़े की हुरड़ा और सराड़ा तहसील के किसानों ने करीब ५००–७०० रूपया डिपॉजिट करवाया फिर भी उनको कुए गहरे करने के लिये कम्प्रेशर्स नहीं दिये गये !

श्री मिर्धा—यह एक विशेष प्रकार का केस है। इसकी जानकारी करने से ही बताया जा सकता है।

श्री हरिसिंह—क्या यह सही है कि कि सिरोही के अन्दर जो कम्प्रेशर्स रखे हुए हैं, वे काम नहीं आ रहे हैं।

श्री मिर्धा—हां दो कम्प्रेशर्स जो सिरोही स्टेट से आये थे वे काम नहीं कर रहे हैं।

श्री कानसिंह—बीकानेर डिविज़न में जहां कि पानी की बहुत कमी है वहां कम्प्रेशर्स क्यों नहीं भेजे गये ?

श्री मिर्धा—जैसा कि मैंने पहले बताया जोधपुर और बीकानेर डिविजन में अगले साल कम्प्रेशर्स भेज दिये जायेंगे।

श्री वेदपाल त्यागी—इन कम्प्रेशर्स से लास्ट ईयर कितने कुए खोदे गये और इस साल कितने ?

श्री मिर्धा—सन् ५३-५४ में कुल १६५ कुए खोदे गये। इस साल दिसम्बर के आखिर तक ६८० कुए खोदे गये तथा जनवरी, फरवरी और मार्च तक ३०० और कुए खोदे जाने की आशा है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार कम्प्रेशर्स की वर्तमान संख्या को काफी समझती है।

श्री मिर्धा—अभी जो १७ कम्प्रेशर्स हैं वे काफी नहीं हैं, इसी वजह से आगामी वर्ष में १५-२० कम्प्रेशर्स और खरीदे जा रहे हैं।

श्री त्यागी : आपके कहने के मुताबिक मुगालता हो जाता है कि कुए नये खोदे गये या गहरे किये गये। अगर गहरे किये गये तो वैसा बतलाया जाय।

श्री मिर्धा : कम्प्रेशर्स का काम ही कुओं को गहरा करना होता है। जब पत्थर की चट्टान आ जाती है तो उस समय कम्प्रेशर्स को काम में लिया जाता है।

श्री हरिसिंह : क्या जालोर डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने अपने यहां कम्प्रेशर्स भेजने की मांग की थी ?

श्री मिर्धा : यह सही है कि जालोर और दूसरे जिलों से भी काफी मांग आती है। मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि अगले साल उनकी मांग की पूर्ति कर दी जायगी।

श्री धूलजी भाई : क्या बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से कम्प्रेशर्स के लिये मांग आई थी ?

श्री मिर्धा : मैं निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकता किन्तु यह सही है कि हमारे पास बहुत सी जगह से मांग आई है।

श्री धूलजी भाई : बांसवाड़ा जिले से किस किस गांव से मांग आई थी ?

श्री रामनिवास मिर्धा : मैं निश्चित तौर से कुछ नहीं कह सकता जहां से मांग आई होगी वहां आयन्दा साल भेजने की हम कोशिश करेंगे।

श्री कंवरलाल जेलिया : क्या सरकार की यह जानकारी में है कि पिछले वर्ष कोटा डिविजन में कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत जो कम्प्रेशर्स भेजे हैं उनके द्वारा पर्याप्त काम नहीं हुआ ? क्या उसको सरकार सन्तोषजनक काम मानती है ?

श्री मिर्धा : यह अलग से सवाल है और विशेष स्थिति के बारे में है।

श्री लाल बहादुर : बारां में कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट में पैसे देकर कम्प्रेशर्स मांगे थे, उसके लिये छः महिने का वादा हुआ किन्तु साल भर होने आया किन्तु अभी तक नहीं भेजे जाने का क्या कारण है ?

श्री मिर्धा : यह कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट का सवाल है। मैं केवल कृषि विभाग के कम्प्रेशर्स का जिक्र कर रहा हूं।

श्री लाल बाहादुर : अब तक वे कम्प्रेशर्स वहां क्यों नहीं पहुंचे ?

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न करने वाले माननीय सदस्यों को यह ध्यान में रखना चाहिये कि मूल प्रश्न क्या है और इसका कितना स्कोप है ? एक ही प्रश्न में सारे दुनियां भर के सवाल होने लगें तो उनके उत्तर किस प्रकार दिये जा सकते हैं ?

श्री कंवर लाल जेलिया : माननीय मंत्री जो फरमा रहे हैं कि कम्प्रेशर्स भेज दिये जायेंगे, तो क्या वे मुफत में भेजे जायेंगे या रेट पर भेजे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२.

सन् १९५३ से १९५५ तक राजस्थान में अपहरण किये गये व्यक्ति

श्री चांदमल मेहता : क्या गृह मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् ५३–५४ और सन् ५४–५५ के वर्ष में कितने कितने व्यक्तियों का राजस्थान में डाकुओं द्वारा अपहरण किया गया ?

(२) उन व्यक्तियों में से पुलिस अधिकारियों द्वारा कितने व्यक्ति छुड़ाये गये और डाकुओं को रुपये देकर कितने व्यक्ति छूट कर आये ?

(३) जो व्यक्ति पुलिस अधिकारियों द्वारा छुड़ाये गये उनके क्या क्या नाम हैं ?

(४) अपहरण किये हुए व्यक्तियों में से किनको डाकुओं ने मार दिया।

(५) ऐसे कौन–कौन व्यक्ति हैं जो अभी तक लापता हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : (गृह मंत्री)

राजस्थान में सन् ५३ में ३७

सन् ५४ में २६

सन् ५५ में २ व्यक्तियों को डाकुओं द्वारा अपहरण किया गया। इनमें से ११ व्यक्ति पुलिस द्वारा छुडाये गये और ४८ स्वयं छूट कर आये हैं। पुलिस द्वारा छुडाये गये व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं :

१. श्रीमती छम्मो
२. श्रीमती हीरकी
३. श्रीमती सोनी
४. श्री मोहीलाल
५. श्री घेवरचन्द
६. श्री हमीरा
७. श्री अली
८. श्री ब्राजा
९. श्री गोविन्द जाट
१०. श्री गोपी किशन
११. श्री मदन लाल

४. झुंझुनू जिले के स्वामी ब्रसोदानन्द तथा भरतपुर जिले का गनपत ब्राह्मण डाकुओं द्वारा मार डाले गये।

५. श्रीमती रहमत, मरियम तथा मोरम यह तीन औरतें अभी तक लापता है।

श्री चांदमल : अपहरण करने वाले कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो अलग प्रश्न है।

श्री खेतसिंह : किडनेप करने वालों का मुख्यतया कोनसा गुट्ट है ?

श्री रामकिशोर व्यास ; अलग अलग ग्रूप्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो पाकिस्तान के ब्रोर्डर पर घूमते हैं, कुछ चम्बल के किनारे और कुछ अरावली की घाटियों में घूमते है।

श्री चांदमल : क्या यह सही है कि अपहरण करने वालों को छुड़ाने में पुलिस काफी असफल रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस नाते तो यह बात सत्य है कि, जिनको छुड़ाया गया उनकी संख्या कम है। इसमें एक कारण यह भी है कि जनता का पूरा सहयोग पुलिस को नहीं मिलता और जितनी सूचना जनता को हमें देनी चाहिये उतनी सूचना भी वे नहीं देते। अब यह सूचना चाहे डाकुओं के डर की वजह से हो या किसी और वजह से वे न देना चाहते हों; पर यह सही है कि सूचना जनता से नहीं मिलती।

श्री चांदमल : आइन्दा ऐसे अपहरण को रोकने के लिए क्या सरकार कोई योजना रखती है ?

श्री गृहमन्त्री—पूरी ताकत लगाकर इन अपहरणों को रोकने का विचार सरकार रखती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या पूरी ताकत ११ व्यक्तियों के छुड़ाने में नहीं लगाई गई ?

श्री गृहमन्त्री—आपने आगे के लिए फरमाया।

श्री चान्दमल मेहता—तो क्या इससे यह समझा जाय कि अब तक पूरा इरादा नहीं था ?

श्री गृहमन्त्री—पहले भी पूरा इरादा था और अब और ज्यादा भारी हो गया।

श्री गुरु दयालसिंह—श्री सूरजमल नागर को कैसे छुड़ाया ?

श्री गृहमन्त्री—उन्हें पुलिस द्वारा नहीं छुड़ाया गया ?

श्री गुरुदयाल सिंह सिन्धु—क्या यह सच है कि कुछ रकम देकर छुड़ाया गया ?

श्री गृहमन्त्री—हमारी जानकारी में यह नहीं है ?

श्री गुरुदयालसिंह सिन्धु—तो क्या फिर आप इसकी जांच करने के लिए तैयार हैं ?

श्री गृहमन्त्री—हमने जांच करनी चाही। मैंने खुद ने भी जानना चाहा, जब कि मैं स्वयं उस क्षेत्र में गया था, पर जानकारी लोग बाग देने को तैयार नहीं हैं और जानकारी नहीं देने का कारण कुछ तो डाकुओं का डर हो सकता है तथा कुछ और कारण भी हो सकता है।

श्री चांदमल मेहता—सरकार के पास ऐसी कौनसी तज़वीज़ है जिससे इन अपहरणों को रोकने की बात सरकार सोच रही है ?

श्री गृहमन्त्री—जिन जिन क्षेत्रों में जिन जिन रास्तों से होकर डाकू आते जाते है वहां वहां ज्यादा निगरानी और ज्यादा पुलिस रखने की योजना सरकार को है।

श्री चांदमल मेहता—वे कौन कौन से रास्ते हैं ?

श्री गृहमन्त्री—वह सदन में बताना जनहित में उचित नहीं होगा।

श्री जवानसिंह—जिन लोगों को छुड़ाया गया उनको छुड़ाने के लिए कितना रुपया दिया गया ?

श्री गृहमन्त्री—मैं समझ नहीं सका आपका प्रश्न।

श्री जवानसिंह—डाकुओं से जिन व्यक्तियों को छुड़ाया गया, उनके लिए कितना रुपया डाकुओं को दिया गया ?

श्री गृहमन्त्री—एक पैसा भी नहीं दिया गया।

श्री जवानसिंह—सरकार ने नहीं दिया या उन आदमियों के सम्बन्धियों ने भी नहीं दिया कि जिनके आदमियों को गिरफ्तार किया गया ?

श्री गृहमन्त्री—आपने पुलिस द्वारा छुड़ाने की बात के लिए पूछा, उसके लिए मैंने निवेदन किया कि एक पैसा भी नहीं दिया।

श्री खेतसिंह—इन जगहों पर क्या वायरलैस सैट्स रखने की कृपा करेंगे आप ?

श्री अध्यक्ष—This is a different question altogether.

श्री वेदपाल त्यागी—कितना रेन्सम दिया गया, डाकुओं के पन्जे से कैदी छुड़ाने के लिए ?

श्री गृहमन्त्री—११ व्यक्तियों को पुलिस ने छुड़ाया। इसमें रेन्सम देने का सवाल पैदा नहीं होता। अब इसके अतिरिक्त जो अपने आप छूट कर आये उनमें किसने क्या दिया, इसकी जानकारी हमें नहीं। क्योंकि जो छूट कर आये उनसे जानकारी करते हैं तो वे बताते नहीं। अब क्यों नहीं बताते वे, इसकी हमारे पास कोई सूचना नहीं।

श्री चांदमल—क्या यह सही है कि पुलिस जनता को कॉन्फीडेन्स में नहीं लेती ?

श्री गृहमन्त्री—बिलकुल सही नहीं।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या पुलिस ने सही जानकारी नहीं देने के कारण किसी को प्रोसीक्यूट भी किया है ?

श्री गृहमन्त्री—यह एक अलग प्रश्न है।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—Questions are over now.

(विराम)

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि राजा श्री मानसिंह ने (वि० सं० ६८) दिनाङ्क २८ फरवरी, ५५ से ४ मार्च, ५५ तक विधान सभा की बैठक से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है। क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?'

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

जन लेखा एवं प्राक्कलन समिति से सदस्यों का त्याग-पत्र

मैं माननीय सदस्यों को पुनः सूचित करता हूँ कि श्री व्रजसुन्दर शर्मा ने जनलेखा समिति से और श्री सम्पतराम ने प्राक्कलन समिति से त्यागपत्र दे दिया है।

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद

अब श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद होगा।

श्री मथुरादास माथुर अपनी स्पीच प्रारम्भ करें, इसके पहले मैं माननीय सदस्यों से यह जानना चाहता हूँ कि मेरे पास २५ नाम तो ट्रेजरी बैंचों की ओर से आये हैं और आठ दूसरी ओर से आये हैं। तो या तो फिर टाइम लिमिट कर दिया जावे या फिर वे माननीय सदस्य स्वयं अपने नाम विदड्रा कर लें जो बोलना नहीं चाहते हैं; या मैं शाम का भी सैशन रक्खूँ और कल फिर बढ़ा दूँ।

श्री हरिदेव जोशी—अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि बजट पर और राजप्रमुख के भाषण पर हमेशा ज्यादा बोलने वाले होते हैं। अगर पहले दिन से ही यह व्यवस्था की जावे कि पीछे बोलने वालों को समय कम मिले और पहले वालों को ज्यादा, तो यह सदन के लिये उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—कल मैंने यही कहा था। कल आप नहीं थे, शुरू से ही। पर सदन की यह मंशा रही कि शुरू में ऐसा नहीं किया जावे

श्री मथुरादास माथुर—जहां तक राज्य-पक्ष के सदस्यों का सम्बन्ध है हमें अगर यह पता हो जावे कि कल सेशन और चलेगा तो इसके लिए तो बात दूसरी है; वरना हम अपने आपको एडजस्ट कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष—नहीं, सदन यदि चाहे कि और समय दिया जावे तो मैं तैयार हूँ इसके लिए। वरना मैं स्वयं अपनी ओर से उत्सुक नहीं हूँ, न उत्सुक हूँ।

श्री हिम्मतसिंह—समय और बढ़ना चाहिये साहब। कल का समय और दें।

श्री वेदपाल त्यागी—लोक सभा में दो दिन दिये जाते हैं।

श्री हिम्मतसिंह—यह राजस्थान है साहब।

श्री वेदपाल त्यागी—बजट पर काफी समय दिया जाता है, यहां सिर्फ ५ दिन दिये गये हैं, कट मोशन्स पर।

श्री अध्यक्ष—बजट की बात नहीं कर रहा हूँ।

श्री वेदपाल त्यागी—इनीशियेटिव अगर वहां से लिया जावे तो हर सूरत में लिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैं भाषणों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो सदन का सेंस लेना चाहता हूँ कि और समय की आवश्यकता हो तो बढ़ाउँ।

श्री मथुरादास माथुर—आज अभी और विचार कर लिया जावे और कल रिप्लाई के लिये समय दिया जावे।

श्री अध्यक्ष—नहीं तो फिर कितने आदमी बोल सकेंगे। अवधि जो है उसका नियन्त्रण होगा कल तो एक घंटा जवाब के लिए रक्खेंगे।

श्री मथुरादास माथुर—कल जो मुख्य मुख्य सदस्य बोल चुके हैं।

श्री गोपीलाल यादव—कल कहां बोल चुके हैं।

श्री मथुरादास माथुर—आप मुख्यों में हैं। मैं नहीं कहता कि आप मुख्यों में नहीं है। (हंसी)

श्री अध्यक्ष—(श्री मथुरादास माथुर से) आप शुरू करिये।

श्री मथुरादास माथुर—माननीय अध्यक्ष, कल श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए मैंने दो मुद्दों पर सदन का ध्यान आकर्षित किया था. एक तो हमारे यहाँ की लॉ एण्ड ऑर्डर की समस्या पर और दूसरा, माननीय जोधपुर से आये हुए साथी ने रूरल वाटर सप्लाई बोर्ड के चेयरमेन के सम्बन्ध में जो सदन के सामने चर्चा की थी उस पर मैंने रोशनी डालने की कोशिश की थी। मैं सदन के सामने उस विषय को चालू रखते हुए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो कल वाटर बोर्ड के विषय में कहा गया था इसके विषय में भी काफी सदन के सदस्यों में भी और बाहर भी भ्रान्ति है। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिन मुद्दों को लेकर जोधपुर से आने वाले साथी ने इस सरकार को पूँजीपतियों के हवाले करने की जो घोषणा की थी और इस तरह की चर्चा की थी, वह कतई निराधार है। मैं सदन के सभी सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि जो वाटर बोर्ड बना है उसमें सभी तरह के लोग हैं। सदन के सदस्य भी हैं, पर्लियामेन्ट के सदस्य भी उसमें हैं, और इसके साथ में वे लोग भी हैं जो

[श्री मथुरादास माथुर]

राजस्थानी हैं और राजस्थान के हर काम में; खास तौर से उन कामों में जिनमें कि जनता पर कष्ट होता है, फेमीन में, फ्लड में काफी हिस्सा लेते हैं और अपना पैसा लाकर खर्च करते हैं, उनका भी सहयोग लिया गया है।

मारवाड़ रिलीफ सोसाइटी के कुछ सदस्यों को जो इसमें रखा गया है उसके माने यह न लगाइये की हमने वाटर बोर्ड या अन्य संस्था को किन्हीं पूंजीपतियों के हवाले कर रखा है। मारवाड़ रिलीफ़ सोसाइटी के सदस्य जब-जब राजस्थान में अकाल पड़ता रहा है तब-तब बराबर अकाल पीड़ितों की सेवा करते रहे हैं, और उन्होंने लाखों रुपये लगाकर जनता की सेवा की है। उन्होंने यह भावना प्रकट की थी हम लोग वाटर बोर्ड में सहयोग देने को तैयार हैं यदि हमारी सेवा ली जाय। वाटर बोर्ड के ज़रिये जो रूपया अब खर्च किया जाता है वही पहले पंचायतों के ज़रिये खर्च किया जाता था, लेकिन पूरे खर्चे का १/३ खर्चा पंचायतों को या जनता को खर्च करना पड़ता था। ऐसे कई इलाके हैं जहां की जनता एक-तिहाई खर्चा नहीं दे सकती थी, इसलिये इन्तज़ाम करने में बड़ा कष्ट होता था, इसलिये वहां पर पानी का कष्ट महसूस करते हुए भी काम नहीं हो पाता था। इसीलिये ऐसे लोगों को इस बोर्ड में लिया गया है, जो पैसा इकट्ठा करके जनता को सहयोग देंगे। जहां की जनता पैसा नहीं दे सकती उनको भी वे सहयोग देंगे और जो रेकरिंग एक्सपेन्डिचर होगा उसका भार सरकार पर या जनता पर नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि वे फैसला करेंगे कि किस-किस गांव में कूँआ या नाड़ी बननी चाहिये, बल्कि ज़िलों के कलेक्टरों के मातहत समितियें बनाई गई हैं जिनमें कर्मठ कार्य-कर्ता भी लिये गये हैं। जो भ्रम फैलाया जा रहा है वह राजनैतिक कारणों से है, यह तो समझ में आ सकता है; लेकिन फेक्ट्स और मुद्दों के आधार पर यह भ्रम बिल्कुल गलत है। इसके साथ-साथ मैं यह भी अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो सेन्ट्रल डेवलपमेन्ट बोर्ड बना है, उसमें भी ऐसे लोग रखे गये हैं जो इस काम में दिलचस्पी रखते हैं।

इसके बाद एक और चीज़ के बारे में मैं अर्ज़ करूंगा जिस पर जोधपुर से आने वाले साथी ने बड़े ज़ोर से प्रकाश डालने की कोशिश की और उन्होंने यह बात रखी कि लॉ एन्ड ऑर्डर बिगड़ रहा है। इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस ओर बैठनेवाले एक मिनिस्टर साहब डाकुओं की इमदाद करते हैं और उन्होंने (क्रान्तिदूत) नामक अख़बार में छपी एक चिट्ठी की ओर इशारा किया। दूसरे सदस्यों ने भी इस ओर इशारा किया और सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब-जब सदन में या पार्टी के चुनाव होने का मौका आता है, तब तक इस प्रकार के अखबार निकलते हैं; यह कोई पहला ही मौका नहीं है, जबकि इस तरह की चीज़ आई हो। जब-जब ऐसा मौका आता है तब-तब ऐसे व्यक्ति सामने आते हैं और अख़बारों में इस तरह की झूठी खबरें निकालते हैं। यह नीचे

श्री वेदपाल त्यागी—अख़बार में पत्र का जो फोटो छपा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर—मैं उस पर भी आ रहा हूं आप संतोष रखिये। मैंने उसको पढ़ा है।

[श्री मथुरादास माथुर]

छपने से पहले ही उधर के कुछ लोग इसको जानते हों तो ताज्जुब नहीं ? यह कैसे हुआ है यह मैं जानता हूं और उधर के साथी भी जानते हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—आपको इसका इल्म पहले से होगा।

श्री मथुरादास माथुर— मुझे मालूम है कि कौन-कौन इसकी तह में हैं और इसलिये लोग ज़ोर से बोल रहे हैं। वे लोग अपनी तस्वीर शीशे में देखेंगे तो उनको पता चलेगा। जो फोटो उस अख़बार के पहले पेज पर छपा हैं वह बिल्कुल झूंठा है। एक टाइप की हुई चिट्ठी की फोटो ली गई है और फिर मिनिस्टर सहाब के दस्तख़तों की अलग फोटो ली गई और फोटो ट्रिक से दोनों फोटों को मिला कर पत्र में छपी चिट्ठी की फोटो लेली गई(good, good की सदन में आवाज़)। यह कैसे हुआ यह आपको मालूम हो जायगा। जिस आदमी को यह चिट्ठी लिखी गई बतलाते हैं उसके पास यह चिट्ठी नहीं पहुंची।

श्री वेदपाल त्यागी—उनके पास पहुंचती तो फोटो कैसे छपता ?

श्री मथुरादास माथुर—आपको चिट्ठी हासिल कैसे हुई, जब कि न तो चिट्ठी लिखी ही गई और न जिसके नाम पर लिखी गई बताते हैं वह कहते हैं कि मेरे पास ऐसी कोई चिट्ठी नहीं आई, और मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैंने ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी। इस प्रकार की चिट्ठी चुनाव के मौके पर छपना मक़सद से खाली नही है। (क्रान्तिदूत) अख़बार हमेशा से ऐसा करता रहा है। वह अख़बार आज निकला है और ४ महिने तक फिर नहीं निकलेगा। फिर कोई बात आयेगी तब फिर यह निकल जायगा। इसे निकालने वाले लोग कोई हौसले के आदमी नहीं हैं, वे कोइ स्टेटस के आदमी नहीं है। यदि इस तरह की कोई चीज़ थी तो उनको चाहिए था कि वे मिनिस्टर साहब से पूछते कि इस तरह की कोई चीज़ हमारे नोटिस में आई है, आप इसकी सफाई दीजिए और फिर अगर सफाई नहीं मिलती तो प्रचार करते। अख़बार निकालने वाले को नोटिस दिया गया है। उस पर शीघ्र ही मुकद्दमा चलाया जायगा। इस तरह के लोग कभी किसी के खिलाफ पर्चा निकाल देते हैं, तो कभी किसी के खिलाफ यह डेमोक्रेसी का नया प्रयोग है। इसमें समय लगेगा, लोगों को समझने में कि किस तरह से काम करना चाहिए और अख़बार वालों को किस तरह से जिम्मेदार होना चाहिए। फिलहाल ये मौका देखते है कि कब किस मिनिस्टर के खिलाफ कुछ लिखा जाय, कब किस तरह के पर्चे निकाले जांय। कभी ऐसा होता कि इस तरह के अख़बार निकालने वालों की हेड लाइन ही गायब होती है और कभी दूसरे आदमी और अन्य आदमी के नाम से झूंठी खबरें निकाल दिया करते हैं। इस अख़बार को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई दूसरी खबर ही नहीं हैं, सिवाय एक ही तरह की खबर के। इससे साफ जाहिर होता हैं कि सिर्फ इस काम के लिए ही यह अख़बार निकाला गया हैं। यह हम खूब समझते हैं कि राजनैतिक मुद्दों को लेकर; कुछ कारणों को लेकर; इस तरह के अख़बार निकाले जाते हैं। सदन का अधिवेशन प्रारम्भ होने से २ दिन पहले यह अख़बार निकलता हैं और उसका उपयोग कुछ लोग राजनैतिक ढंग से करते हैं। इस तरह की चीज़ प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के आधार पर किस तरह से हैं यह मैं

[श्री मथुरादास माथुर]
नहीं समझ सका। हमारे त्यागी जी प्रजातन्त्र की दुहाई बात-बात में देते हैं। इस तरह की चीज़ कहां तक डेमोक्रेसी को पनपाने वाली है, यह वे ही बता सकते हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—This is a serious charge against a Minister and this sort of statement and advocacy would not do.

श्री मथुरादास माथुर—It is a charge against those people who are responsible for creating such situations. It is unfortunate, that those people who are behind these things will not come forward: they only come in the House and show warth

श्री अध्यक्ष—We are discussing Rajpramukh's Address.

श्री मथुरादास माथुर—We are discussing Rajpramukh's Address, but objection has been teken in your absence and that objection has not been cared for. Anything which has come in a paper and has a bearing on the question of law and order, it was my duty to reply, otherwise it goes without reply.

श्री मथुरादास माथुर—मैं सदन का ज्यादा समय इस बारे में नहीं लेना चाहता क्योंकि किसी व्यक्ति ने गलती की है तो कानून से उसको सज़ा मिलेगी। राजनैतिक चाल से यह बात की गई है तो उससे हम निपटेंगे। यह मैं बता देना चाहता हूं कि जो बात छपी है वह फ़र्ज़ी है, झूंठी है और बनाई गई है,और राजनैतिक कारणों से बनाई गई है। इस अख़बार की जितनी भी कॉपियें आज तक निकली हैं उन सबको आप देखते तो आपको पता चलेगा कि किसी न किसी को बदनाम करने के लिए ही यह अख़बार निकलता है। इस पर मुकद्दमा चलेगा और उसका जो फैसला होगा वह आपके सामने आयेगा। समाचार मिला है कि उसके खिलाफ़ मुकद्दमा आज ही दायर हो जायगा। यह ऐसा मुद्दा नहीं था जिस पर कि आज मौके पर चर्चा की जाती, लेकिन कल जोधपुर से आने वाले साथी और त्यागीजी ने अपना दिमाग इस ओर दिया था, इसलिए जवाब देना मेरा फर्ज हो गया था।

एक बात और कहना चाहता हूं। विरोधी दल के उपनेता ने कल कुछ बातें कहीं थी। विरोधी दल के होने के कारण तो वे यही कहते कि श्रीमन् राजप्रमुख को उनके अभिभाषण के लिये धन्यवाद नहीं देना चाहिए, लेकिन दिल और दिमाग़ से तो उन्होंने भाषण की तारीफ़ ही की है।

श्री हिम्मतसिंह—आप में क्या यह खास बात है कि आप दूसरों के दिल और दिमाग की बात समझते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर—समझना पड़ता है। उनके भाषण मे ऐसी कोई बात नहीं थी सिवाय इसके कि सेटलमेंन्ट के पटवारी और जंज़ीर खींचने वाले ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। हो

[श्री मथुरादास माथुर]

सकता है कि यह एक बड़ा महकमा है किसी इलाके में स्केल टेढ़ी-मेढ़ी खींची गई होगी। यह कोई ऐसी बात नहीं हैं कि जिसके कारण राजप्रमुख महोदय को धन्यवाद नहीं दिया जाय। आपको रेवेन्यु का एक्सपीरियेन्स है, आप रेवेन्यु के माहिर हैं, इसलिये छोटे मोटे नुक्स निकाल सकते हैं। क़ानून में अपील की गुंजायश रखी गई है और इसकी कई अपीलें होती भी है और मन्जूर भी होती हैं। और कई खारिज़ भी होती हैं। इसके लिये राजप्रमुख महोदय को धन्यवाद नहीं दिया जाय, यह कहां तक वाजिब है?

श्री हिम्मत सिंह—बड़े नुक्स तो फिर निकाले जायेंगे।

श्री मथुरादास माथुर—होंगे तो निकाले जायेंगे और उनका जवाब भी दिया जायगा। आपकी नजर छोटी-छोटी बातों पर ही गई हैं। जंजीर टेढ़ी खिंच गई, या किसी पटवारी ने किसी से ५)रु० ले लिये, इन बातों पर आपकी नजर गई है, किन्तु इन बातों को भी हम रोकेंगे। अगर कोई पटवारी आपका मर्जिदान है तो हम उसको भी ऐसा करने से रोकेंगे। राजप्रमुख महोदय का भाषण नीति पर होता है। भाषण में उन्होने बताया कि सैटलमेन्ट के बारे में सरकार की नीति इस प्रकार की है, इतना काम कर चुके है, और इतना और कर लेंगे, और शीघ्र ही सब एरिया सैटल हो जायगा। इसमें अगर कोई कमी है तो बतलाईये इसमें कोई कमी नहीं बतलाई गई, इसलिये हम समझते हैं कि सेटलमेन्ट के बारे में सरकार की नीति को सदन मंजूर करता हैं। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पहले मेरे मित्रों ने कुछ बात चलाई थी, इसलिये मैंने उनको जबाब पहले दे दिया है।

कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के बारे में भी चर्चा की गई थी। के. सी. डे. हैं या उनका पूरा नाम क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन डे साहब जो कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के डाइरेक्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उन्होंने भी इस केन्द्र के बारे में यह राय जाहिर की है की हिन्दुस्थान में जितने भी कॉम्युनिटि प्रोजेक्ट ब्लॉक्स हैं उनमें से हमारे यहाँ का ब्लॉक वन ऑफ दि बेस्ट ब्लॉक्स (सर्वोत्तम खण्ड) कहलाने लायक है। इसलिये आपको इसके बारे में कोई शिकायत नहीं हो सकती। मुझे शिकायत हो सकती है या और लोगों को शिकायत हो सकती है, जिनके यहां कॉम्युनिटि प्रोजेक्ट का काम धीरे हुआ है लेकिन आपके द्वारा यह कहना ठीक नहीं है। किसी पुराने पटवारी के कहने से ही आपने ये विचार रखे हैं, आप खुद इन विचारों तक नहीं पहुंचे हैं।

आपने जो एन. सी. सी. मूवमेंट और आग्ज़ीलियरी फोर्स (Auxiliary Force) के बारे में गाँधीजी के नाम पर कहा कि गाँधीजी के ऐसे विचार नहीं थे। मैं आप से निवेदन करूंगा कि ऐसे मामलों में गाँधीजी का नाम न लें तो अच्छा हो। स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों को फौजी ट्रेनिंग देना, उन्हें फिज़िकली फिट बनाना और डिसिप्लिन सिखाना, क्या बुरी चीज है? अगर बच्चों को इस तरह कि ट्रेनिंग दी जाती है तो आप गाँधीजी का नाम लेकर इसे रुकवाइयेगा नहीं? प्रजातंत्र को मज़बूत करने के लिये हमारे नौजवानों में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी हैं। कॉलेजों और स्कूलों में एन. सी. सी. काफी तरक्की पर है और इससे डिसिप्लिन इंप्रूव हुआ है, और यह अच्छी बात है कि विद्यार्थी इसमें काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। इस बारे में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा।

[श्री मथुरादास माथुर]

सर्विसेज़ के बारे में भी कुछ चर्चा की गई थी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कुछ व्यक्ति आ पाते हैं और कुछ नहीं आ पाते। जो नहीं आ पाते उनको असंतोष होता ही है और इस वजह से वे अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते, यह आपका कहना है। इसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि कुछ लोग एम. एल. ए. हो जाते हैं और कुछ रह जाते हैं। जो कम्पीटिशन में आते हैं उनको फायदा मिलता है और जो नहीं आते हैं उनको फायदा नहीं मिलता है। रिक्रूटमेन्ट के जो रूल्स बने हुए हैं उनके अनुसार इन्टरव्यू होता है। इन्टरव्यू करने के लिये बाहर से लोग आते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाले उनको सिलेक्ट करते हैं। जो रूल्स और सिद्धान्त बने हुए हैं उनको मानना पड़ेगा इसलिए इस बारे में कुछ कहना बेकार था और सर्विसेज़ गेलेरी के लोगों को ब्लेम करने का मकसद था। इत्तफाक से उस समय उसमें कोई भी बैठे हुए नहीं थे इसलिए उनकी यह बात भी निराधार ही रही। यह बात कहना कि कांग्रेस की तरफ से सर्विसेज़ में इंटरफियरेन्स की जाती है, ठीक नहीं, किसी डिस्ट्रिक्ट या तहसील कांग्रेस कमेटी के प्रेज़ीडेन्ट की नजीर दी गई। जब कभी कोई गैर कानूनी काम करते हुए नज़र आते हैं तो लोग लिख ही देते हैं; करना न करना अफसरों की मर्जी की बात है, सही सुझाव देना तो उनका फर्ज है। अपने पास भी कई लोग आते हैं और मिनिस्टरों के पास भी कई लोग सुझाव लेकर आते हैं, करना न करना उनकी मर्जी की बात है।

श्री वेदपाल त्यागी—Perhaps the Hon'ble Member does not know that a writ of the High Court does not carry so much value as a letter from a Congraessman to the services.

श्री मथुरादास माथुर—Right, I agree. मैं मानता हूं कि हाईकोर्ट ने कह दिया होगा कि यह लेटर कोई वकत नहीं रखता। हम भी कहते हैं कि यदि कोई बाहर का आदमी चिट्ठी लिख दे तो वह कानूनी दृष्टि से बेकार है? It is only an advice to him. इसका मतलब यह नहीं है कि किसी ने चिट्ठी लिखदी है तो वह अफसर चिट्ठी लिखने वाले का हुक्म माने ही, लेकिन यह कहना कि किसी को चिट्ठी लिखने का अधिकार ही नहीं है, यह मैं नहीं मानता। हिन्दुस्तान के हर एक सीटीज़न को चिट्ठी लिखने का अधिकार है। उसको माने न माने यह अफसर के अधिकार की बात है। उस अफसर ने चिट्ठी को मान लिया, यह उसकी मर्जी थी। उसने राय ठीक समझी होगी, इसलिए सम्भवतः मान लिया। हाई कोर्ट ने उसको ठीक नहीं समझा होगा। हाईकोर्ट हजारों केसेज़ पलट देता है, यह कोई बुरी बात नहीं है। किसी कांग्रेसमेन ने जनता का काम किया है तो सोच समझ कर उसकी राय में ठीक होगा तभी किया होगा। त्यागीजी खुद समझदार हैं। उनके सामने भी कई चिट्ठियें आई होंगी जब कि वे मिनिस्टर थे। उन्होंने भी किसी की राय मानी होगी। सही या ग़लत भी मानी होगी। यह कहना कि चिट्ठी लिखने का अधिकार नहीं है, सही नहीं है, हरेक नागरिक को अधिकार है लिखने का और बात करने का। माने न माने यह सामने वाले के अधिकार की बात है। राजनैतिक कारणों से यह कहना है कि कांग्रेसमेन बेजा असर डालते है, ठीक नहीं है। यदि कोई कांग्रेसमेन सरकारी अफसरों से मिलते हैं तो कोई बेज़ा बात नहीं है। सरकारी

[श्री मथुरादास माथुर]

अफसर ही जनता का काम करने की एजेन्सी है, इसलिए उनको जनता के काम के लिए मिलना ही पड़ता है ? लॉ एण्ड ऑर्डर के नाम पर किसी के साथी को पीट दिया तो बड़ा दर्द हुआ; जोधपुर से आने वाले कॉम्युनिस्ट पार्टी के साथी को। यदि कानून की अवहेलना की है तो मुकद्दमा दायर होगा। यदि मुकद्दमा दायर करते हैं तो लॉ एण्ड ऑर्डर को बदनाम करते हैं और यदि दायर नहीं करते हैं तो भी लॉ एण्ड ऑर्डर को बदनाम करते हैं। राजप्रमुख के भाषण में मुद्दों पर ही चर्चा होनी चाहिए। डाकुओं को सरेन्डर करवाने की नीति सही है या गलत, इस पर चर्चा होनी चाहिए। नीति से सम्बन्धित चीज़ों पर चर्चा होती तो हम समझ सकते थे। छोटी-छोटी बातों में नुक्स निकालने से कोई मतलब हल नहीं होता। राजप्रमुख महोदय के अभिभाषण को यदि आप शुरू से आखिर तक पढ़ने की कोशिश करें तो उसमें सब फेक्ट्स दिये हैं।

एक साथी ने कल कहा था कि भाखरा और चम्बल से हमारे यहां नहरों द्वारा पानी आयेगा, इतने एकड़ ज़मीन हरीभरी हो जायगी। जोधपुर से आने वाले साथी ने कहा कि ये सब सब्ज़ बाग़ है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह सब्ज़ बाग़ कैसे हैं। पानी आ रहा है इतने बड़े एरिया में, खेती हो चुकी है। दुनियां के किसी भी देश की हिस्ट्री में आप यह बात नहीं बता सकते कि एक ही दिन में सब काम हो गया हो। राजप्रमुख महोदय कहते हैं कि इस तरह की हमारी पॉलिसी है। बड़े बड़े काम चल रहे हैं, बांध बंध रहे हैं, ५-७ साल में काम खत्म होता है। यह नहीं हो सकता कि अभी बटन दबाया और अभी रोशनी हो गई, या इतनी ज़मीन में सिंचाई हो गई। हर काम में समय लगता ही है। यह कहना कि धन्यवाद नहीं दिया जाय इसका अर्थ मैं नहीं समझ सका।

इसलिये मैं, माननीय अध्यक्ष, सदन के सदस्यों से यह अर्ज करूंगा कि जो कुछ भी श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में फरमाया है उन्होंने उससे सरकार की नीति पर प्रकाश डाला है। इससे इस बात का पूरा सबूत है कि जो बातें पूरी नहीं कर सके हैं उन्हें हम अब कर रहे हैं। २००० मकान बनाने की स्कीम है जो अगर गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के पास भेजदी गई है तो इसके लिए तो धन्यवाद दीजिये। श्रीमन् राजप्रमुख ने गत वर्ष अगर इसके लिए धन्यवाद मांगा होता तो आप कह सकते थे कि स्कीम भेजी ही नहीं है धन्यवाद किस बात का दें। पर अब जो एक काम हुआ है, एक काम कर दिया है तो उसके लिये धन्यवाद नहीं दें। यह तो हम, मैं समझता हूं ठीक काम नहीं करेंगे।

अन्त में मैं श्री गुलाबचन्दजी कासलीवाल ने जो श्रीमन् राजप्रमुख को धन्यवाद देने का प्रस्तव रक्खा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैं इस प्रस्ताव पर अपना संशोधन हाउस के समक्ष पेश करना चाहता हूं। इसको पेश करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात की हमें खुशी है कि श्रीमन् राजप्रमुख ने हिन्दी में भाषण दिया, परन्तु उनको जो धन्यवाद दिया जा रहा है वह

Page No.24

[श्री मथुरादास माथुर]
प्रस्ताव अंग्रेज़ी में है। वह प्रस्ताव भी हिन्दी में रखा जाता तो अच्छा होता। मैं अब भी हाउस के नेता से कहूंगा कि इसको पास करने से पहले हिन्दी में कर लें।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—हाउस के नेता ने वह प्रस्ताव नहीं रखा है।

श्री गोपीलाल यादव—तो मेरा इसमें संशोधन का प्रस्ताव है। असली प्रस्ताव इस प्रकार है :

"That the Members of the Assembly assembled in thised sessoion are deeply grateful to His Highness the Rajpramukh for the Address which he has been pleased to deliver to the House."

मैं इस प्रस्ताव के आगे कुछ थोड़े से शब्द एड करना चाहता हूं।

"But regret that the Address does not give any hope to the Kisans that their economic exploitation is going to end."

माननीय अध्यक्ष, श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण पर बहुत चर्चा हो रही है और वह चर्चा इस किस्म की बन गई है कि जो चीज़ बजट पर बहस के सिलसिले में आनी चाहिए तथा और जगह आनी चाहिए वह भी यहीं आ रही हैं। इसलिये इस पर बहस इतनी लम्बी हो रही है कि शायद दो दिन में पूरी न हो सके। तो ऐसी सूरत में मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजप्रमुख के भाषण पर उसी चीज़ पर बोलें, जो इससे सम्बन्ध रखने वाली हैं। जो बातें बजट के समय कही जाने वाली है उनको बजट पर बहस के दौरान में कहा जाय, इस समय नहीं कहा जाय। अगर बजट पर बहस के सिलसिले में कही जाने की बातें हैं तो उनको बजट पर बहस के समय ही कहा जाय। बजट पर बहस के लिये ५ से लेकर १५ दिन का समय दिया जा सकता है। हमारे यहां ५ दिन रखे गये हैं अगर और समय की आवश्यकता होगी तो अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करेंगे कि बजट पर बहस का समय बढ़ा दें, और अध्यक्ष महोदय अवश्य उस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे।

दूसरी चीज़ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इधर बैठने वाला कोई भी एक वक्ता बोलता है तो उधर बैठे हुए हर एक वक्ता जवाब दें तो इस तरह से तो बहस बहुत लम्बी हो जायगी। जवाब देने का काम तो हाउस के नेता और प्रस्तावक महोदय का ही रखें। दूसरे सब कुछ उन्हें राजप्रमुख के भाषण के सम्बन्ध में कहना है वहीं बोलें।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजप्रमुख के भाषण में हर साल हम यह देखते हैं कि कुछ न कुछ बातें कहीं जाती हैं और वे (श्रीमन् राजप्रमुख) वही बातें कहते हैं जिनमें शासन की और गवर्नमेंट की प्रशंसा होती है। यह पद्धति इस प्रकार की है कि मैं चाहूंगा कि इसमें कुछ तब्दीली हो। राजप्रमुख का भाषण ऐसा हो कि जिससे पिक्चर सरकार का हाउस के सामने रहे। इस भाषण में जहां सरकार अपनी सफलताओं का वर्णन करे वहां अपनी त्रुटियों, गलतियों, का भी एडमिशन बगैर किसी संकोच के हाउस के सामने करे और जब तक यह पद्धति चालू नहीं हो तो तब तक

[श्री गोपीलाल यादव]

राजप्रमुख का भाषण हमारे लिये कोई कामयाबी का भाषण नहीं होता, तब तक यह भाषण कोई माने नहीं रखता।

हाउस के नेता से मैं, इसलिये, प्रार्थना करूंगा कि भविष्य में इस बात को ध्यान में रखें कि राजप्रमुख का भाषण ऐसा भाषण हो जिसमें गवर्नमेंट जहां अपनी सफलताओं, कामयाबियों और अच्छाइयों को हाउस के सामने रखे वहां साथ ही साथ अपनी भूलों, गलतियों और कमजोरियों को भी हाउस के सामने रखे ताकि जनता सरकार की सफलताओं के साथ साथ खामियों और गलतियों को भी समझ सके।

इसके बाद मैं इस भाषण की दो-चार बातों के बारे में दो-चार शब्द कहूंगा। सबसे पहला मामला लॉ एण्ड आर्डर का है। लॉ एण्ड आर्डर में सुधार हो रहा है, मैं भी यह कहता हूं कि निश्चित सुधार हो रहा है। पर चीज यह है कि हमारे सामने इस बात के आने से कोई माने नहीं निकलते कि जुर्मों में इतने पर्सेंट कमी हुई है। हमारे सामने यह चीज आये कि ये चोरी-डाके बिल्कुल बन्द हो जायेंगे, बिल्कुल खत्म हो जायेंगे। यह तभी हो सकता है जब कि गवर्नमेन्ट इस चीज पर ध्यान दे कि ये चोरी-डाके हो क्यों रहे हैं, फिर यह बीमारी समझ में आ जाय तो इसका इलाज करें। अगर पिछले साल १००० डाके पड़े, इस साल ६०० ही रह गये और अगले साल ८०० रह जांय और उनमें १६० असेम्बली के मेम्बरों के घरों का भी नम्बर आ जाय तो जब तक चोरी-जारी है तब तक इसमें १० परसेंट की कमी माने नहीं रखती और फिर हमें यह भी देखना है कि यह कमी वास्तविक भी है या नहीं।

मैं यह कहने को तैयार नहीं कि गवर्नमेन्ट गलत फिगर हमारे सामने रखती है, या हमें धोखा देती है। संभव है कि सैकड़ों चोरियां ऐसी होती हैं जो पुलिस में रजिस्टर ही नहीं होती। पुलिस में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो पुलिस वाले देखते हैं कि गत वर्ष से दस पर्सेंट कम चोरियों का नम्बर रहा तो हमारी तरक्की होगी, हमारा काम दीखेगा और हमें इनाम मिलेगा। इस लिहाज से भी १०-२० पर्सेंट जो वे दर्ज करते थे वे यदि दर्ज नहीं करें तो कमी हो सकती है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इसकी सफलता इस चीज में देखी जाय कि वास्तव में हम इस बीमारी का डाइग्नोसिस (dignosis) करें और सदन के सामने, जनता के सामने यह रखें कि हम इसे निश्चित रूप से समाप्त करने जा रहे हैं।

अब मैं अपने मुख्य संशोधन की तरफ आता हूं जो मैंने इस प्रस्ताव में रखा है। इस भाषण में यह कहीं नहीं बताया गया है कि इकोनोमिक एक्सप्लोइटेशन, आर्थिक शोषण बन्द होने जा रहा है। माननीय अध्यक्ष, इस साल के अन्दर चीजों के भाव इस कदर गिरे हैं कि किसान आज त्राहि-त्राहि कर रहा है, उसके पास खाने व पहनने को सामान नहीं रहा है, लगान देने के बाद अब वह बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। जो रेंट रेट्स इस हिसाब पर मुकर्रर की गई थीं जब कि बाजरा ५ सेर का बिकता था और अब आज बाजरा १० से १५ सेर के बिकने की हालत में भी वही रेंट रेट्स कैसे दे सकते है। जिस वक्त रेंट रेट्स मुकर्रर की गई थीं तो इसका बेसिस रखा गया था पैदावार का १/६ हिस्सा, यह

[श्री गोपीलाल यादव]

बेसिस ही गलत था। इसे बेसिस बना कर किसानों से लगान लेते हैं तो निश्चित समझिये कि राजस्थान का किसान भूखों मरेगा। राजस्थान के बहुत से इलाके तो ऐसे हैं कि उधर बैठे हुए सैकड़ों मेरे मित्र मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि किसानों से लगान लेना तो दूर रहा किसानों को सब्सीडी कुछ मिलना चाहिये, इस लिहाज से कि वे काश्त कर सकें। पैदावार का १/६ हिस्सा लें इस बेसिस में गड़बड़ है। क्योंकि जागीरदार पैदावार का हिस्सा लेते थे, किसान के अगर पैदावार नहीं हुई तो उसे कुछ नहीं देना पड़ता था और अगर काश्तकार के पैदावार कुछ ज्यादा हुई तो जागीरदार को कुछ ज्यादा मिल गया। किसान खेती के समय में बहुत सा सामान काटते थे तो ले जाते थे पर अब पैदावार के आंकड़े लेकर १/६ मुकर्रर कर दिया है। रेमिशन गवर्नमेन्ट का होता है, थोड़े इलाके में होता है, सब में नहीं होता।

यह प्रसन्नता की बात है कि गवर्नमेंन्ट ने एक ऑर्डीनेंस राजप्रमुख द्वारा निकलवाया है जिसमें रेंट रेट्स कम करने के अधिकार सरकार को दिये गये हैं। वह एक जगह ही नहीं बल्कि सभी जगह के लिए काम में लिया जाय, यह मैं निवेदन करूंगा और हमारे यहां एक बेसिस लगान का कायम किया जाय जो हमारे पड़ोस की जमीन है उसको देख कर उसकी पैदावार और हमारे यहां की पैदावार को ध्यान में रखते हुए किया जाय। हमारे पड़ोसी राज्य यू. पी. और पंजाब हैं, तो पंजाब और यू. पी. में जो लगान की रेट्स है उनसे आधी रेंट रेट्स हमारे यहां लगें.........

क्योंकि वहां पैदावार अच्छी होती है। माली हालत वहां की अच्छी है, पानी अच्छा है। इसलिये हमारे यहां एक सिद्धान्त बना कर रेट ली जानी चाहिये कि पंजाब और यू० पी० में जो रेटस् हैं उनका आधा लेंगे तो निश्चित आप राजस्थान के किसानों के एक्सप्लोइटेशन को बन्द करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो राजस्थान का किसान जो गरीब और भूखा है बरबाद हो जावेगा और जब किसान बरबाद हो जावेगा तो हम भी यहां पर आराम से नही बैठ सकेंगे। अगर किसान बरबाद होता है तो हमारा देश बरबाद होता है। अगर आप किसानों की मीटिंग में जावें और देखें, जो (मिटिंग) अमूमन हुआ करती हैं, तो आपको एक अजीब दृश्य नजर आवेगा और उसको देख कर आप वहां पर खड़े नहीं रहेंगे, आपको शर्म आवेगी। वे लोग यह देखते हैं कि यह दूसरी कौम का आदमी जो अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छे जूते पहने हुए कौन है जो चार पाई पर भी नहीं बैठ सकता। उसके ऐसा सोचने का कारण यह है कि उनके पास साफ कपड़े पहनने को नहीं है, उसके जूते अच्छे नहीं। वे यह समझते हैं कि उनके घर में बैठने को चारपाई तक नहीं और उनकी फाइनेन्शियल पोजीशन भी अच्छी नहीं है। जब तक हम उन किसानों की हालत दूसरे लोगों जैसी नहीं बना देंगे तब तक किसानों का विकास नहीं होगा। मुझे दुःख है कि श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है। हमको यह चाहिये कि हम किसानों की हालत को शहरी लोगों की हालत पर लावें। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान इन्कम टैक्स की ओर दिलाना चाहता हूँ। सेन्ट्रल गवर्नमेंट हम सब से इन्कम टैक्स लेती है। उसकी दर क्या है, वह ३ और ४ पाई है। उस पर भी ३६०० रुपये की आमदनी पर एक पैसा भी नहीं लिया जाता। जब नॉन एग्रीकल्चरल इन्कम पर ३६०० रुपयों पर एक पैसा भी टेक्स का नहीं लिया जाता तो फिर किसान के पास आपको कम से कम १००० रुपये तो छोड़ने चाहिये और

[श्री गोपीलाल यादव]

अगर आप उस पर इन्कम टैक्स की तरह छोड़ देते है तो एक बीघा पर आप उनसे दो-चार पैसे से ज्यादा नहीं ले सकते । इसके लिये आप यह कहेंगे कि अर्थ की कमी को किस तरह से पूरा किया जावे ? इसके लिये मैं यह अर्ज करूंगा कि इस सम्बन्ध में मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा और बजट के समय बताऊँगा । इस वक्त तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि किसानों की हालत बहुत खराब है और उसको सुधारने के लिये जो प्रयत्न करने चाहिये वे नहीं किये जा रहे हैं ।

श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में शिक्षा पर ३ करोड़ रुपया जो खर्च किया उसका जिक्र किया है लेकिन उसमें यह नहीं कहा गया कि १० साल में शिक्षा कम्पलसरी हो जानी चाहिये । इसका यहां पर जिक्र नहीं है । अगर इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट सारे राजस्थान में एक्शन नहीं ले सकती तो कम से कम एक्सटेन्शन ब्लॉक्स जो बनाये हैं उसके साथ तो इसको जोड़ देती । उसमें यह बताया गया है कि अब तक लगभग राज्य का पांचवां भाग इस योजना में शामिल हो गया है और कुछ ही समय में अगली पंचवर्षीय योजना में सारा राजस्थान विस्तार सेवा योजना में आ जावेगा । इसलिये जिस तरह आपके सर्विस एक्सटेन्शन ब्लॉक्स चल रहे हैं तो उसके पेरेलल कम्पलसरी एजूकेशन का काम भी शुरू हो जाए कि हम एजूकेशन कम्पलसरी कर देंगे और फ्री कर देंगे, तो कितना अच्छा हो ।

मैं आपका ध्यान काश्मीर की ओर दिलाना चाहता हूँ । वहां पर मैट्रिक और इन्टर तक एजूकेशन फ्री है । जब वहां पर एजूकेशन फ्री है तो क्या हम हमारे यहां मेट्रिक तक भी एजूकेशन फ्री नहीं कर सकते ? इससे सरकार को थोड़ी आमदनी होती, मगर इससे किसानों को कितनी तकलीफ होती है । अगर आप एक किसान के लड़के से ८ आने लेते हैं तो उससे किसान की क्या हालत होती है ? उसको आप तभी समझ सकते हैं जब आप उस किसान के मकान पर जा कर देखें, उसके घर में आप जाकर रहें । किसान को ४-४ आने इकट्ठे करने में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है । इसलिये मैं यह कहूँगा कि किसान के एक्सप्लोइटेशन को रोका जावे और सबसे पहला काम यह होना भी चाहिये । इसका श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में कुछ भी जिक्र नहीं है जो होना चाहिये ।

एक चीज मैं और अर्ज करना चाहता हूँ और वह पंचायत और म्युनिसिपेल्टीज़ के बारे में है । मैं यह निवेदन करूँगा कि पंचायतों के चुनाव अभी हुए और हो रहे हैं उनमें जो गड़बड़ियां हुईं उन्हें मैं और दूसरे व्यक्ति भी अच्छी निगाह से नहीं देखते । उसका कारण यह है कि हमने ऐसे नियम नहीं बनाये कि कम से कम पंचायत के वोटर्स का एक रजिस्टर हो । चाहे आप हाथ उठवाएं या वोट लें, मगर कम से कम ऐसा तो होना चाहिये कि वोटर्स का रजिस्टर हो जिसमें वोटर्स के नाम दर्ज हों ताकि यह तो पता चल सके कि इतने आदमी वोट डालेंगे । इस चुनाव का नतीजा यह हुआ कि दूसरे गांव के लोग आकर वहां वोट देने के लिये बैठ गये । रिटर्निंग ऑफिसरने २५ साल के वोटरों को निकाल दिया और १८ साल के वोटरों को ले लिया । यह रिटर्निंग ऑफिसर की मर्जी पर रहा कि वह चाहे तो मिनिस्टरों को बदनाम कर दे या मिनिस्टरों की तारीफ करा दे । अखबारों में खबरें छपीं कि मिनिस्टरों ने कौम्युनेलिज्म को प्रोत्साहन दिया और पक्षपात किया । मैं समझता हूँ कि ये दोनों चीजें गलत हैं । न मिनिस्टरों ने किसी का पक्ष लिया और न कौम्युनेलिज्म को प्रोत्साहन दिया गया । मगर जो भी रिटर्निंग ऑफिसर आये उन्होंने भयंकर गल्तियें की हैं, जिससे गवर्नमेंट की बदनामी और मिनिस्टरों

[श्री गोपीलाल यादव]

की बदनामी हुई। उनके पास कोई रजिस्टर नहीं होने से दूसरे ५ गांव के लोग आ गये और ५ गांवों की औरतों को परदा डाल कर लोग ले आए। उनके नाम तो उनके पास थे नहीं। २०० औरतें दूसरे गांव से आ गई और आ कर वोट डाल दिये गये। इससे यह सब गड़बड़ हुई। इसलिये जब तक आप वोटर्स लिस्ट नहीं बनावेंगे और पहले उनकी हाजरी लें उसके बाद चाहे तो आप हाथ उठवा लीजिये या वोट डलवा लीजिये लेकिन इस सदन में इस सम्बन्ध में काम्युनेलिज्म की जो चर्चा होती है उसके लिये मैं यह कहूंगा कि वास्तव में कॉम्युनेलिज़्म किसी किस्म का हो उसको रोकना अवश्य चाहिये। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और बड़ी हंसी आती है जब मैं यह सुनता हूँ कि फलां जगह लोग जाट राज्य कायम करना चाहते हैं, फलां सदस्य जाट हैं, फलां मिनिस्टर जाट है, फलां व्यक्ति जाट है और पंच चुना गया वे उनको राजस्थानी क्यों नहीं मानते; चाहे वह जाट हो या गूजर ?

एक माननीय सदस्य—आप जाटों का ही नाम क्यों लेते हैं ?

श्री गोपीलाल यादव—मैं दूसरों के बारे में भी कहता हूँ ? मैं जाट नहीं हूँ, मैं अहीर हूँ।

(विराम)

तो शंकर राव देव कमीशन के हैड होकर भरतपुर आये। उन्होंने मुझसे पूछा कि यादव साहब बताइये कि भरतपुर के जाट एन्टी कॉंग्रेसी क्यों है ? मैंने उन्हें जवाब दिया कि भरतपुर के जाट एन्टी कॉंग्रेसी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सब ने यही कहा है कि भरतपुर के जाट एन्टी कॉंग्रेसी हैं। मैंने उन्हें जवाब दिया कि यह गलत है। कारण यह है कि दफ्तर में नौकरियों में सौ फी सदी पचास फी सदी कायस्थ, ब्राह्मण, बनिये और दूसरी कौमों के लोग भरे हुए थे। कभी किसी जाट ने कहा कि हम बैकवर्ड हैं, नौकरियों में नहीं हैं, हमको नौकरियों में रखो। हिज़ हाइनेस ने कुछ अहीरों को और कुछ गूजरों को नौकरी में रख दिया तो कॉंग्रेसी पेपर्स ने प्रचार किया कि यह राजा जाट हो गये, यह जाटों को ही नौकरी दिलवा रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि जाटों ने इसको रिजेन्ट किया। जाट यह समझने लग गये कि भरतपुर के कॉंग्रेसीं दुश्मन हैं। भरतपुर के जाट केवल भरतपुर कांग्रेस के ही खिलाफ थे, बाकी सारी कॉंग्रेस के भक्त थे। देहली की भी मुख्य चीज़ बताता हूँ। देहली की डिमान्ड थी कि उसको बड़ा सूबा बनाया जाय। यह सब लोगों की तरफ से और देहातों की तरफ से भी मांग आयी। शहरियों ने प्रचार किया कि यह तो जाट लोग बनाना चाहते हैं। मेरे पास जब आये तो मैंने कहा कि यह बिलकुल झूठ है और इस तरह एक कॉम्युनिटी के पीछे पड़ेगें तो देश का अहित करेंगे। इसलिये कॉम्युनिलिज्म का गलत प्रचार नहीं करना चाहिये।

इसके अलावा मुझे एक और चीज़ बताना है। नई योजनाओं का श्रीमन् राजप्रमुख ने जिक्र किया है। नदी-घाटी और बिजली के लिए जिक्र किया है। मैं कई सालों से बार-बार निवेदन करता आ रहा हूँ कि राजस्थान के किसानों के लिए जब तक कुएँ नहीं बनावेंगे, बड़ी तादाद में रकम नहीं रहेगी तब तक कोई सुधार होने वाला नहीं। भाषण में नदी-घाटी का तो जिक्र है किन्तु राजस्थान की गवर्नमेन्ट ने दो करोड़, या एक करोड़ रुपया इस बात के लिए सेट अपार्ट नहीं किया है कि जिससे ट्यूब वेल्स बनाये जायं। पानी समस्या का जिक्र है कि उसके लिए रुरल वाटर बोर्ड बन गया। मैं

[श्री गोपीलाल यादव]

निवेदन करूं कि उसके लिए प्लानिंग की जरूरत है। राजस्थान में बहुत से गांवों में पानी नहीं है। एक गांव तीन मील पर तो दूसरा गांव चार मील पर मिलेगा। पानी की समस्या का हल इस तरह से नही कर सकते। कम से कम राजस्थान का एक गांव तीन हजार और पांच हजार की आबादी का हो। दो सौ, पांच सौ घरों के गांव हैं उनको इकट्ठा करायें। ट्यूब वेल बनावें, पचास हजार रुपया खर्च होगा। उस ट्यूब वेल के जरिये से दस गांवों को आबाद बना दीजिये। फिर सिंचाई भी उससे हो सकती है। उससे पानी मिलेगा और लोगों की हालत ठीक होगी। अगर इस तरह की स्कीम सारे राजस्थान के लिए बना देगें तो ठीक रहेगा। चम्बल का पानी थोड़े इलाके में जावेगा, भाखरा का पानी थोड़े इलाके में जावेगा। उससे बाकी के सारे राजस्थान का इलाका सरसब्ज होने वाला नहीं है। उनकी गरीबी को जब तक मिटावेंगे नहीं तब तक राजस्थान के लोगों का दुख दूर होगा नहीं।

गवर्नमेन्ट की अच्छी योजना हैं कि दूसरी जगहों में दफ्तर भेजें। अब तक जो नुक्स रहा है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और माननीय मुख्य मन्त्री जी इस पर ध्यान दें। भरतपुर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट भेजा, अहलकार हैं जयपुर, बीकानेर और उदयपुर के। उदयपुर में एक्साइज डिपार्टमेन्ट भेजा, भरतपुर के रहने वाले मुसीबत में फंस गये। जयपुर में रहते हैं तो इतनी मुसीबत नहीं। वे वहां से घर नहीं जा सकते हैं। जयपुर से बॉम्बे आसानी से पहुँच सकते हैं लेकिन जयपुर से उदयपुर पहुँचने में अधिक टाइम लगेगा और गरीब अहलकार जिनको १००) रुपये पे (pay) के मिलते हैं यदि एक दफा भी घर जांय तो उनकी बड़ी मुसीबत होती है। डिपार्टमेन्ट के साथ-साथ एक काम और कर दें कि भरतपुर में जो डिपार्टमेन्टस् हैं उनमें सौ या उससे कम वेतन पाने वाले अहलकारों को, जो वहीं के हों और काम कर सकें उनको वहां पर ट्रान्सफर कर दें। उदयपुर में जो महकमे भेज रहे हैं उनमें उन लोगों को भेज दें जो वहां के रहने वाले हों। इसी तरह कोटा के हैं तो कोटा में। ऐसा होने पर वे दिल लगाकर काम करेंगे। इससे डिपार्टमेन्ट भी सक्सैसफुल बनेगा और वहां के लोगों को भी तसल्ली होगी। नहीं तो, बाहर के अहलकार कोशिश करेंगे कि यह फैल हो जाय। इस तरह नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी।

बेकारी की समस्या के सम्बन्ध में भी श्रीमन् राजप्रमुख ने जिक्र किया है। यह बेकारी तो भयंकरता के साथ बढ़ रही है और जबतक इसका हल नहीं किया जायगा काम नहीं चलेगा। बेकारी को दूर करने के लिए कहा है कि कारखाने खुलेंगे। पता नहीं कब खुलने वाले हैं ? सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट पर जोर देकर दो-चार कारखाने जरूर खुल जाने चाहिए जिससे कुछ लोगों को राहत तो मिले। जो बेकारी की समस्या है वह केवल एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज में आंकड़े लेकर बतायी हुई है। लेकिन हजारों आदमी ऐसे हैं जो बेकार बैठे हैं। न दरख्वास्तें दे सकते हैं और न कोई पूछता ही है। बेकारी की समस्या को दूर करने के लिए बड़ा भारी प्रयत्न करना है। जब तक यह (समस्या) हल न हो, जब तक कि सब आदमी काम पर न लगा दिये जायें, हमें चैन से नहीं बैठना है। मुझे एक बड़ी चीज़ का दुख होता है और वह यह है कि हम खुद रोजगार पा रहे हैं; हमारे चार लड़के हैं, चारों को रोजगार दिला दिया लेकिन फिर हम रिश्तेदारों के लिए सिफारिश के साथ ऑफिसर्स को एप्रोच करते है और उनको भी मिल गया; लेकिन हम यह नहीं सोचते कि वह गरीब आदमी जिसके एक ही बच्चा है उसको सर्विस मिलने का कोई तरीका नहीं हैं। वह इस तरह से डिजेक्टेड हैं कि उस (बच्चे)

[श्री गोपीलाल यादव]

को कुए में डाल दे । मैं यह निवेदन करूं कि देहातों में नौकरियों के लिए कदर बढ़ायी जा रही है, उनको नौकरियों में लेते हैं; लेकिन कई नौकरियां ऐसी होती है कि देहातियों को पता ही नहीं लगता और वे पूरी हो जाती हैं । सिफारिशें उनके पास काफी नहीं होती । अतः कम से कम आप अफसरान को हिदायत करेंगे कि रिक्रूटमेन्ट करें तो ८० फीसदी आदमी देहात से लें । इस वक्त इस रिजर्वेशन की सख्त जरूरत है और जब तक ८० फीसदी देहात के आदमियों को रिजर्वेशन नहीं देंगे तब तक देहातों की बेकारी नहीं सुधरेगी और देहातियों को प्रोत्साहन भी नहीं मिलेगा ।

इसके अलावा एक चीज़ का मुझे जिक्र करना है जो श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में रह गई । वह है अच्छी परम्परायें कायम करना । मैं यह चाहता हूं कि अच्छा होता कि अगर राजप्रमुख इस चीज़ पर जोर देते कि हाउस अच्छी परम्परायें कायम करे, राजस्थान की भलाई के लिए काम करे, आपस में लड़ना-भिड़ना छोड़े और एक प्रकार का जो वायुमंडल बना हुआ है और जिससे राजस्थान की भलाई नहीं हो रही है, उसको छोड़ कर इसको कल्याणकारी राज्य बनावें । इन शब्दों के साथ मैं अपने अमेन्डमेन्ट को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हरिदेव जोशी—अध्यक्ष महोदय, कल से श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण पर...

श्री अध्यक्ष—Ten to fifteen minutes.

श्री हरिदेव जोशी—कल से श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर विवाद हो रहा है । मुझे इस विवाद के सिलसिले में बहुत कुछ नहीं कहना है । मैं केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि हमको यह समझना है कि आखिर राजप्रमुख का भाषण कोई रामायण, गीता, अथवा महाभारत का बहुत बड़ा पोथा तो नहीं हो सकता है, उसमें कुछ सीमित चीजें ही आ सकती हैं । उसमें उल्लेख करने के लिए कुछ इतनी चीजें ही हो सकती हैं कि जिनके आधार पर हम यह समझें कि यह आगामी वर्ष हमारा किस तरह का होगा, हम क्या-क्या योजनायें बना रहे हैं और हमने कितनी योजनाएं बना कर पिछले दिनों उनमें क्या-क्या सफलतायें पायी हैं और यदि उसी नुक्तेनजर से हम श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण को देखें तो मैं समझता हूं कि भाषण अपने आप में काफी पूर्ण है, अनावश्यक शब्दावलियां और अनावश्यक संदर्भ इसमें नहीं हैं । काफी आंकड़े देकर, कुछ ठोस बातें बतला कर, अभिभाषण में यह बतलाने का प्रयत्न किया गया है कि वर्तमान से आगे बढ़ कर इस प्रान्त को आगे बढ़ाना चाहिए ।

इसमें कोई शक नहीं कि हमारे कुछ मित्रों को इससे निराशा होती है और वे इसलिये निराश होते हैं कि वे इसमें अपने ढंग की, अपनी रुचि की और अपने प्रकार की चीजें देखना चाहते हैं । कई बार तो कुछ लोग अपनी धारणा के अनुसार, अपनी इच्छानुसार चीजें नहीं देख पाते इसलिये निराशावश वे ऐसी बातें कहते हैं । आखिर एन० सी० सी० और ए० सी० सी० की ट्रेनिंग आज के युग की आवश्यकता है । इसके लिये यह कहना कि यह आज के युग के अनुसार नहीं है इस प्रकार की कुछ चीजों को कहने से ऐसा मालूम होता है कि हमारे पास में सोचने के लिये या तो सामग्री ही नहीं है या कहने के लिये कोई चीज नहीं है । इसी प्रकार के वातावरण में कुछ लोग बोले दिखते

[श्री हरिदेव जोशी]

हैं। मैं यह समझता हूं कि अपनी सारी कठिनाइयों के बावजूद अपनी सारी कमजोरियों और कमियों के बावजूद भी राजस्थान आगे बढ़ा है। राजस्थान के अन्दर जो तरक्की के काम हो रहे हैं उनके लिये मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि हम इन कार्योंसे एक मिसाल कायम कर सकेंगे, हम बतला सकेंगे आगे के वर्षों में और भविष्य की पीढ़ी बतला सकेगी कि राजस्थान का नक्शा इन वर्षों के अन्दर बदला है।

राजस्थान एक मरुस्थल है, इसमें कोई शक नहीं, मगर अगले पांच सात वर्ष बतलायेंगे कि हम राजस्थान का कैसा स्वरूप देख रहे हैं। हम वास्तविकता को बदलना चाहते हैं और उस वास्तविकता को मैं आंकड़ों के रूप में देखना चाहता हूं यह कल हमारे एक मित्रने कहा था। उनके अनुसार राजप्रमुख ने जो आंकड़े खेती के सिलसिले में बनाये हैं वे क्या झूठे हैं, गलत हैं। आपको यह ज्ञात होना चाहिये कि गत वर्ष उतनी सिंचाई नहीं हुई क्योंकि गतवर्ष भाखरा से हमें पानी नहीं मिला। इस वर्ष भाखरा का पानी हमारे यहां आया है इससे यह साफ प्रतीत होता है कि हमने इतनी प्रगति इसमें की है। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिये कि राजस्थान सरकार ने कुछ काम किया है।

मैं पिछले दिनों जब कोटा गया था तो वहां पर मैंने चंबल का कार्य देखा। उसे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ये काम ऐसे हो रहे हैं जिनसे हम यह समझ सकते हैं कि राजस्थान के अन्दर महान् कार्य हो रहे हैं। इस कार्य से चाहे पूरे राजस्थान का नक्शा न बदले किन्तु राजस्थान के एक भाग का अवश्य नक्शा बदल जायगा। गांधी सागर बान्ध से बिजली और कोटा बेराज से हमें पानी मिलेगा, उससे सिंचाई होगी और खेती होगी। इससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी, लोगों की हालत सुधरेगी। तो जो चीज है और जो हो रही है उनको हमें स्वीकार करना चाहिये। इसके लिये यह कहना कि ये कपोल-कल्पनायें हैं, केवल सब्ज बाग दिखाना है, ठीक नहीं, यह वे ही लोग कह सकते हैं जिनको अपने स्वप्न निरर्थक होते दिखते हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि किसानों को उपज की कीमत घट रही है, मगर हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि यह समस्या और बेरोजगारी की समस्या तथा अनाज के भावों की समस्या यह सारे हिन्दुस्तान की समस्या है और इसे हमें अखिल भारतीय स्तर पर ही देखना चाहिये। अगर राजस्थान सरकार इस पर कुछ करती है तो वह केवल थेगली लगाने के बराबर ही हुआ। केवल दो-चार टांके लगाने से ही सारी चादर नयी नहीं हो सकती। इसके लिये तो नई चादर ही खरीदनी होगी। कल एक मित्र ने यह भी कहा था कि हमें भी मध्यभारत सरकार की तरह अनाज खरीदना शुरू कर देना चाहिये।

श्री जवानसिंह—यह चादर ही तो बदलनी है।

श्री जोशी (अपना भाषण जारी रखते हुए)—मैं भी तो यही कह रहा हूं कि आपको चादर बदलनी पड़ेगी, आपको अपने नुक्ते निगाह को बदलना होगा। आप अपने दिमाग के अन्दर यह सोच कर बैठे हैं कि केवल दो-चार टांके लगाने से ही नई चादर हो जायगी, तो उससे काम बनने वाला नहीं।

[श्री जोशी]

अध्यक्ष महोदय, मैंने सुना है कि राजस्थान सरकार भी कुछ अनाज खरीदने के विषय में सोच रही है और कुछ अनाज खरीदा भी है। यह कितनी हद तक सफल होगा या हुआ है यह मैं नहीं कह सकता। कुछ हजार मन, १० हजार मन या लाख दो लाख मन अनाज के खरीदने से किसानों के उपज की कीमत बढ़ सकती है तो इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं। आज यदि १० लाख मन अनाज खरीद लिया तो केवल इस वर्ष ही किसानों को फायदा होगा। एक तरफ तो यह हो रहा है कि जो चंबल योजना चल रही है उसके पूरे होने से लाखों मन अनाज की पैदावार होगी, उसी प्रकार भाखरा से भी लाखों मन अनाज पैदा होगा, पार्वती योजना से हमें काफी लाभ होगा। इस तरह से पैदावार लगातार बढ़ती रही और उसी रफ्तार से अनाज के भाव गिरते गये तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि आखिर हमें इसके लिये क्या करना है। जैसा कि श्री एच० के० व्यास ने बतलाया कि मध्यभारत सरकार की तरह राजस्थान सरकार को भी अनाज खरीदना शुरू कर देना चाहिए। मैं उनके इस सुझाव से काफी हद तक असहमत हूं इसलिए कि समस्या यह नहीं है कि अनाज को खरीद कर किसानों के भावों को ठीक रखा जाय किन्तु समस्या तो यह है कि किस प्रकार की पैदावार की जाय जिससे किसानों की हालत ठीक हो सके। इसलिये किसानों को सही नेतृत्व दिया जाना चाहिये, उनको सही दिशा बतलानी चाहिये कि आया वे किन-किन चीजों की पैदावार करें। क्या वे गेहूं, चना, जौ की पैदावार करें या दूसरे कैश प्रोडक्ट्स पैदा करें।

इस प्रकार ऐसी चीजें हैं जिनसे राजस्थान प्रगति कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। इससे हमें यह पूर्ण आशा है कि निकट भविष्य में राजस्थान का स्वरूप बदलेगा। जैसा कि हमने राजप्रमुख के भाषण में पढ़ा इन्जीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वालों की संख्या बढ़ा रहे हैं, ओवरसियर कोर्स के लिए हम स्थान बढ़ा रहे हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिनकी हमें बहुत आवश्यकता है। इससे हम टेक्निकल हेन्ड्स को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा देने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आज शिक्षितों के अन्दर बेकारी है जो कि एक प्रकार से हमारे लिए सिर-दर्द बना हुआ है। यह बेकारी एक प्रकार से हमें दूसरी ओर सोचने को प्रेरित कर रही है। अध्यक्ष महोदय, आज हमें यह सोचना है कि आखिर हमने इस समस्या को हल करने का क्या तरीका अख्त्यार किया है और हम इस समस्या का हल किस प्रकार करना चाहते हैं ? श्रीमन् राजप्रमुख का जो भाषण हुआ उसमें सरकार की रीति-नीति का जिक्र है। उससे एक चीज़ तो समझ में आती है कि सरकार शिक्षा की नीति में परिवर्तन करना चाहती है। सरकार प्राइमरी शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहती है। आज देश के सामने दो प्रकार की शिक्षा प्रणालियां हैं और उन दोनों पर एक्सपेरिमेन्ट्स हो रहे हैं। इस अनुसन्धान के बाद हमारी सरकार इस निर्णय पर पहुँची है कि यहां बेसिक शिक्षा की पद्धति को काम में लिया जाय। यही एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जिसके अनुसरण से शिक्षित बेकारों की संख्या पर पाबन्दी लग सकती है। धीरे-धीरे अगर हमने इस पद्धति के अनुसार प्रगति की तो मैं यह समझता हूं शिक्षित बेकारों का अन्त होने वाला है। इसके बाद में आपने यह भी देखा है कि यह राजस्थान सरकार ने निर्णय किया है कि कॉलेज की एजूकेशन को ज्यादा महत्व न दिया जाय, इसके बजाय टेक्निकल एजूकेशन को महत्व दिया जाय। इसी बात को ध्यान में रख कर टेक्निकल स्कूलों की अधिक व्यवस्था की गई है। कल जिन मित्रों ने इस बात का जिक्र किया वे, इन चीजों को नजर अन्दाज करना चाहते हैं वे उस काम को सराहना नहीं चाहते जो काम कि राजस्थान सरकार ने किये हैं।

Page No.33

[श्री हरिदेव जोशी]

मैं यह भी समझता हूं कि एक स्वस्थ परम्परा स्थापित करने की दृष्टि से यह चीज़ सभी को स्वीकार करना चाहिये कि जो काम हुए हैं उनकी हम तारीफ करें। आज इस बात का कोई दावा नहीं कर सकता कि राजस्थान के अन्दर किसी प्रकार की खामी नहीं। हमारी भी कमज़ोरियां हैं, खामियां हैं, लेकिन हम उन खामियों को मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसको मिटाने के लिये हमें सरकार को प्रेरणा देनी चाहिये। आज दुनियां के अन्दर ऐसे कई देश भी हैं जिनमें प्रजातन्त्र की प्रणाली बहुत पुरानी है, जिनकी शासन प्रणाली भी बहुत पुरानी हैं। वे देश भी यह दावा नहीं कर सकते कि उनके अन्दर कोई खामी नहीं, उनके प्रति कोई शिकायत नहीं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के बारे में यह कल्पना करना कि यहां पर हम में कोई कमज़ोरियें नहीं हैं, यह बहुत बड़ी कल्पना करना होगा। परन्तु एक चीज़ है और वह यह है जो हमें देखना है कि हमारी प्रगति अनुकूल है या नहीं और तरक्की ठीक है या नहीं, इसको हमें नज़र अन्दाज करके नहीं चलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकर बहुत अफसोस हुआ कि हमारे यहां संसदीय परम्परा है कि जो लोग सदन में नहीं बैठे हुए हों, हाउस के सदस्य नहीं हों उनके बारे में ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिये जो उनकी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल हो। कल हमारे मित्र हरिकृष्ण व्यास ने जल बोर्ड और बाहर के व्यक्तियों के ऊपर ऐसे लांछन लगाये, जिनकी सफाई देने के लिए वे यहां उपस्थित नहीं हो सकते। इस प्रकार जो व्यक्ति इस सदन में अपनी सफाई नहीं दे सकते उन पर इस प्रकार के लांछन लगाना एम. एल. ए. जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिये शोभा नहीं देता। ऐसी बातें करने के लिये माणक चौक की चौपड़, उनकी पार्टी का प्लेटफार्म या और कोई प्रोपेगेन्डा मीटिंग ही हो सकती थी। माननीय अध्यक्ष, मुझे क्षमा किया जाय कि सदन में इस तरह से अपने दिल के गुब्बार निकाल कर वे प्रान्त की तरक्की करना चाहते हैं, तो यह गलत है। राजस्थान सरकार ने महसूस किया कि गांवों के अन्दर जिस प्रकार की पानी की व्यवस्था होनी चाहिये उस प्रकार की नहीं हो रही है, अतः इसके लिए जल-बोर्ड का निर्माण किया। इस निर्माण के अन्दर भी यह चीज़ थी कि ऐसे लोगों को लिया जाय जो इस काम के लिये अपना समय, पैसा और सुविधाएं दे सकते हैं, और वास्तव में काम कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रख कर राजस्थान सरकार ने बोर्ड का निर्माण किया। वह बोर्ड सफल होगा अथवा असफल, यह भविष्य बतायेगा। इस बोर्ड के बारे में राजनैतिक विचारधाराओं को लेकर सदन में अपने दिल के गुब्बार निकालना, बोर्ड से नाराज़ी प्रकट करना, और उन लोगों के बारे में गलत धारणा प्रकट करना, जो कि अखिल भारतीय आधार पर सेवा का कर्य कर रहे हैं, यह कहां तक उचित है। सदन को अधिकार है कि उसके बारे में कुछ कहे, परन्तु उसी हालत में जब कि उनकी असफलताओं का पूरा प्रमाण मिल जाये, जब कि वे काम कर चुके हों अथवा उसके कामों की रिपोर्ट हमारे सामने हो, समय बीत चुका हो और यह समझने की स्थिति में हों कि अब इसके बारे में विचार व्यक्त करने की स्थिति में हैं। परन्तु अभी तो काम ही शुरू नहीं हुआ और उससे पहले ही उसके बारे में बातें करना, लांछन लगाना, धारणाएं व्यक्त करना, हमने

[श्री हरिदेव जोशी]

शुरू कर दिया है, इसका मतलब हम यह समझते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हम अपने दिमाग़ में जो एक तूफ़ान है उसको निकालना चाहते हैं। इससे जाहिर होता है कि हमारे दिमाग़ में एक खराबी है जो हमारी प्रगति में बाधक बनना चाहती है। स वास्ते मैं सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि देश के निर्माण के बारे में जो कोई कार्य कर हो रहा हो तो उसके बारे में अपनी राय तभी जाहिर करें जब कि यह प्रमाण मिल जाय कि उसमें खराबी है।

अब मुझे खामियों के बारे में कहना है। श्रीमन् राजप्रमुख ने सर्विसेज़ के इन्टिग्रेशन के बारे में कहा है। मुझे खुशी है कि यह इन्टिग्रेशन पूरा हो गया है। चाहे किसी आदमी को किसी केडर में रखा हो मुझे किसी में दिलचस्पी नहीं, पर एक चीज़ जो में महसूस करता हूं वह यह है कि चाहे आइ. ए. एस. हों, आर. ए. एस. हों, सबोर्डिनेट सर्विसेज़ के हों पर बहुत बड़ा तबका है इस प्रान्त के अन्दर जो आज की प्रजातान्त्रिक प्रणाली में फिट नहीं हो रहा है। अफ़सोस इस बात का है कि हम देश का निर्माण करना चाहते हैं, ऐसे औज़ारों के जरिये जो या तो इससे विपरीत और कामों के लिए बनाये गये हैं या इस कार्य में वे काम में नहीं आ सकते, काम नहीं दे सकते। जनतन्त्र को सफल बनाने की दृष्टि से एक बहुत बड़ा तबका हैं जो जनतंत्र को सफल नहीं बनाना चाहता। पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने जो सर्विसेज़ से मांग की थी वह मांग थी नेशनल ड्रेस के बारे में, हिन्दुस्तान की वेश-भूषा के बारे में, और उनसे मांग की थी कि नेकटाई को हटाया जाय और बन्द कॉलर का कोट रखा जाय। वार टाइम में चर्चिल ने मांग की थी इंग्लैण्ड के निवासियों से कि पेंट की किनारी को मोड़ना बन्द करदें; देश में जो कपड़े की कमी है तो पेन्ट की किनारों को मोडने से २ इन्च कपड़ा बचने वाला है। इससे देश में जो कपड़े की कमी है उसको पूरा करने में किसी हद तक मदद मिलेगी। आज हमारे देश के नेता ने भी यह मांग की है, लेकिन ऊंचे से नीचे तक के अधिकारियों को देखा है कि देश के नेता की इस पुकार (अपील) का उन पर कोई असर नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष, में ऐसा समझता हूं कि उन लोगों के दिमाग में, दिल में, ऐसी भावना नहीं है कि नेता की पुकार की क़द्र कर सकें, ऐसी मांग के माफ़िक चल सकें, देश के निर्माण के लिए आगे बढ़ सकें, वह लोग देश का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिये मैं आपके ज़रिये उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो देश का निर्माण करना चाहते हैं उनकी क़द्र करें और सहयोग दें, न कि उनके काम में बाधक बनें।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति पदासीन)

सर्विसेज़ के अन्दर उत्साह हो, कर्मण्यता हो मैं उनसे इस बात की इसलिये मांग करता हूं कि देश को आजाद कराने में आज की सर्विसेज़ ने जब काम नहीं किया तो उनके लिये आज मौक़ा है कि और भी ज्यादा उत्साह के साथ देश के निर्माण में भाग लें और देश को आगे बढ़ायें और अपनी जो कमज़ोरी रह गई है उसको पूरा करें। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

चेयरमेन महोदय, आप घंटी बजाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बैठ जाना चाहिये, परन्तु मैं दो बातें और कहना चाहता हूं।

श्री सभापति—आपका समय हो चुका है, अब दो मिनट से ज्यादा नहीं मिलेंगे।

श्री हरिदेव जोशी—वह यह है कि श्री गोपीलालजी यादव ने अभी एक संशोधन रखा था, मैं उनके भाषण से अक्षरशः सहमत हूं। मुझे उनके भाषण में कोई संशोधन नहीं करना है क्योंकि पहला मौका है जब कि श्री यादवजी ने सुझाव दिये हैं। मैं भी समझता हूं कि राजस्थान सरकार को उन सुझावों पर अमल करना चाहिये, विशेष कर पंचायतों के चुनाव होते हैं उनके बारे में। क्योंकि बदगुमानियां, गलतफहमियां होती हैं उनको रोकने की कोशिश करना होगा। उनके कथन का मैं समर्थन करता हूं, परन्तु ताकत के साथ में उनके संशोधन का विरोध करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे अपने संशोधन को वापिस ले लें। आशा है वे उसे वापिस तो लेंगे ही।

मैं मानता हूं कि अनाज के भाव गिर रहे हैं, मगर मैं यह नहीं जानता हूं कि वे जो कुछ कहते हैं वह इसलिये कहते हैं, क्योंकि उनके भी भाव गिर रहे हैं। उन्होंने आज देखा है कि आंध्र में चुनाव के क्या रिज़ल्ट्स रहे हैं। उनके वहां भाव गिरे हैं। इसलिये गिरे हैं कि उनकी धारणा एक प्रकार की होती है। उनकी धारणा की मार्केट वेल्यू तब बढ़ती है जब कि असंतोष हो, कोई गड़बड़ी हो, जहां फसाद और कुछ ऐसी चीज़ हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन भावों को संतुलित करने की कोशिश करना है। वे भाव संतुलित तब होंगे जब कि दूसरे प्रकार के भावों की कीमत बढ़ाने की वे कोशिश करें। मेरा निवेदन यह है कि यदि वे कन्स्ट्रक्टिव सुझाव दें तो उनके भावों की क़ीमत बढ़ सकती है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय (सभापति), मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार के भावों की क़ीमत बढ़ती रहे तो उनके भावों की क़ीमत भी बढ़ती रहेगी, उनकी बातों की भी क़ीमत बढ़ सकती है और उनकी बातों की क़ीमत तब बढ़ेगी जब कि वे कन्स्ट्रक्टिव सुझाव देकर अपने उन भावों की क़ीमत घटायेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय चेयरमेन, श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर यह वादविवाद हो रहा है। श्रीमन् राजप्रमुख को धन्यवाद का प्रस्ताव भेजें या नहीं, उसमें विभिन्न रायें सुनने में आ रही है। श्रीमन् राजप्रमुख ने यहां पदार्पण करने का कष्ट किया और उन्होंने अंग्रेजी के बजाय हिन्दी में अपना भाषण देकर यहां की भावनाओं का आदर किया, इसके वास्ते तो उनको धन्यवाद दिया जा सकता है, परन्तु जहां तक उनके भाषण में जिन बातों का वर्णन है उस विषय में राजप्रमुख को धन्यवाद देने के मैं विपक्ष में हूं, और उनको धन्यवाद नहीं दिया जा सकता।

उनके अभिभाषण के सुनने से ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे सरकार ने भाषण तैयार करके श्रीमन् राजप्रमुख के सामने रख दिया है और राजप्रमुख से उसे रिसाइट (recite) करवा दिया है, ऐसा प्रतीत हुआ है। यदि श्रीमन् राजप्रमुख देश का दौरा करके और देश के लोगों से पर्सनली-कॉन्टेक्ट करके और देश की वास्तविक परिस्थिति से परिचित होते और देश में फैली हुई गरीबी और बेकारी और दूसरी चीजों की भयंकर समस्याओं से परिचित होते तो, मैं समझता हूं कि श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण का एक दूसरा ही रूप होता। परन्तु दुख है कि श्रीमन् राजप्रमुख ने कॉन्टेक्ट स्थापित नहीं किया देश की मासेज़ से। और अपनी गवर्नमेंट के तैयार किये हुए भाषण को रिसाइट कर दिया। इस वास्ते उनको धन्यवाद देने में मैं अपने आप को असमर्थ समझता हूं।

[रावत श्री शंभूसिंह]

माननीय चेयरमेन महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख ने कई एक मुद्दों पर प्रकाश डाला। उनमें से पहले उन्होंने कानून और व्यवस्था के ऊपर प्रकाश डाला है। जहां तक मैं समझता हूं सरकार कानून और व्यवस्था सुधारने की कोशिश कर रही है, यह एक अच्छा क़दम है। लेकिन जैसा कि दावा किया गया है कि क़ानून और व्यवस्था सुधर रही है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। कितने डाकुओं को पकड़ा गया, कितनों ने आत्मसमर्पण किया; यह किया, वह किया, इस पर प्रकाश डाला गया, मगर इस बात पर एक शब्द भी नहीं कहा गया कि इस वर्ष में कितनी डकैतियां हुईं, कितने हज़ार का माल लूटा गया और कितने का बरामद हुआ और कितना नहीं हुआ। इन बातों पर प्रकाश नहीं डाला गया। अपने मुंह अपनी सरकार की तारीफ़ कर देना कुछ और बात है, परन्तु वास्तविकता कुछ दूसरी है। हम रात-दिन सरकार के दावों को सुनते हैं कि सरकार की क़ानून और व्यवस्था सुधर रही है, लेकिन अखबारों में हम रोजाना पढ़ते हैं कि आज फलाँ जगह डकैती हो गई, हज़ारों का माल लूट ले गये; यह हो गया, वह हो गया, तो कैसे मान लें कि शांति और व्यवस्था में सुधार किया गया है। अभी थोड़े दिन पहले देवगढ़ के पास मदारिया एक स्थान है जिसमें भयंकर डकैती हुई। देवगढ़ में एन्टी डेकोइटी फोर्स बहुत बड़ी तादाद में पड़ी हुई है और उनके पास मोडर्न इक्विपमेंट और जीपें मौजूद हैं और मदारिया देवगढ़ से बहुत नज़दीक है। देवगढ़ में इनफॉर्मेशन पहुँच चुकी थी, मगर फिर भी वहां से सहायता नहीं मिली और जैसे एक असहाय को लूटा जाता है उसी तरह मदारिया में लूट हुई।

एक दूसरा दृष्टांत आपको देता हूं। गंगापुर में आमली एक क़स्बा है वहां की माइका माइन्स का एक गोदाम है। उसमें डकैती हुई, और ताज्जुब यह है कि वहां लूटमार करके उसी फेक्ट्री की मोटर में बैठकर डाकू चले गये और उस फेक्ट्री के मोटर वाले को मजबूर किया गया कि दूर लेजाकर छोड़ा जाय। इसके अन्दर लिखा है कि हमने जीपें खरीद लीं हैं, उनकी कॉम्युनकिशन्स की सहूलियतें बढ़ाने का उद्योग किया जा रहा है। अब तक डाकू ऊंटों पर आते थे। कि अब वे पैदल आने लगे हैं, बावजूद इसके भी वे नहीं पकड़े जा सकते हैं; तो यह कैसे माना जा सकता है कि शांति और व्यव-स्था में इम्प्रूवमेंट हो रहा है? डकैती फोर्स डाकुओं को पकड़ने में कहां तक सफल हो रही है यह तो मैं नहीं कह सकता, मगर डकैती फोर्स की वजह से जनता में आतंक छाया हुआ है। डकैती फोर्स के कई आदमी वहां लोगों पर अत्याचार करते हैं, स्त्रियों को भगाने जैसी कार्यवाही करते हैं। देवगढ़ की ज़नता को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। वे न मालुम किस शक में या और किसी अपनी बात को प्राप्त करने के वास्ते उनके साथ सख्ती करते हैं, और जनता में आतंक छाया हुआ है। तो मैं यह समझता हूं कि यह कोई अच्छी बात नहीं है। जहां तक सरकार इस सम्बन्ध में प्रयत्नशील है वह अच्छी बात है, मगर जितना दावा किया गया है वैसा प्रतीत नहीं होता है।

उसके बाद नेशनल एक्स्टेन्सिव सर्विस ब्लाक्स के वास्ते कहा गया है। यह ब्लॉक्स, मैं सम-झता हूं, वहां खोले जायेंगे जहां एक विशेष पॉलीटिकल पार्टी खोलना चाहती है, और वहीं वे खोले जा रहे हैं। वहां के स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को महसूस करके कोई नेशनल एक्स्टेन्सिव सर्विस ब्लॉक्स नहीं खोले गये।

[रावत श्री शंभूसिंह]

उसके बाद वर्षा की कमी जहां है वहां राहत का काम खोलने की चर्चा की गई, मगर कई ऐसे स्थान हैं कि जहां जरूरत होते हुए भी राहत का कार्य नहीं खोला गया; जैसा कि बरार गांव जो कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है।

राजस्थान भूमि-सुधार और जागीर पुनर्ग्रहण की चर्चा करते हुए श्रीमन् राजप्रमुख ने बहुत सी बातों पर प्रकाश डाला है। जहां तक जागीर पुनर्ग्रहण का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं, उसमें सरकार की यह बात कही जाती है कि वह इन्टरमीडियेरीज (intermediaries) को हटाना चाहती है और इन्टरमीडियेरीज को हटाये जाने से जनता को राहत दिलाना चाहती है। मैं समझता हूं कि जागीर पुनर्ग्रहण से जनता और किसानों में विशेष कर, कोई संतोष नहीं पैदा हुआ है, और न उनको कोई विशेष राहत ही मिली है, क्योंकि सरकार इन्टरमीडियेरी को हटाकर, स्वयं एक इंटरमीजियेरी के रूप में वहां आ बैठी है। जैसा कि किसान और सरकार के बीच में जागीरदार को एक इन्टरमीडियेरी मानते थे तो होना तो यह चाहिये था कि एक जागीरदार के जितने राइट्स और टाइल्स थे वे सब के सब उन किसानों में वेस्ट कर दिये जाते, मगर वे राइट्स और टाइल्स उनमें वेस्ट नहीं करके सरकार खुद बीच में एक इन्टरमीडियेरी बनकर आ बैठी है। राइट्स और टाइल्स जो जागीरदार के थे वे सरकार ने इन्टरमीडियेरी बनकर ले लिए। होना यह चाहिए था कि बजाय रेन्ट पे (pay) करने के किसान रेवेन्यू पे करता रहे आजकल जब कि एग्रिकलचरल इन्कमटैक्स बन गया है तो उसकी भी जरूरत नहीं है। वह एग्रिकलचर इनकम टैक्स पे (pay) करता और इस तरह कोई विशेष रेन्ट वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं थी। किसानों से रेन्ट ही नहीं लिया जा रहा है, बल्कि नये सेटिलमेंट में रेन्ट रेट्स भी बढ़ाये जा रहे हैं। रेन्ट रेट्स के बढ़ जाने के बाद बजाय किसानों को राहत मिलने के और ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी।

इसके अलावा किसानों के साथ ऐसे २ अहलकारों से काम लिया जा रहा है जो कि भ्रष्टाचारी हैं और उनमें अन्सतोष फैलने का वे कारण हो रहे हैं। तो, चेयरमेन महोदय, यह कोई संतोष की बात प्रकट नहीं हुई।

इसके बाद सीलिंग की ओर इशारा किया था। सीलिंग तय की जा रही है, मगर इकॉनोमिक होल्डिंग को नज़र में रख कर की जा रही है या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि राजस्थान में होल्डिंग वैसे ही स्केटर्ड (Scattered) है। कहीं सीलिंग के ज़रिये रक़बा और ज़्यादा स्केटर्ड नहीं हो जायगा ? यदि होल्डिंग ज़्यादा स्केटर्ड हो जाता है तो अनइकॉनोमिक होल्डिंग हो जाता है, और यह, मेरी समझ में, देश के लिए फायदेमंद नही हो सकता।

चेयरमेन महोदय, डेवेलपमेंन्ट और फाइवइयरप्लान (पंचवर्षीय योजना) के विषय में जो राजप्रमुख महोदय ने चर्चा की, वह अच्छी बात है। नये-नये तालाब और बाँध बनने से देश की उन्नति हो सकती है। सिंचाई के अधिक साधन उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ शिकायतें सुनने में आई हैं। जहां तालाबों के बंध हो रहे हैं वहां किसानों की खड़ी फसल को नष्ट किया जा रहा है, और उनको पूरी तरह से कपेन्सेट नहीं किया जाता है, उनको वहां से बेदखल कर दिया जाता है।

[रावत श्री शंभूसिंह]

उन्होंने मेहनत करके अनाज बोया' और वे आशा करते थे कि अच्छी खेती होने पर बाल बच्चों को खाने को मिल सकेगा। उनकी खेती को नष्ट किया जाता है। इसी तरह से जो तालाब या कुए बांध की जमीन के बीच में आ जाते हैं उनको भी बर्बाद किया जाता है और उनके एवज़ में नये बनवाने की कोई व्यवस्था नजर नहीं आती। जो कपेन्सेशन दिया जायगा उससे नये कूए नहीं बन सकते। पहले के बने हुए कुओं में कम खर्चा लगा होगा, लेकिन नये बननेवाले कुओं के बीच में कहीं पत्थर आ गया तो मुश्किल हो जायगी। उनको पूरा कपेन्सेट करना चाहिये। समय समाप्ति सूचक घन्टी।

यदि मुझे और कुछ समय दिया जावे तो बहुत कुछ निवेदन करना है।

श्री सभापति—आप दो मिनिट और ले सकते हैं।

श्री रावत शंभूसिंह—मुझे १० मिनिट और दिये जावें।

श्री सभापति—इतनी गुंजायश नहीं है।

रावत श्री शंभूसिंह-(भाषण जारी रखते हुए) श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में राजस्थान में जिप्सम ज़्यादा मिलने की तरफ इशारा किया और यह फरमाया कि हमने सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को इसके लिये लिखा है कि वे यहां पर फेक्ट्री बना दें तो हम समझते है कि यह बहुत अच्छा क़दम है। जैसा कि मैंने अपने सुझावों में कई मर्तबा कहा था इसको यहां काफी गुंजायश है। उसकी तरफ शायद सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है, यह बहुत अच्छी बात है। राजस्थान में जिप्सम मेटीरियल उपलब्ध होता है उसको यहीं खर्च करने के लिये कारखाना बन जावे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह कारखाना सरकार का ही होना चाहिये। यदि किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा एक्सप्लॉइटेशन हुआ तो ग़रीबों का भला नहीं हो सकेगा।

शिक्षा के लिये राजप्रमुख महोदय ने जो कुछ फरमाया उनमें दो बातों का जिक्र नहीं आया। एक तो यह कि कंपल्सरी प्राइमरी एज्युकेशन कब से की जा रही है और दूसरी बात यह कि शिक्षितवर्ग में अनएम्पलॉयमेन्ट फैला हुआ है। कॉलेजों और स्कूलों से निकलने वाले विद्यार्थियों को एम्पलॉयमेन्ट नहीं मिल रहा है जिसको हल करने के लिये क्या ज़रिया निकाला है, इसका कोई ज़िक्र भाषण में नहीं है। कंपल्सरी प्राइमरी एज्युकेशन होना जरूरी है। पड़ोस के छोटे राज्य अजमेर में यह हो गया है, लेकिन राजस्थान में नहीं हुआ। इसके अलावा जहां हाई स्कूल्स खुलने वाले थे वहां वायदा करने पर भी वे नहीं खोली गये है, जैसे भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में गंगापुर में हाई स्कूल खोलने का सरकार ने कहा था। हाई स्कूल के लिये इमारत बनवा ली गई, लेकिन पहले की सरकार के वायदे के माफिक हाई स्कूल नहीं खोला गया। वर्तमान शिक्षा मंत्रीजी ने, जो आज मुख्य मंत्री भी हैं, आश्वासन दिया था कि हाई स्कूल खोला जायगा। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी के पास शिक्षा का भी पोर्टफोलियो है इसलिये वे वहां पर हाई स्कूल खोलकर वहां की जनता के मन में आदर प्राप्त करेंगे, मुझे इसका पूर्ण विश्वास है।

[रावत श्री शंभूसिंह]

इसके अतिरिक्त लेबर के वास्ते राजप्रमुख महोदय ने इशारा किया था कि इतने मकानात बन रहे हैं लेबरर्स को इतना प्रोविडेन्ट फंड और अन्य सुविधाएं दे रहे हैं। चेयरमेन महोदय, वास्तव में स्थिति यह है कि लेबर में काफी असंतोष है। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जहां माइका काफी मात्रा में उपलब्ध होता है वहां पर माईका लेबरर्स को न तो वक्त पर पैसा मिलता है और न लेबर लॉज और एक्ट के मुताबिक, जो सुविधाएं देनी चाहिये नहीं दी जाती हैं। वहां पर कुछ पोलिटिकल एजेन्सीज़ ऐसी है कि जब तक उन पॉलिटिकल एलिमेन्ट्स् के थ्रू अप्रोच नहीं करते तब तक कोई राहत नहीं मिल सकती। वहां पर जो लेबर इन्सपेक्टर हैं वे क्या करते हैं और उन लेबरर्स को राहत क्यो नहीं दी जाती है? ऐसे भी उदाहरण हैं कि उनको पेमेन्ट नहीं मिलता है और जब तक पोलिटिकल एलिमेन्ट्स को अप्रोच नहीं करते हैं तब तक सुविधा नहीं दी जाती है। ये मुश्किलात लेबर को तकलीफ देने के लिये क्रिएट की जाती हैं। वे महसूस करते हैं कि जब तक पोलिटिकल एलिमेन्ट्स को एप्रोच नहीं करेंगे कोई सुविधा उनको नहीं दी जायगी। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि भीलवाड़ा के लेबरर्स की डिफिकल्टीज (कठिनाईयों) को मिटावें और उनको राहत दिलावें। (समय समाप्त सूचक घंटी)

मैं निवेदन करूंगा कि मुझे ५ मिनिट और दें।

श्री सभापति—आप एक मिनिट में अपना भाषण खत्म करें।

रावतश्री शंभूसिंह—श्रीमन् चेअरमेन महोदय, मैं देखता हूं कि बहुत से वक्ताओं को भाषण देना है इसलिये मैं प्रकट करता हूं कि राजप्रमुख को धन्यवाद दिया जावे। अपना भाषण यहीं समाप्त करता हूँ।

श्री चान्दमल मेहता—चेयरमेन महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण, में राजस्थान सरकार ने एक वर्ष में जो कार्य किया और आयन्दा जो कार्य करने जा रही है, इसका लेखा-जोखा दिया है। उनका सारा भाषण पढ़ने के बाद यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राजस्थान ने पिछले वर्ष में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। जन-हितकारी योजनाएं बनीं, जन-हितकारी क़ानून बने और लॉ एंड ऑर्डर की हालत को ठीक किया गया। इस दृष्टि से श्रीमन् राजप्रमुख और हमारी सरकार को धन्यवाद दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। मैं उन्हें धन्यवाद देने के साथ साथ उन चीज़ों की चर्चा करना आवश्यक समझता हूँ जिनका कि जिक्र उन्होंने अपने भाषण में नहीं किया है, और जिनके बारे में जिक्र होना आवश्यक था।

राजस्थान में कई तरह की प्रगति हुई है और कृषि की प्रगति के बारे में कई मित्रों ने काफी विचार प्रकट किये हैं। मैं राजस्थान सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ औद्योगिक प्रगति की ओर। राजस्थान के निर्माण के बाद कोई औद्योगिक प्रगति नहीं हुई, बल्कि औद्योगिक ह्रास ही हुआ है; यह कहूँ तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। पहले जो बड़े-बड़े कारखाने हमारे यहां थे उनकी शक्ति कम हुई है। महाराजा किशनगढ़ मिल्स में पहले ३००० मजदूर काम करते थे वहां आज केवल ८००

[श्री चांदमल मेहता]

मज़दूर काम करते हैं। इसी तरह दूसरे बड़े-बड़े कारखानों का भी ह्रास ही हुआ है। जहां तक नये कारखानों के निर्माण का सम्बन्ध है मेरी मान्यता है कि इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है और काफी उदासीनता रही है। भारत के कई प्रान्तों में भारत सरकार द्वारा बड़े-बड़े कारखाने खोले गये हैं और वहां पर उनसे बेकारी दूर करने में काफी सहायता मिली है, लेकिन राजस्थान में एक भी ऐसा कारखाना नहीं है जो राजस्थान सरकार के प्रयास से भारत सरकार ने खोला हो। जहां तक छोटे उद्योगों का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करूँगा कि छोटे उद्योग क़रीब-क़रीब समाप्त हो गये हैं, राजस्थान के निर्माण के बाद। मैं इसमें केवल राजस्थान सरकार का ही दोष नहीं मानता। चीजों के भाव गिर जाने के कारण भी ह्रास हुआ है। लेकिन जहां तक राजस्थान सरकार का ताल्लुक है, छोटे उद्योगों को पनपाने का, उसने भी अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं किया है।

राजस्थान के कई उद्योग हैं, जयपुर के उद्योग की खासतौर से चर्चा कर देना चाहता हूं। वह उद्योग एक ऐसा महत्वपूर्ण उद्योग है जिससे कि २० हज़ार आदमियों को काम मिलता है। यही नहीं, बल्कि देश को डॉलर भी मिलता है। दूसरे मुल्कों से कच्चा माल हमारे यहां आता है और उससे इतनी बड़ी संख्या में आदमियों को काम मिलने के साथ साथ उसका जो पक्का माल तैयार करके दूसरे मुल्कों को भेजते हैं, उससे डॉलर भी मिलता है। वह महत्वपूर्ण उद्योग राजस्थान का खरड़ उद्योग है। इस खरड उद्योग की तरफ राजस्थान सरकार ने कोई तवज्जोह नहीं दी है, और इसका नतीजा यह हुआ है कि कच्चा माल जो हम बाहर से मंगाते थे और उसका पक्का माल तैयार करके बाहर भेजते थे उन्हीं मुल्कों ने उस कच्चे माल से पक्का माल तैयार करना शुरू कर दिया है। यह सिर्फ हमारी सरकार की इस ओर तवज्जोह नहीं होने की वजह से हुआ है। इसमें फाइनेन्शियल इमदाद की कोई आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ इस ओर तवज्जोह देकर कुछ सहूलियतें देने की आवश्यकता थी। राजस्थान सरकार अगर प्रयास करती तो कच्चे माल के आयात पर रेस्ट्रिक्शन्स दूर हो सकते थे। इस ओर सरकार की तवज्जोह नहीं होने से २० हज़ार आदमियों को जो काम मिलता था वह तो बन्द हो ही गया है साथ ही साथ जो उसके बदले में हमें डॉलर मिला करता था वह भी बन्द हो गया है, और जब हमारे यहां यह काम समाप्त हो गया तो बाहर के मुल्कों ने, जो हमें कच्चा माल भेजते थे, इस काम की आवश्यकता को महसूस किया, और आज यह काम वहां उन मुल्कों में ही चालू हो गया है। और इस तरह राजस्थान का एक बड़ा गृह-उद्योग समाप्त हो गया है। इसके अलावा और भी कई उद्योग हैं, जैसे साबुन का जो उद्योग है वह लीवर कम्पनी के मुकाबिले में हमारे राजस्थान में चल सकता है पर राजस्थान सरकार की ओर से कुछ ऐसी कठिनाइयां पैदा हुईं, कि कस्टम के रियायत की जो सहूलियतें दी हुई थीं, वह छीन ली गईं, जो इस उद्योग के ह्रास का कारण बनी।

इसी तरह हाथ करघे का उद्योग भी राजस्थान में बहुत पिछड़ा हुआ है। दूसरे उद्योगों की भी यही स्थिति है। राजस्थान सरकार को मैं इस बात के लिये तो धन्यवाद दूंगा कि उसने कुछ समय पूर्व एक फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन का निर्माण किया है, जो मध्यम वर्ग के उद्योगों को आगे बढ़ाने में सहायक होगा।

[श्री चांदमल मेहता]

फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन के बारे में कई बातें सदस्यों द्वारा सदन में कही गई हैं और मैं भी इसके बारे में कहने की आवश्यकता समझता हूं। फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन की कायमी में राजस्थान सरकार ने अपने ऊपर जवाबदारी ली है और उस जवाबदारी के माफिक साढ़े तीन पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट उनको दिया जायगा, जिनके इसमें शेयर्स होंगे। राजस्थान सरकार ने यह जिम्मेदारी अपने सिर पर ली है तो जो इसके पदाधिकारी हों, चेयरमैन हों वे ऐसे हों कि इसको पूरी तरह से निभा सकें। परन्तु इसके जो चेयरमैन रखे गये हैं वे ऐसे हैं जो उन कम्पनीज के मैनेजिंग डाइरेक्टर भी हैं जिनकी ओर राजस्थान सरकार का बहुत बड़ी तादाद में रुपया बाकी है और रुपये का पेमेन्ट नहीं करने के परिणाम स्वरूप सरकार को उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये विवश होना पड़ेगा। एक ओर ऐसे व्यक्ति को फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनायें और दूसरी ओर उनके खिलाफ कार्यवाही करें, यह कहां तक ठीक है।

दूसरी बात मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस तरह के फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन के निर्माण मात्र से ही राजस्थान के उद्योगों की तरक्की नहीं हो सकती। इसके लिये राजस्थान सरकार को राजस्थान की औद्योगिक सर्वे जल्दी से जल्दी करानी चाहिये। श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने अभि-भाषण में इसकी चर्चा नहीं की है। मैं मानता हूं कि राजप्रमुख के भाषण में सारी की सारी बातों की चर्चा नहीं हो सकती, पर राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर गया है और इस वर्ष औद्योगिक सर्वे पूरी करा दी जायगी।

छोटे उद्योगों को ऋण देने के लिये समिति बनी है और उसके ज़रिये ऋण दिये जा रहे हैं, पर साथ ही अर्ज करूँगा कि जिन अधिकारियों के हाथों में यह काम सौंपा है उन अधिकारियों के जरिये वास्तविक काम हो सकेगा या नहीं, इस बात की पूरी निगरानी रखने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि ऋण दे दिये जायं और काम नहीं हो। सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण के लिये एक्सपर्ट भी मुकर्रर किये हैं। एक-आध एक्सपर्ट हमारे यहाँ किशनगढ़ में पहुँच गये। उनका काम यह है कि घर पर रहें और तनख्वाह लेते रहें। टेक्निकल शिक्षा की जो बात बताई गई है उसको कार्यवाही हो; ऐसा नहीं कि कोई अमली कार्यवाही न हो और कोरी कागजी कार्यवाही ही रह ज़ाय।

लॉ एन्ड ऑर्डर की बात बताते हुए कुछ आँकड़े दिये गये हैं और उनमें बताया गया है कि हमने इतने प्रतिशत तरक्की की है, बड़े बड़े जुर्मों में कमी हुई है। पर मैं निवेदन करूँगा कि सरकार ने आदमियों के अपहरण जैसे मामलों को बड़ा मामला नहीं समझा है और इसका जिक्र तक नहीं किया है। सम्पत्ति का लूटा जाना इतना बड़ा अपराध नहीं माना जाता जितना बड़ा अपराध कि आदमियों का अपहरण का मामला है। आदमियों के अपहरण के बारे में मन्त्री महोदय भी मानते होंगे कि इसमें कमी नहीं हुई है, उनके एक स्टेटमेन्ट में भी ऐसी बात कही गई कि इस अपराध में कमी नहीं हुई है। एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि लूट-मार को कम करने के लिये पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इसको कम करने की सरकार ने कोशिश भी की और लूट-मार कम हुई, इसमें जो ४५ पर्सेन्ट कमी हुई है उसके लिये सरकार धन्यवाद और बधाई की पात्र है। पर मैं सरकार को अर्ज कर दूँ कि नई तरह के डाकू पैदा हो गये हैं।

[श्री चांदमल मेहता]

जो डाकू डाका डालने आते हैं वे घन्टे दो घन्टे लूटते हैं; पर ये जो दूसरी तरह के डाकू हैं वे मुस्तकिल तोर पर लूटते ही रहते हैं और इनकी लूट के माल की तादाद करोड़ों पर पहुँचती है। ये जो डाकू हैं इनके लिये फौज पुलिस सब है पर दूसरी तरह के जो ये डाकू हैं उनके लिये ये कोई साधन काम में नहीं आ सकते। शायद मन्त्रीजी सोचेंगे कि ये कौन से डाकू हैं। मैं निवेदन कर दूँ इस बारे में। हमारी जो योजनाएँ हैं उनके ऊपर कितना खर्चा हुआ है और हमें कितना रिटर्न मिला है, इस पर सोचेंगे तो पता चलेगा कि वे डाकू कौन से हैं। कहा गया कि ७०० मील लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया है। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान से सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में सड़कें बनेगी तब तक फर्स्ट फाईव ईयर प्लान में बनी हुई सड़कें खत्म हो जायेंगी। निर्माण कार्यों में अधिकारियों का कमीशन मुकर्रर है। जयपुर राजधानी है और यहां पर बड़े-बड़े अफसर ज्यादा रहते हैं तो ३० पर्सेन्ट कमीशन मुकर्रर है। उक्त कमीशन में बन्दर बाँट सभी छोटे-बड़े अफसरों की होती है। और दूसरे डिविजन्स हैं, जहां बड़े अफसर कम रहते हैं तो वहां २० परसेन्ट कमीशन की बन्दर बांट हो जायगी।

जहां उन बड़े डाकुओं की फिक्र करते हैं तो इन डाकुओं की ज्यादा फिक्र करनी पड़ेगी, जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, हम कर लगा कर जो लेते हैं, और वह पैसा जो भारत सरकार से लोन के रूप में लेते हैं, उसको बीच ही में लूट लेते हैं।

अगर इस बात में सत्य है, तथ्य है तो मैं तो यही कहूँगा कि हमने जनता के साथ एवं भारत सरकार के साथ विश्वासघात किया है। इसके लिये फरियाद करने वाला कोई नहीं और यदि कोई मिल जावे तो पुलिस में रिपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। मैंने सड़कों को खोदकर देखा और मालूम हुआ कि जहाँ एग्रीमेन्ट में ६ इँच मोटा पत्थर का खुर्रा बनना चाहिये था वहाँ पर ३ इँच मोटा पत्थर का खुर्रा बनाया गया और जहाँ ५ इँच मोटी गिट्टी सड़क पर डालनी चाहिये थी वहां पर दो इँच मोटी गिट्टी डाली गई। ये सारी चीजें मैं किसी प्रकार आलोचना करने की दृष्टि से नहीं कहता हूँ; मैं यह इसलिये कहता हूँ कि यह अच्छा हो कि अगले वर्ष इसमें सुधार हो। जिस समय जवाब दिया जावेगा उस समय सरकार की तरफ से यह कहा जावेगा कि यह सही नहीं है तो मैं उनसे यह कहूँगा कि वे किसी भी सड़क पर मेरे साथ चले चलें, मैं उनको कन्विन्स करा दूँगा कि मैंने जो कहा है वह सच है या नहीं। जैसा की विरोधी दल के आदमी आलोचना के लिये कहते हैं वह बात यहाँ पर नहीं है। मैंने तो यह बातें इसलिये कहीं हैं कि सरकार इस पर ध्यान दें और यह कह कर मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मैं दूसरी बात यह अर्ज करना चाहता हूँ।

श्री एच. के. व्यास—क्या सारी सड़कें ही ऐसी हैं?

श्री सभापति—आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री चान्दमल मेहता—मैं एक बात आखिर में जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि जहां पुलिस डाकुओं को गिरफ्तार करने में सफल हुई है वहां पर वह डाके डालने में भी सफल हुई है। जो पुलिस डाके डालने वालों को पकड़ सकती है वह डाके डालने में भी माहिर है। इस सम्बन्ध में कई कोन्क्रीट एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूं जिससे यह साबित होगा कि पुलिस का क्या काम रहा है। पुलिस वाले चोरियों की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करते और अगर करते हैं तो भी मुलज़िमानों को रुपये मिलने पर छोड़ देते हैं और उनका चालान नहीं करते। चोरी की रिपोर्ट के भी पैसे लेते हैं और जब एसेम्बली में रिपोर्ट करते हैं तो झूठी रिपोर्ट करने का मुकद्दमा चलाते हैं। इस सम्बन्ध में पुलिस पर जब बहस होगी उस समय सारी बातें डिटेल में कहूँगा और सारा प्रकाश डालूँगा।

इसलिये मैं निवेदन करूँगा कि जो कुछ राजप्रमुख ने अपने भाषण में कहा है और जैसी योजनाएँ हैं उसके लिये हम निश्चित तौर से उनको धन्यवाद देंगे क्योंकि सारी बातें पूरी नहीं हो सकतीं, कुछ अधूरी रह सकती हैं। मैं यह मान कर चलता हूँ कि हमारी सरकार की जो कमियें रह गई हैं, आयन्दा आने वाले वर्ष में वह उन खामियों को पूरा कर देगी।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—माननीय चेअरमैन, मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करने के के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं पंचायत के चुनाव के सिलसिले में कुछ अर्ज करना चाहूँगा। मैंने देखा कि गंगानगर जिले में पंचायत के जो चुनाव हुए वे किस तरह हुए। इस विषय में कुछ बातें कही गई हैं लेकिन जो बातें मैंने देखी हैं वे विचित्र किस्म की है। मैं देखता हूं कि ऐसे गांव आपको मिलेंगे जो चुनाव-क्षेत्र में नहीं हैं और वहां के लोग चुने जाते हैं। यह एक हेरानगी की बात है कि ४. बी. बी., ३८, ३६, ४०, ४१, ४२ बी. बी. की जमीने हैं, मगर बजाय यहां के १६ बी. बी. और १७ बी. बी. से एक पंच और एक सरपंच चुना गया और वह भी ऐसा चुना गया जो हिन्दी नहीं जानता। जिसके पास करीब २५० वोट थे और विरोधी के पास १३०० वोट थे। १३०० वोट होते हुए भी वह दूसरा चुना कैसे गया, यह एक खास बात है। वह कैसे चुना गया, यह मैं बतलाता हूं। वहां एक राजनैतिक पार्टी रिटर्निंग ऑफिसर के साथ रहती थी और एक दिन पहले वह जिन लोगों को पंच चुनवाना होता उसको टिकट दे देती और दूसरे दिन उसको चुन लिया जाता।

श्री एच. के. व्यास—कौन सी पार्टी थी।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—जो पार्टी अभी पॉवर में है।

ऐसा भी हुआ। कई जगह से लोग खड़े नहीं हुए, नोटिफिकेशन करवाया नहीं, मगर फिर भी चुने गये। जैसे आप देखेंगे कि चानणा में पंचायत के लिए २ आदमी खड़े हुए। एक का नाम सरदार गणपतसिंह और दूसरा गुरुदयालसिंह। गुरुदयालसिंह नहीं चुना गया। ऐसा आदमी चुना गया जो वहां क्षेत्र में हाजिर नहीं था। दूसरों का जिक्र करने से पहले मैं अपना ही जिक्र करना मुनासिब समझता हूं। मैं अपने ही पंचायत क्षेत्र की बात करता हूं। उस क्षेत्र के मुतल्लिक कई दिन पहले ही यह ऐलान कर दिया गया था कि हम अपनी मर्जी के पंच और सरपंच चुनेंगे। इसके

[श्री गुरुदयाल सन्धु]

मुतल्लिक १६. १२. ५४ को मैंने एक चिट्ठी सेन्ट्रल गवर्नमेंट और माननीय मुख्य मंत्री को भी दी और लिखा कि यहां पर यह होने वाला है। उसके बाद २५ तारीख को इसी क्षेत्र में पुलिस का बैच (bach) आया पुलिस ने चाहा कि जो वे चाहें वही आवें। मैंने २५ तारीख को चीफ मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी और कलेक्टर को भी लिखा। इसका चुनाव २७ तारीख को हुआ। २६ तारीख को एक पुलिस एस. पी. पुलिस गेंग को लेकर आता है। चुनाव होने वाला है और जिस रोज चुनाव होने वाला होता है उसी रोज १२ बजे पुलिस एस. एच. ओ० एक तार देता है जिसका मजमून इस तरह है:—

"I gave message yesterday to you to send men with arms and weapon carrier but not reached. Now information reached here that Sardar Gurdial Singh, M. L. A. threatened Congress Party to injure them. Therefore send armed forces and carrier to Jaluka panchayat. I am proceednig. "

यह १३बजे (१ बजे मध्यान्ह), पंचायत इलेक्शन शुरू होने से पहले, वहां से ४ मील दूर पदमपुर से यह तार दिया है। जब चुनाव शुरू हुए तो दूसरा एक्सप्रेस तार जिसका नम्बर ११५ है उसमें लिखा है।

" Due to serious condition in Jaluka Panchayat I am proceeding. "

यह वह देता है। मैं एक पंचायत के उम्मीदवार के तौर पर खड़ा होता हूं। इसमें मेरे विरोधी को १३ वोट आते हैं। अगर आप चाहें तो उसकी जांच करवा लें, १४ वां वोट नहीं। सारा गांव मेरी तरफ। इसी प्रकार एक गांव जिसमें एक के ३०० वोट और दूसरे के २०० वोट थे वहां पर तीन दफे नोटिफिकेशन हुआ और जब देखा कि मेरी पार्टी जीत रही है तो उसको पोस्टपोन कर दिया और आज वहीं पर नोमिनेशन किया गया है। यह सब प्रीप्लान्ड था।

"शेम, शेम की आवाज विरोधी दल की तरफ से।

आज यह एक आम प्रश्न बन गया है। लोग कहते हैं, हम कहा करते थे कि जनरल इलेक्शन में बेलट बोक्सेज़ से बेलट इधर से उधर हो गये, आज आप बतावें कि यह कैसे हुआ ? एक तरफ १० आदमी होते हैं वोट देने वाले और दूसरी तरफ सारा गांव; मगर फिर भी १० वोट वाला जीत जाता है। गांव वाले कहते हैं कि उस दिन हम वह कहा करते थे जो बात सच्ची थी या आज की बात सच्ची है। मैं इतना ही कहना मुनासिब समझता हूं कि जो चीजें गंगानगर में हुई शायद इस डेमोक्रेसी में कहीं नहीं हुई होंगी।

अब मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा जो लॉ एण्ड ऑर्डर से सम्बन्ध रखती है। वह मुझ से ज्यादा सम्बन्ध रखती है। मैं कई दिनों से सुनता हूं, देखता हूं कि मैं (कांग्रेस की) राजनैतिक पार्टी से आज कल मतभेद रखता हूं इसलिए मुझे जल्दी कत्ल कर दिया जाय। इस सिलसिले में काफी पत्र लिखे हैं। इस सिलसिले में मैं होम मिनिस्टर और आई. जी. पी. से जनवरी १०-१२ तारीख को, इस वक्त कोई तारीख याद नहीं आ रही है, गंगानगर में भी मिला और मैंने बताया कि

[श्री गुरुदयाल सन्धु]

एक आपके साथी, आपकी सरकार में बैठे मंत्री ऐसी कार्यवाही कर रहे हैं, वे मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं। मैंने उनको कहा, पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं यह देखता हूं और मुझे यह सुनने में आता है कि आपको कत्ल करने के लिए तीन मुरब्बा उन्होंने देने का वादा किया है। मैंने माननीय मंत्रीजी से जानना चाहा कि क्या आपने कोई मुरब्बा देने का वादा कर रखा है? उनका पत्र मेरे पास गया, इसकी मेरे पास कोई इन्फार्मेशन नहीं हैं। मैंने उन्हें लिखा कि मैं इसलिए ज्यादा चिंता में हूं कि मेरे खिलाफ इश्तहार लगाकर गवर्नमेंट होस्टल में बांटे गये थे। वह आदमी १६५० में किसी राजनैतिक संस्था, का मैं कांग्रेस की ही नहीं कहता किंतु किसी राजनैतिक संस्था का मेम्बर नहीं था, वही आज उनकी पार्टी का है और उसको दो मुरब्बा अलॉट किया इश्तिहार लगाने के लिए और इसीलिए चिन्ता थी कि यह तीन मुरब्बा वाली बात कहीं सच हो। इसलिए मैंने शोर मचाया। जहां हो सकता था वहां लिखा। ७-२-५५ को मेरा एक विरोधी, मेरा जानी दुश्मन (अश्रव्य), उससे फायर करवाया। मुझे लगा भी एक फायर दिन के दस बजे वह फायर हुआ, मेरे मकान से करीब दो सौ गज के फासले पर। अगर मेरी वाइफ बन्दूक लेकर नहीं पहुँचती तो जरूर मैं मार दिया जाता। आखिर दो बजे पुलिस पहुँची। पुलिस वालों ने बन्दूक बरामद कर ली। जिस जगह फायर हुआ निशान मिले, जिस जगह फायर लगा वह मिट्टी आदि देखी। लेकिन उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। ऐसा कहते थे कि मेरी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। मुल्जिम कहते हैं एक मन्त्री का नाम लेकर कि वह मंत्री हमारी पीठ पर है।

श्री हरीकृष्ण व्यास :— किसका नाम लेते थे?

श्री गुरुदयालसिंह सिन्धुः—चौधरी श्री कुम्भाराम।

("शेम, शेम" की विरोधी पक्ष से आवाज)

मैं ऐसा कहता हूं और जितने आदमी थे, हजारों थे, गंगानगर जिले के हजारों लायक आदमी थे, उन्होंने एक मेमोरेन्डम बना कर भेजा, मुख्य मंत्री जी को कि हमारे सामने ऐसा कहा गया कि इस आदमी को कत्ल कराने की साजिश है। इसके बाद ८ तारीख को डी. एस. पी. पहुंचा। डी० एस० पी० कहता है कि मामला सच है, लेकिन हम क्या करें, ऊपर से इशारा है और उस वक्त के एस० पी० की इज़ाज़त लेकर गिरफ्तार करेंगे। मुल्जिम एक मिनिट भी पुलिस से अलहदा नहीं हुआ। ८ तारीख को डी० एस० पी० गंगानगर पहुंचे और एस० पी० साहब रात की गाड़ी से बैठ कर ६ तारीख को सुबह बीकानेर डी० आई० जी० के पास पहुंचे। उनकी मन्जूरी लेने के बाद, तार देने के बाद, टेलीफोन पर बात करने के बाद एस० आई० को पदमपुर भेजा जाता है और कहा जाता है कि गिरफ्तार कर लो। ६ तारीख को वह गिरफ्तार हो जाते है। वहां के लोगों ने ऐसा महसूस किया, बुरी तरह फील किया। वहां के लोगों ने, बाबू मूलारामजी ने चौधरी साहब को चिट्ठी लिखी। पता लगा कि मुल्जिमोंकी जमानत के लिए करणपुर में चौधरी साहब पहुंच रहे हैं। उसी वक्त मीटिंग की और मेरे साथी मूलारामजी ने चौधरी साहब को चिट्ठी लिखी कि सब साथी बात करना चाहते हैं। इन्टर्व्यू का टाइम नहीं मिला, कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देना चाहिए था। उनकी गिरफ्तारी हो कर मुकदमा अदालत में पेश हो जाता, लेकिन चौधरी साहब का आना पोस्टपोन हो गया। २४

[श्री गुरुदयाल सन्धु]

तारीख को चौधरी साहब आना चाहते थे। १८ तारीख को यह मशहूर कर दिया गया कि २४ तारीख को चौधरी साहब आवेंगे और जमानतें होंगीं। मैंने कांग्रेस प्रधान को चिट्ठी लिखी, माननीय प्रधान मंत्री इन्डिया को तार दिये कि मेरे साथ ज्यादती होती है। सिर्फ मतभेद होने के कारण। मैंने सुखाड़ियाजी को पत्र लिखा, उनका जवाब मेरे पास है। उन्होंने लिखा कि मतभेद होने के कारण कोई ज्यादती नहीं होगी। २४ तारीख को चौधरी साहब करणपुर में पधारते हैं और उन मुल्जिमान की २५ तारीख को जमानतें होती हैं।

मैं अर्ज करूं कि डा० साहब पदमपुर को कहा कि मेरे लगी हुई है सर्टिफिकेट दो, तो कहा कि मैं शहादत नहीं दे सकूंगा क्योंकि मेरा महकमा चौधरी साहब के पास है। उसके पहले एक डाक्टर ने सरदार अजीतसिंह, मेरे एक साथी को सर्टिफिकेट दे दिया था। सर्टिफिकेट दिया था सुखजीतसिंह ने तो उसका तबादला कर दिया जुर्म लगा कर। रायसिंह नगर उनको चार्ज मिल गया और वे वहां दो-तीन दिन कायम रहे। फिर पता चला कि उनको तो सजा देना था, रायसिंहनगर जैसी जगह पर क्यों लगा दिया। ट्रान्सफर करके गंगानगर में रिलीविंग में घूम रहे हैं। डाक्टर की हिम्मत नहीं हो सकती थी कि ऐसी कार्यवाही करें कि जिससे मुझे फायदा पहुंच जाय। मैं इतना ही अर्ज करना काफी समझता हूं। मैंने देखा कि २४ तारीख को मेरे एक रिश्तेदार सरदार मस्तानसिंह, एक्स पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर, बीकानेर स्टेट, ने कहा कि आपको ऐसी कार्यवाही नहीं करना चाहिए। तो २५ तारीख को यह बात आउट हो गई कि सरदार मस्तानसिंह गुरुदयालसिंह की मदद कर रहा है। तो उनको चेलेन्ज मिल गया। मैं राजस्थान असेम्बली में जा रहा हूं। मेरे बच्चों को यहां छोड़ना पड़ा, शायद किसी को कत्ल न कर दिया जाय। मेरे घर के चारों तरफ घेरा है। कचहरियों में जाते हैं तो सरदार मस्तानसिंह को गालियां देते हैं और कहते हैं कि हम जिन्दा नहीं छोड़ेंगे। ऐसी हालत में यह लॉ एन्ड ऑर्डर है।

मैं बाकी मामलों को बजट के वक्त में अर्ज करूंगा लेकिन एक और अर्ज कर देना चाहता हूं और वह है लेण्ड रेवेन्यु के बारे में। लेण्ड लैस टिनेन्ट्स को जमीनें अलॉट की जा रही है, गंगानगर जिले में। ये किस तरह अलॉट की जा रही है? एक दफा मैंने अर्ज किया था कि पांच तहसीलों को दरख्वास्तें आने में पांच तारीख तक ६ लाख रुपया रिश्वत का चल चुका। एक आदमी तहसील पदमपुर में है जिसका काम है कि लोगों से दरख्वास्तें लेकर अपने पास रखे। १६ तारीख को हिसाब किया और उसके पास १६ हजार रुपये रिश्वत के पहुँचे। सिर्फ एक आदमी, जिसके पास दरख्वास्तें संभाल कर रखने का काम था उसका यह हाल है। लेता क्या था? एक दरख्वास्त पर एक रुपया, दो रुपया। अर्जी नवीसों ने कितना कमाया? एक दरख्वास्त पर आठ आने के टिकट लगाना चाहिए था हलफनामे पर, दरख्वास्तें तो सादे कागज पर होनी चाहिए थीं। क्या हुआ, एक रुपया का स्टाम्प कर दिया और कह दिया कि खजाने में स्टाम्प नहीं हैं। पहले ही दो-तीन अर्जीनवीसों ने खरीद लिये। १) रुपया वाले स्टाम्प का दो रुपया देना पड़ा। इस तरह मैंने देखा कि जिसको अलॉटमेंन्ट हो रहा है, अलाटमेन्ट में यह हुक्म था, कमेटी ने फैसला किया था कि कोई आदमी अपनी गिरदावरी शामिल नहीं करेगा बल्कि लिख देगा कि मेरी गिरदावरी किस जगह है, उनका काम है तफतीश करना।

[श्री गुरुदयाल सन्धु]
तहसीलदार ने हुक्म दिया कि गिरदावरी की नक्ल लगावे और उसके लिए एक आदमी को दस रुपये ले लेकर १००) रु० देने पड़े।

यह हालत है हमारे रेवेन्यु विभाग की। अगर मैं पुलिस के मुतल्लिक अर्ज करूं तो उसकी एक लम्बी चौड़ी कहानी है, इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कह देना काफी समझता हूं कि गंगानगर के जितने भी थाने हैं, पुलिस स्टेशन्स हैं उनका ऑक्शन होता है, उनका सौदा होता है। एक सब इन्सपेक्टर कहता है कि मैं इस थाने के पांच हजार देता हूं दूसरा उसके लिये ६ हजार लगाता है; इस तरह से वह थाना ६ हजार में ऑक्शन होता है। अगर इसमें आपको झूंठ मालूम हो तो मैं ऐसी मिसालें पेश कर सकता हूं। जालूका थाने के थानेदार का महज तबादला इस कारण हुआ कि वह थाने के लिये इतना रुपया नहीं दे सकता था, उसकी जगह दूसरा थानेदार आया।

इन लफ्जों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हालत हमारे राजस्थान में हो रही है उसको देखते हुए मैं राजप्रमुख को थैंक्स देने के मोशन में अपने आपको शरीक नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस मोशन का विरोध करता हूं।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

श्रीमती यशोदादेवी—अध्यक्ष महोदय, दो दिनों से श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण पर चर्चा हो रही है। इस सम्बन्ध में मैं भी दो शब्द सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं।

डाकुओं के विषय में मेरे माननीय सदस्य श्री चांदमलजी ने खुलासा कर दिया है कि कितने प्रकार के डाकू होते हैं।

राजप्रमुख ने अपने भाषण में कृषि के सम्बन्ध में जो कुछ जिक्र किया है उस पर मैं कुछ बोलना चाहती हूं। कृषि-सुधार के लिये, किसानों को राहत देने के लिए इस भाषण में कुछ जिक्र किया गया है। जिस प्रकार माननीय सदस्य ने बताया कि डाकू तीन प्रकार के होते हैं उसी प्रकार मैं भी यही अर्ज करना चाहती हूं कि किसान भी तीन प्रकार के होते हैं। मैं राजप्रमुख के भाषण से यह नहीं समझ सकी कि इन तीन प्रकार के किसानों में से किस प्रकार के किसान को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष, एक तो वह किसान है जो देहली में बैठ कर अपने यहां बांसवाडा जिले में या कहीं भरतपुर या अन्य किसी स्थान पर खेती का काम करवाता है या कोई किसान जयपुर में बैठा है और डूंगरपुर में वह कृषि–सुधार का कार्य करवाता है।

दूसरा वह किसान है जो २४ घंटे अपने खेत में अपने खून का पसीना कर परिश्रम करता है। इन किसानों में से किस–किस को राजप्रमुख के भाषण के अनुसार ज्यादा फायदा होगा।

माननीय अध्यक्ष एक वह किसान है जिसकी राहत के लिए हजारों और लाखों रुपया हमारी

[श्रमती यशोधा देवी]

सरकार द्वारा मन्जूर हुआ है, जिसको बजट में प्रस्तुत किया जायगा और उसमें यह बताया जायगा कि फलां-फलां डिविज़न में इतना हज़ार रुपया खर्च हुआ हैं। वास्तव में वह रुपया खर्च हुआ है या नहीं, इससे उन किसानों को राहत मिली है या आगे मिलेगी; यह हमें देखना है। मेरा जहां तक खयाल है सरकार ने इस ओर कभी गौर से देखा नहीं है और न मेरे वे माननीय सदस्य जो उस क्षेत्र से आये हैं उन्होंने ही देखा कि वहां के किसान की क्या हालत है।

भील क्षेत्र के किसान की क्या हालत है? जिन किसानों के तीन-तीन और चार-चार मील की दूरी पर झोंपड़े हैं, जिनके आस-पास पानी का पता नहीं, उस क्षेत्र में पानी की व्यवस्था के लिए सरकार ने जो पैसा मन्जूर किया है उस पैसे का दुरुपयोग हुआ है, इसका मैं आपके सामने जिक्र करना चाहती हूं। अभी कुओं की तकावी के लिये जो पैसा मन्जूर किया गया वह किसको मिला, इस बारें में मैं कुछ प्रकाश डालना चाहती हूं। फरवरी और मार्च के महीने में यह पैसा मंजूर हुआ, तहसील से कलेक्टर का आॅर्डर निकलता है कि फार्म भरे जायं और कुओं के लिये तकावी-ऋण लिया जाय। यह समय वह है जब कि किसान अपनी खेती में लगा रहता है। वह उस समय व्यवस्थित फॉर्म भर कर पैसे मन्जूर नहीं करवा सकता। इससे होता यह है कि वह पैसा लेप्स हो जाता है और जो पैसा दिया भी जाता है उसमें पक्षपात होता है। मुझे यह कहना तो नहीं चाहिये, लेकिन जब उधर बैठने वाले सदस्य यह कहा करते हैं कि विरोधी पक्ष के लोगों की आलोचना करने की खाली आदत सी होती है' तो मैं उनसे यह निवेदन कर देना चाहती हूं कि हमारी सरकार की नीति और कार्य करने का जो ढंग है वह पक्षपात पूर्ण है। जब तक वह नहीं मिटेगा, विरोधी पक्ष को उनकी आलोचना करने का मौका मिलता रहेगा। उस क्षेत्र के जो कांग्रेसी सदस्य हैं वे किसानों को कहते हैं कि हम तुम्हारे फॉर्म भरवाते हैं और उस फॉर्म भरवाने के लिए एक एक फॉर्म के ऊपर चार-चार पैसे लेकर फॉर्म भरे गये हैं। वहां के एक कांग्रेसी सदस्य ने एक एक फॉर्म के पीछे पांच-पांच रुपया तक लिया है, कुओं की तकावी के लिये फॉर्म भरवाने के लिये। फॉर्म भरवाने के बाद यह भी नहीं कि जिनसे पांच रूपये लिये गये उन सब के फॉर्म मन्जूर हो जायं। मेरे पास एक रिपोर्ट आई है। वे लोग यह करते हैं कि उनमें से कुछ लोगों के फॉर्म मन्जूर करवा देते हैं और बाकी के फॉर्म को फाड़ दिया जाता है। पांच-पांच रूपये लेकर भी फॉर्म फाड़ दिये जाते हैं। तीन-तीन, चार-चार बार तहसीलों में जाने के बाद भी उनको सारा पैसा नहीं मिलता। मैंने खुद ने कुशलगढ़ तहसील में देखा है कि जहां के किसानों ने २० कुए अपने हाथ से खोदे, जिसके अन्दर पानी आ गया। लेकिन जिन किसानों को खेती बनाने के लिये पैसे की आवश्यकता है उन किसानों को पैसा नहीं मिला, उसकी बजाय एक ऐसे किसान को पैसा मिला जिसने कुआ नहीं खोदा और उसे कुए की मन्जूरी के पूरे पैसे दिये गयें; यह कह कर दिये गये कि तुमने कांग्रेस का फॉर्म भरा। बाकी किसानों को इस लिये नहीं दिया गया कि वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी या किसान मजदूर पंचायत के मेम्बर हैं।

तो माननीय अध्यक्ष, हमारी राजस्थान सरकार की नीति यह रही और किसानों के साथ इस तरीके से सौतेली मां जैसा बर्ताव रहा तो गांव के किसान ऊंचे नहीं उठ सकते और गांवों की खेती हरी-भरी नहीं हो सकती और जो स्वप्न इस सरकार के, हमारे सामने राजप्रमुख ने बताये हैं वह स्वप्न

[श्रीमती यशोधा देवी]

हज़ार वर्ष तक भी पूरे नहीं होंगे। अगर हमारी राजस्थान सरकार को गांवों को ऊँचा उठाना है और गांवों की खेतीं को हरा-भरा बनाना है तो किसानों को खुले हाथों खेत सुधारने के लिये तकावी बांटनी पड़ेगी और लगान में सुधार करना पड़ेगा। इसके बाद किसानों से सरकार पूरा लगान वसूल कर सकती है। यह नहीं करेगी तो यह स्वप्न आपका पूरा नहीं होने वाला है। सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिये। मैं कहती हूँ कि आपकी तरफ के जो जिम्मेदार सदस्य हैं, आपकी आंखों में धूल भोंकते हैं, आपकी आंखों पर पट्टी बांधते हैं और कहते रहते हैं कि हमारे यहां अच्छा काम हो रहा है, आप हमें इसी तरह से राहत देते रहिये। ऐसा होने पर सरकार जरूर बदनाम होगी। यदि सरकार को बदनामी से बचाना है तो पार्टी वालों की बात मत सुनिये। जो लोग किसी पार्टी के नहीं है और जो निष्पक्ष हैं उनको वहां भेजिये और गांवों में टापे-टापरे में भेजकर सही खबर मंगाइये कि हमने अमुक जगह इतने जो पैसे दिये वे उन्हें मिले या नहीं? तभी आपको सही हालात मालूम होंगे। विरोधी दल हमेशा सरकार को रास्ता दिखाने वाला होता है। अगर आप अपनी नीति बदल लें और किसानों के साथ अच्छा व्यवहार करें, सच्ची सहानुभूति दिखावें तो हमको कोई बात के स्वप्न नहीं आते। कोई सींग हमारे नहीं लगे हैं कि हम बार-बार आपको मारते रहें। आप भील इलाके में आइये, वहां पानी की आवश्यकता है।

आपने जोधपुर के जवाई बन्ध का जिक्र कर दिया, कोटा के चम्बल बांध का जिक्र कर दिया, कोटा की तरक्की कर दी किन्तु आप इस भील इलाके को भूल गये। बांसवाड़ा या उदयपुर डिवीज़न के किसानों का जिक्र नहीं किया है। आज चम्बल योजना भील एरिया में सफल होने वाली नहीं है। आज पंचवर्षीय योजना में जो एक-एक गांव में कम से कम एक कूँआ बना दिया जाय और छोटे-छोटे नालों की योजना जो हमने कई बार आपके सामने रखी है उसको पूरा किया जाय, अगर छोटे छोटे नाले बन्धवा दिये जायं और किसानों का पन्डोश (मेड) बांधने के लिये खुले हाथों पैसे दिये जायं तो आप देखेंगे कि दो साल में ही किसानों के खेत, गांवों के खेत कितने हरे-भरे हो जाते हैं। आज शहरों की जनता गांव वालों पर निर्भर है, न कि गांव वाले शहर की जनता पर निर्भर है। वहां जब गांवों की वह हालत है तो आप बताइये कि शहरों की जनता कैसे पनप सकती है? आपने विकेन्द्रीकरण किया है। वह विकेन्द्रीकरण हो रहा है जयपुर में, जोधपुर में और बड़े बड़े शहरों में। आज गांव से तमाम किसानों का शोषण होकर जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में पैसा इकठा हो गया है। यह केन्द्रीकरण जनता बर्दाश्त नही करेगी, काश्तकार बर्दाश्त नहीं करेंगे, जब तक कि सही मायने में विकेन्द्रीकरण नहीं होगा और आप ऊपर से यह स्वप्न देखते रहेंगे तो माननीय अध्यक्ष, मैं जरूर यह कहना चाहती हूँ कि यह बात आज नहीं तो कल, एक वर्ष बाद नहीं तो दो वर्ष बाद, दो वर्ष बाद नहीं तो तीन वर्ष बाद, वही स्वप्न देखना पड़ेगा कि तैलंगाना की तरह यहां जरूर क्रान्ति भड़केगी।

यह है कृषि सुधार। मैंने आपको तीन प्रकार के किसान बताये हैं। एक वे जो दिल्ली में बैठे हैं और बांसवाडा में खेतीं करते हैं और सरकार के साथ रिश्ता रखकर लाखों रुपया कृषि-सुधार के नाम पर मन्जूर करवा लेते हैं। दूसरे वे किसान हैं जो सिर पर छाता रखकर जाते हैं और सरकार से

[श्रीमती यशोधा देवी]

कुछ इमदाद हासिल कर लेते हैं। तीसरे वे किसान हैं जो रात-दिन अपने खेतों में अपना खून पसीना बहाते हैं. परन्तु उनको सरकार से कुछ नहीं मिलता। आप वहां जाकर देखें कि उन लोगों को पसे की कितनी आवश्यकता है, खेती को सुधारने के लिये उनको सरकारी सहायता की कितनी आवश्यकता है ? माननीय अध्यक्ष. यह पक्षपात की नीति सरकार छोड़ दे कि जिस डिवीज़न का जो मंत्री हो, होता आया है अब भी होते रहेंगे और होता रहा है; मुझे किसी मंत्री-मंडल से द्वेष नहीं है माननीय–अध्यक्ष, फिर भी किसी सरकार को जनता का प्रिय बनना है तो बिना पक्षपात के जिस डिवीज़न के मंत्री हों उस डिवीज़न को वह छोड़ दें और दूसरे डिवीज़न में जाकर देखें कि वहां के किसानों की हालत कैसी हैं और उनको राहत पहुंचाने की कोशिश करें। कोई मंत्री महोदय ऐसा करेंगे तो जनता अपने आप उनको देवता समझेगी और सही मायने में गणतंत्र राज्य कायम हो जायगा। आज आपके ऊपर बराबर छींटाकशी होती है। जब जनता के साथ पक्षपात होता है। तो इस प्रकार के एतराज़ात उटाये जाते हैं। कोई सदैव किसी कुर्सी पर कायम नहीं रहता; अतः जनता के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिये। लाखों करोड़ों रुपये सरकार ने जो मन्जूर किये हैं उसे पानी की तरह बहाया जाता है और काम कुछ भी नहीं होता। एक किसान के ३०० रुपये मन्जूर होते हैं तो उस किसान के हाथ में वे पैसे जाने चाहियें, बाकायदा उस किसान के हाथ में जाने चाहिये पर होता यह है कि हमारे गांव के भाई उसके एजेन्ट बन जाते हैं और ३०० रुपये मंजूर हो जाते हैं तो उस किसान् को कह देते हैं कि तू अपना काम शुरू कर दे। यह किसान के ऊपर निर्भर रहना चाहिये कि वह मज़दूरों को मजदूरी चार आना, आठ आना या बारह आना दे लेकिन एजेन्ट साहब बीच में पड़कर मज़दूरों को आठ-आना मज़दूरी देकर और बारह आने के हिसाब से मज़दूरी लगाकर चार आना अपनी जेब में डाल लेते हैं। आज इस प्रकार की अन्धाधुन्धी चल रही है कि इस अन्धाधुन्धी को दूर करने के लिये हमारी सरकार ध्यान दे और बिना पक्षपात के आदमी जो किसी पार्टी के नहीं हैं उन्हें हर क्षेत्र में भेजकर निगाह करवाये कि क्या वास्तव में किसी सड़क पर या कुए पर खर्चा हो रहा है और इसमें इस तरह की बेजा कार्यवाहियां तो नहीं हो रही हैं। यह है कृषि सुधार के लिये ध्यान देने की बातें।

माननीय अध्यक्ष, में यह अर्ज करना चाहती हूं कि राजप्रमुख ने महिलाओं के लिये कोई जिक्र नहीं किया है। मैं मानती हूं कि बड़े-बड़े शहरों में कॉलेज खोलने के लिये उसके ऊपर काफी जोर दिया गया है पर उस क्षेत्र के लिये, जिसके बारे में मैंने पिछली साल भी जिक्र किया था जहां कि वास्तव में शिक्षा की आवश्यकता है उस क्षेत्र की तरफ अभी तक किसी भी सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है (समय समाप्ति सूचक घंटी) पांच साल राजस्थान को बने हुए हो गये हैं। हर साल मिनिस्ट्री बदलती है, मगर किसी भी मिनिस्ट्री के किसी मिनिस्टर ने वहां शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया है। वहां छोटी–छोटी स्कूलें खोली गई हैं। उनके बजाय आदिवासी क्षेत्र में दो बोर्डिंग हाउस नहीं खोले गये। इनके कायम करने के लिए सरकार के सामने रिपोर्ट पेश की गई। उसमें सरकार का, माननीय अध्यक्ष, इतना खर्चा नहीं होता है जो कि छोटे छोटे स्कूलों में उसको खर्चा उटाना पड़ता है। तो उस क्षेत्र के आदिवासियों के लिए बोर्डिंग हाउस का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित होना चाहिए।

चौधरी श्री मोतीराम-माननीय अध्यक्ष, मेरे भाई श्री गुलाबचन्दजी कासलीवाल ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव श्रीमन् राजप्रमुख के लिये रखा है में उसका समर्थन करता हूं और इस सम्बन्ध में यह अर्ज करता हूँ कि राजस्थान बनने के बाद आज जो राजस्थान का नक्शा है वह दूसरी तरह का है। इस राजस्थान के अन्दर कई राज्य थे, जिन राज्यों के अन्दर, जो आज एक थानेदार की तनख्वाह है वह आई० जी० पी० की तनख्या होती थी। आज इस विशाल राजस्थान में सब कर्मचारियों को एक जैसा वेतन मिलने लगा है। एक अच्छा तगड़ा सा राज्य बनाया है। उस समय हर तरह की उसके अन्दर कमियां थीं और बहुत से किसानों को कष्ट था। बहुत तरह से कष्टों को दूर करके आज किसानों और हरिजनों को बहुत ज्यादा राहत मिली है। इसलिए मैं श्रीमन् राजप्रमुख को उनके भाषण के लिए धन्यवाद देता हूँ।

इसके साथ यहां सदन में एक खास तरह का वातावरण बन गया है। व्यक्तिगत आक्षेप इस सदन में आ गये हैं। १०० बार मना किया जा चुका है, मगर परम्परा यहां ऐसी डल चुकी है, इसलिए मुझे उसका जवाब देना जरूरी है।

अध्यक्षजी, सबसे पहले तो यह है कि एक किसान पर अटेक होता है। वह किसान सदियों से ही इन राज्यों के अन्दर दबा हुआ था। आज वह एक चूहे के बिल में से, जैसे कि एक चूहा मुंह निकालता है, आज इस डेमोक्रेसी के अन्दर वह किसान मुंह निकालना चाहता है; किन्तु चूहा कमज़ोर होता है इसलिए चूहे पर सब दुनियां टूट पड़ती है, चीलें भी टूट पड़ती है तथा और भी जानवर टूट पड़ते हैं। इसी तरह वे उस किसान को घेरे पड़े हैं। वह पसन्द नहीं करते हैं किसान का आगे बढ़ना, यह कारण है इसका। मैं अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूँ कि जिस किसान के पास एक झोंपड़ी भी नहीं है उसके जिम्मे यह इल्जाम लगाया जाता है कि वह भूमिदार बन रहा है और जो लोग अपनी औरतों के नाम से जमीन तरमीमि कराके, जो लोग मकान किराये से ५००) रू० माहवार लेते हैं आज वे कॉम्युनिस्ट बन बैठे हैं। एक दूसरे सिद्धान्तवादी की बात करता हूँ, वे सिद्धान्तवादी मेरे साथी हैं जिन्होंने पिछली राजस्थान सरकार में करीब पौने दो साल तक राज्य किया था। हम जानते हैं कि किसानों के साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया ? आज वह किसानों के जिम्मे तरह तरह के इल्जाम लगाते है, और क्रान्तिदूत का नाम लेते हैं। में क्रान्तिदूत के जीवन को बताना चाहता हूँ कि क्रान्तिदूत किन लोगों का है। यह उन साथियों का है जो हमारे बीकानेर महाराज ने प्रजा परिषद् के नाम से वहां संस्था चलाई थी। उसके अन्दर उन साथियों को वेतन देकर प्रजा परिषद् का मेम्बर बनाया गया था और प्रजा परिषद् के मेम्बर बनाकर जेल भेजते थे और प्रजातन्त्र के खिलाफ वोट देते थे। ये वह लोग हैं। कांग्रेस के राज्य में उसके बाद कॉंग्रेस से वे निकाल दिये गये। उन लोगों को उसने कोई महत्व नहीं दिया, तो उन्होंने क्या किया ? जैसा जैसा उनका स्वभाव था, जैसे जैसे उनके कार्य जनता के सामने आये तो जनता ने उनको निकाल दिया है। जो लोग राज्य करते थे, किसानों को चूसते थे, किसानों का खून पीते थे, उन लोगों ने उनको बढ़ाया। यह लोग ऐसे हैं। उन्होंने सोचा कि अगर हम हमारी आवाज को पहुंचा नहीं सकते हैं तो किसान और हरिजन आगे आ जावेगें। उन लोगों ने इसको बनाया है। वे क्या हैं ? में आपसे कहूँगा कि जो गरीब सबसे ज्यादा सामने आना चाहता है उसको खत्म करने के लिए इन लोगों ने यह ढोंग रचा है।

[चौधरी श्री मोतीराम]

उन्होंने पच्चीसों इल्जाम लगाये हैं और कहा है कि जिन लोगों ने डाका डाला है वह कुम्भारामजी के साथी हैं। इसके बाद में २५ वां इल्जाम यह था कि कुम्भारामजी की औरत है वह मुसलमानी है। मैं जानता हूँ कि जब कुम्भारामजी ६ साल के थे और उनकी स्त्री ६ साल की थी उस वक्त शादी हुई थी। उसका बाप जाट, उसकी माँ जाटनी, उसका दादा जाट है (हँसी) तो फिर कैसे वह मुसलमानी हुई। यह क्रान्तिदूत की मान्यता है। उसको मान्यता देते हैं इस सदन के लोग तो मुझे अफसोस है कि इसको हम सदाचार मानते हैं, उनको ऊँचा मानते हैं, हम अच्छा मानते हैं, और उनकी बात कहते हैं।

राजाओं के बाद प्रजातन्त्र आया और प्रजातन्त्र होने के बाद यह किया कि वह कांग्रेस के वोट भरते हैं, कांग्रेस के विरोध में काम करते हैं। कांग्रेस राज्य आया तो उनकी पार्टी ने दूसरे को लीडर चुन लिया तो उन्होंने उनका विरोध किया और ७ आदमी व्यासजी की सत्ता को तोड़ने के लिए विरोधी दल में जा पहुँचे। व्यासजी ने मनाया तो कांग्रेस में आये। इस तरह के लोग तो सदाचारी माने जाते हैं, वे एक अच्छे भले आदमी माने जाते हैं। अफसोस है कि इस तरह के आदमियों को इस सदन में मान्यता है।

एक भाई गंगानगर से आये हैं वह बहुत सीधे हैं। किसी टाइम पर वे सरदारजी चाहते थे कि उन्हें डिप्टी मिनिस्टर लिया जाय और उन्हें नहीं लिया..................

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या आप किसी हाई कोर्ट से जांच करवाने को तैयार हैं? मैं इसको चेलेन्ज करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—मैं सदन के माननीय वक्ताओं से यह प्रार्थना करूंगा कि राजप्रमुख के भाषण पर जैसा व्याख्यान होता है उसको उसी स्तर पर रखें और व्यक्तिगत स्तर पर न आयें, जिससे कि सदन का वातावरण क्षुब्ध हो।

चौधरी श्री मोतीराम—यह मेरे लिए ही है या दूसरों के लिए है। जब लोगों ने यह कहा तो उस वक्त आप बोले नहीं।

श्री अध्यक्ष—सब लोगों के लिए है। मैं आपको यह बतला रहा था कि न आपके साथ पक्षपात हो और न दूसरे के साथ। कोई दूसरा सदस्य एक गलती करता है तो वह गलती आपको नहीं करना चाहिए।

चौधरी श्री मोतीराम—मैं "गलती" नहीं कह रहा हूं। मैं सदन की जानकारी के लिए कह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष—आप अपना भाषण दीजिये।

चौधरी श्री मोतीराम—अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि पंचायतों के चुनाव अवै-

[चौधरी श्री मोतीराम]

धानक हैं। श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह सदन की जानकारी के लिए अर्ज कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस में वे लोग हैं जो निहत्थे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास में भूमि नहीं है, जो भूखे और नंगे हैं, वे कांग्रेस में हैं। जो लोग विरोध में हैं वे सारे जमींदार है, लेन्डलॉर्डस हैं, जागीरदार हैं। (हंसी) आप हंस लीजिये फिर में बोलूंगा।

तो इन लोगों की जिम्मेदारी है। कांग्रेस से नाराज रहनेवाले यही लोग है। ये कांग्रेस से नाराज क्यों हैं? इन्होंने ही पंजाब से लोगों को बुला २ कर अपने चकों में बैठाया और गरीब किसानों और हरिजनों को हराया। इस तरह के हैं इनके कारनामे। कांग्रेस के टिकट पर कोई नहीं जीता है। कांग्रेस ने किसी को टिकट नहीं दिया है। वे लोग अपने ही बल बूते पर जीते हैं। कांग्रेस ने उनको मदद नहीं दी है। इस पर भी मेरे साथी सरदारजी कांग्रेस से नाराज होते है। उन्होंने कोई पंचायत नहीं छोड़ी जहां पुलिस और पंचायत के अधिकारियों को अपने जोर से दबाकर अपना काम नहीं बनाया हो। ये हैं सरदारजी के कारनामे। मैं यह अर्ज करूंगा कि सरदारजी ने हर तरह के उपाय काम में लिये।

(कई सदस्यों का एक साथ बोलना)

अध्यक्षजी, मेरे लायक दोस्त सरदारजी पहले कांग्रेस में थे और उनके कहने से कमेटी बनाई और उस कमेटी में सरदारजी ने पंजाब से लाकर जो नाज़ायज सरदार थे उनको रखा (हंसी)...

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरदारजी कौनसे? झुन्झुनूवाले तो नहीं हैं।

चौधरी श्री मोतीराम—मैं यह कह रहा था कि......

श्री गोपीलाल यादव—जरा धीरे बोलिये तो सुनने में आ जायगा। जोर से आप बोलते हैं तो सुनाई नहीं देता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ये सरदारजी कहां के हैं, कहीं झुन्झुनू के तो नहीं हैं?

चौधरी श्री मोतीराम—सदन की जानकारी के लिये ये बातें बता रहा हूं। लोगों को यह महसूस होता है कि ये बातें क्यों करते हैं? इसलिये कई लोग बराबर हंस रहे हैं और यह चाहते हैं कि मैं नहीं बोलूं तो अच्छा हो, लेकिन मेरी आदत ऐसी है कि में डरने वाला नहीं हूं। मेरे दोस्त ने पंजाब के हकीकी भाई-बेटों के नाम से काफी गड़बड़ की है। उनके ये कारनामे कमेटी के रेकॉर्ड में मौजूद हैं।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या आप इसकी जांच कराने के लिये तैयार है? में आपका चेलेन्ज मन्जूर करता हूं। मैं आज तक किसी नामजद कमेटी का मेम्बर नहीं रहा।

चौधरी श्री मोतीराम—अध्यक्ष महोदय, मैं अभी दो-तीन मिनट में खत्म करे देता हूं। वह जमीन सरदार साहब ने फरजी नाम से ले ली। पिछले साल भी उन्होंने काफी गड़बड़ी की। ये हैं सरदारजी के कारनामे। सरदारजी बहुत कुछ गड़बड़ियें करते ही रहते हैं। सरदारजी के पास मुसलमान रहते हैं जिनके पास ३००० हजार गाये–भेड़ें हैं; ४०००० रुपयों की जिनसे आमदनी है। पंचायतों के चुनावों में......

श्री अध्यक्ष—आप राजप्रमुख के भाषण पर बोल रहे हैं या पंचायतों के चुनाव पर ?

चौधरी श्री मोतीराम—मुझे १ मिनिट और बोलने दीजिये।

श्री कपिलदेव—इन्हें एक मिनिट और बोलने की इजाज़त दीजिये।

चौधरी श्री मोतीराम—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन की जानकारी के लिये कुछ बातें बताना चाहता हूं जिनसे सरदारजी के कारनामों पर रोशनी पड़ेगी। सरदारजी के हकीकी भाई हैं वे इनके साथ ही में पहले काम करते थे। वे ५ भाई आज ५ मुरब्बों के मालिक हैं और अकेले सरदारजी १० मुरब्बों के मालिक नाज़ायज़ तौर पर हो गये।...

श्री हरिकृष्ण व्यास--On a point of order, Sir, I draw attention to Rule 102 part (V) where it is specifically laid down that while making a speech no Hon'ble Member shall make a personal charge against a Member. I will request the Chair to exercise the right of the Chair and prevent the Hon.'ble Member from making personal charges against another Member.

चौधरी श्री मोतीराम—अध्यक्षजी, मेरी बात सुन लीजिये (हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे पॉईन्ट ऑफ ऑर्डर का कोई जबाब नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—वे इसको समझ गये हैं।

चौधरी श्री मोतीराम—इसलिये मुझे कहना पड़ता हैं। आप नहीं बतायेंगे तो मैं बता दूँ। सन् ३७ से लगाकर आज तक चचा–भतीजों के बीच हकों की लड़ाई चल रही है और उन पर केस चलता है; जो कुंभारामजी पर इल्जाम लगाये जाते हैं। कुंभारामजी पर तो झूठे ही इल्जाम लगाये जाते हैं। सरदार साहब के साथ हर तरह से रियायत होती जा रही है। यह कहा जाता है कि सरदारजी के गोली लगी हैं। सरदारजी के गोली लगे और सदन में आकर बैठ जांय, भला क्या यह अजीब बात नहीं है ? जिनके तीन–तीन गोली लगे वे इस तरह से आकर बैठ जांय ? जिन गरीबों के गोली लगी है उल्टा उन्हीं का चुनाव रद्द करवाया और पुलिसवालों ने उन गरीबों की सुनवाई तक नहीं की और उल्टा गरीबों पर ज्यादतियां की जाती हैं। जिनके हकों का झगड़ा है, जमीन का झगड़ा है सगे भतीजों के साथ; वे ही कुंभारामजी पर इल्जाम लगावें, यह कहाँ अक्लमन्दी है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—यह जो मेरे विरूद्ध इल्जाम लगाये गये है क्या उसकी जांच के लिये बन्दोबस्त किया जायगा ताकि पता लगे कि श्रीमानजी कहां तक सच बोलते हैं ?

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर बोलता हुआ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमन् राजप्रमुख ने इस सदन में हिन्दी में भाषण देने की जो नई परम्परा चालू की है उसके लिये वे अवश्य बधाई के पात्र हैं। यह मानते हुए भी कि ऊपर से इस प्रकार की परम्परा चालू की गई है, मैं आपके जरिये सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हिन्दी को अपनाया जाय। यह जो नारा है यह केवल दिखावा मात्र है। इसके बारे में मैं सदन के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट पास होने के बाद जागीर कर्मचारियों को नौकरी में लेने का मसला सरकार के सामने आया। कुछ इलाकों के अन्दर यह मसला मुमकिन है सही ढंग से हल हो गया हो किन्तु जागीर इलाकों के कर्मचारियों की जो दुर्दशा जयपुर इलाके में है उसकी मुझे काफी जानकारी है और उन पर किस प्रकार का अन्याय और ज्यादतियां हो रही हैं उनको मैं सदन के सामने इस समय रखना चाहता हूं।

इस सिलसिले में मैं सरकार का जो एक हिन्दी का नारा है उसके बारे में भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। वह बात यह है कि जागीरी कर्मचारी जिन्होंने सरकार के पास दरख्वास्तें पेश की हैं और जिनके लिये जाने का मामला है, उनके बारे में यह हुआ है कि हमारे जयपुर डिवीज़न में पहले तो सरकार ने बहुत ज्यादा तादाद में आदमियों को रिजेक्ट कर दिया है और जो थोड़े बहुत आदमी रहे हैं उनको कहीं लगाने के लिए कमिश्नर महोदय या कलेक्टर महोदय ऑर्डर कर देते हैं; तो एक हमारे जयपुर में एस. डी. ओ. साहब अंग्रेजी परस्त आकर बैठ गये हैं, जो यह कह कर हर एक को डिस्क्वालिफाई कर देते हैं कि, "तुम अंग्रेजी नहीं जान सकता और तुम नहीं लिया जा सकता।"

वह सरकार जो श्रीमन् राजप्रमुख से हिन्दी में भाषण दिलवाती है उसी सरकार के नीचे काम करने वाला एक अधिकारी इस प्रकार के पत्र भेजता है कि जो अंग्रेजी नहीं जानता है उसको सरकारी नौकरी में नहीं लिया जाय। यह तो हमारी सरकार की अंग्रेजी को हटाकर हिन्दी को अपनाने की नीति का विश्लेषण है। मैं ऐसे आदमियों के नाम पेश करूंगा कि जिन्होंने उम्र में कभी जागीरदार की नौकरी नहीं की, वे लोग यह स्वर्ण अवसर प्राप्त करके जागीरदार से सार्टिफिकेट लेकर सरकारी नौकरियों में लग गये। दो आदमियों का विचित्र ढंग का उदाहरण पेश करूंगा। एक तो श्री अमृत-लाल जैन नामक व्यक्ति हैं जिन्होंने उम्र भर मुख्त्यार आम का पेशा जलेबी चौक में किया है जिसे हर एक एम. एल. ए. जो जयपुर के हैं, जानते हैं। आपने जो यहां से नजदीक शाहपुरा ठिकाना है, वहां के रावजी युवक हैं, बच्चे हैं उनके यहां ६ महीने से नौकरी कर ली और उनसे सर्टिफिकेट ले लिया। हालां कि सरकार के शुरू से आदेश हैं कि जो ठिकाने का ३ साल से नौकर हो उसे लिया जाय। इस ठिकाने के लिये प्रमाण है कि इस ठिकाने को कोर्ट ऑफ वार्ड्स से रिलीज़ हुए एक साल हुआ है। उनकी अर्जी पेश होती है तो कहते हैं कि तहसीलदारों में ले लिया जाय। इस पर वे कहते हैं कि तहसीलदार की जगह तो मेरे लिये ठीक नहीं, मुझे एस. डी. ओ. बनाया जाय।

जिन लोगों ने उम्र भर जागीरों में काम किया, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है वे ठिकानों के नौकर तो दर दर भटक रहे हैं क्योंकि उनकी पहुंच नहीं है और जिनकी पहुंच है वे सरकार को

[श्री मानसिंह महार]

धोखा देकर सरकारी नौकरी में घुस गये हैं। यह प्रत्यक्ष केस है जिसे सरकार को हाथ में लेना चाहिये और इन महाशयजी ने जो गलत बात की है उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिये।

दूसरे हैं इन्हीं महाशय के छोटे भाई संतोषकुमार जैन। उन्होंने हमेशा से मुख्त्यार आम का काम किया है। जागीर कर्मचारियों की मांग की गई तो मेंदवास ठिकाने में सर्टिफिकेट लेकर पेश कर दिया कि हमारे यहां ५ साल से कामदार हैं। इसके बाद वे यह करते हैं कि उस वक्त जो कलेक्टर साहब थे, जो अब दिल्ली चले गये हैं, उन्होंने कहा कि तुम तो यहां काम करते थे तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो ठाकुर साहब की इज़ाजत से यहां काम करता था। उनको एस. डी. सी. में ले लिया जाता है; यह सरकारी अधिकारियों की बुद्धिमत्ता का परिचय है।

एक साहब उदयसिंहजो हणूत्या बडवाड़ा के बारेठ है। वह एक छोटा सा दो-तीन हजार का ठिकाणा है, ३०–४० हिस्सेदार हैं, किसी के १०० की जागीर है, किसी के १५० की जागीर है। उस ठिकाने से लिखवा लिया कि उदयसिंहजी हमारे यहां १४०) रुपये माहवार पर नौकर थे। सरकार को सोचना चाहिये-कलेक्टर कमिश्नर महोदय आज-कल आइ. ए. एस. हैं, आर. ए. एस. हैं उनको सोचना चाहिये था कि २–३ हजार की जागीर में अगर १४० रुपया माहवार तनख्वाह देकर आदमी रखेंगे तो दो हजार रुपये तो इसकी तनख्वाह के ही हो गये, फिर राज्य में भी कुछ भरना पड़ता होगा। तो फिर जागीरदार क्या फाके करते थे, वे क्या करते थे? परन्तु उनका भी प्रभाव लोगों में कुछ है इसलिए उन्हें भी १५०) रुपया माहवार पर ले लिया गया है। इस प्रकार जागीरी कर्मचारियों के एपॉइन्टमेंट में पक्षपात की नीति अपनाई है। इसके बारे में मैं अर्ज़ करूंगा कि सरकार के साथ जिन लोगों ने ४२० की है उन्हें फौरन हटाया जाय और जो वास्तव में जागीरों के कर्मचारी हैं उनको लिया जाना चाहिये।

अब मैं, जो हिन्दी–अंग्रेजी कुछ भी नहीं जानते उनकी मिसाल कि उन्हें सरकारी नौकरी में रख लिया गया है, इसके बारे में सरकार के सामने कुछ उदाहरण रखूंगा। कुछ आदमियों के केस जयपुर एस. डी. ओ. के पास पड़े हुए हैं। उनको कह दिया जाता है कि तुम अंग्रेजी नहीं जानते। माननीय मन्त्री महोदय, कमिश्नर महोदय चाहेंगे तो मैं उनके नाम दे दूंगा। वैसे एक मामला मैंने पिछली मर्तबा सरकार के सामने रखा था और सरकार को मालूम है कि वह क्या था। इस प्रकार उन लोगों को कह दिया गया कि तुम अंग्रेजी नहीं जानते, तुमको लोअर डिविज़न क्लर्क्स में नहीं लिया जाता। उसी लोअर डीवीजन कर्ल्की में अंग्रेजी जानना तो दूर रहा, एक महानुभाव हैं दौलतसिंह, जो अपना नाम लिखना जानते हैं, वह भी इतने बड़े हरफों में कि दस्तखत करते हैं तो दौलत सिंह, दस्तखत से ही कॉपी का आधा पन्ना भर जाता है, उन्हें लिया गया। जो अंग्रेजी जानते हैं, हिन्दी जानते हैं उनको तो एस. डी. ओ. साहब ने यह कर कर टरका दिया कि वे अंग्रेजी नहीं जानते और दूसरी ओर यह एक ऐसी मिसाल है कि जो पूरे दस्तखत तक नहीं करना जानता उसको लोअर डिविज़न क्लर्क में रख दिया जाता है। एक और मिसाल है। एक मुसलमान हैं जो किशनगढ से आये हुए हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से यह तज़वीज़ पेश हुई कि उन्हें अपर डिवीज़न क्लर्क में ले लिया जाय. वे अंग्रेजी की ए. बी. सी. डी. भी नहीं जानते, अच्छी तरह हिन्दी भी नहीं जानते, उनकी पर्सनलीटी देखी जाय या मंत्री महोदय अपने सामने बुलाकर उनसे बात चीत करें; परन्तु शर्त यह है कि मैं भी मोजूद होऊं, नहीं

[श्री गुरुदयालसिंह सिंधु]

तो मेरी अदम मौजूदगी में मन्त्री महोदय दूसरी तरह का ही सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या यह भी संभव है कि उसके बजाय दूसरा आदमी ही लाया जाय। उसको यू. डी. सी. में ले लिया गया है। लोग कहते हैं कि राजस्थान में जातिवाद है, फिरकापरस्ती है। मैं तो कहता हूं कि इस राजस्थान सरकार में तो सभी वाद हैं। चौमू ठिकाने के दो आदमी सिलेक्ट हो गये थे। उन्होंने अर्ज किया कि जब तक ठिकाना रिज्यूम न हो जाय तब तक हम को नौकरी पर न बुलाया जाय। उन दो आदमियों में से एक तो सिपाही रेन्क का आदमी था, और दूसरा १२५) रुपये माहवार तनखा पाने वाला था। अध्यक्ष महोदय, जो सिपाही रेन्क का आदमी था उसे यह कह दिया गया है कि जब तक ठिकाना रिज्यूम नहीं होता है तुम वहीं काम किये जावो और जो दूसरा आदमी १२५) रुपये पे (pay) ले रहा था वह आज भी दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है और उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा है।

और यह मैं आपको बता दूं, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैंने यह जो मिसाल दी है उसमें जाटवाद का प्रश्न नहीं। वे एक मुसलमान हैं और उनने इस प्रकार का ऑर्डर दिया है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां सब जातियों का जाति वाद चलता है। ये चन्द बातें अध्यक्ष महोदय, मैं नामजद करके बताना चाहता हूं। मन्त्री नये नये आये हैं, नये नये मंत्री के नाते कुछ कर गुजरेंगे तो नाम होगा; वर्ना मंत्री-मण्डल बनता है और चला जाता है, यह तो दुनियां जानती है।

इसके अलावा लॉ एन्ड ऑर्डर की बड़ी धूम है। मैं मानता हूँ कि लॉ एण्ड ऑर्डर के जो बड़े मामलात, मसलन डकैतियां वगैरह, में कमी हुई है, इसको डिनाइ करना मैं गलत मानता हूँ। लेकिन लॉ एन्ड ऑर्डर की जो हालत गांवों में आज है उसके लिये अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें सुधार की गुंजायश है। हमारी सरकार ने और हमारे पुलिस फोर्स ने अपना ध्यान ज्यादा डकैतियों की तरफ आकर्षित किया है। इससे यह हुआ है कि गांवों में चोरियें वगैरह इतनी हुई कि उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया और उसकी वजह से गांवों में लोगों को बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है और अगर हमारी सरकार चोरियों की तरफ ध्यान दे तो जरूर सुधार होगा। इसके मुत्तल्लिक मैं बजट पर जब भाषण होगा, कुछ मिसालें पेश करूँगा और आशा करूँगा कि सरकार कुछ जनता की भलाई करे। अभी मैं कुछ जल्दी में हूँ, घड़ी दौड़ी जा रही है और मैं खुद जल्दी करना चाहता हूँ।

मैं एक बात के सम्बन्ध में, जो मेरी कॉन्सटीट्युएन्सी इफेक्ट करती है जरूर निवेदन करना चाहता हूँ और वह खास बात यह है कि श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में उसका जिक्र हुआ है। वह है हमारे राजस्थान का सेटलमेंट डिपार्टमेंट। अध्यक्ष महोदय, सेटलमेंट डिपार्टमेंट के बारे में जो कुछ भी कहा जावे वह थोड़ा है।

हम देखते हैं कि इस विभाग में हजारों स्क्वायर मील जमीन की पैमायश हुई है और पर्चे बांटे गये है, लेकिन राजस्थान के अन्दर एक मेरी ही कॉन्स्टीट्युएन्सी ऐसी अभागी है कि जिस पर सेटलमेंट विभाग की खास कृपा रही है, जिस पर सेटलमेंट विभाग का कोपभोजन रहा है। वही एक ऐसा

[श्री गुरुदयाल सिंह सिंधु]

इलाका है जिसके अन्दर १७ रुपया प्रति बीघा का लगान बंधा है और वह भी एक जागीर का इलाका है और वह खास इलाका है अचरोल का। वहां पर पर्चे बंटे करीब ३ वर्ष हो गये हैं लेकिन वहां के किसानों की पुकार कोई आदमी सुनने को तैयार नहीं। किसान चिल्ला चुके है किन्तु कोई सुनने वाला ही नहीं। बाद में इसकी जांच करने के लिये सरकार ने एक बड़े आला अफसर जो पहले एस. डी. ओ. आमेर में थे, उनको मुकर्रर किया कि इसकी जांच करके रिपोर्ट पेश करे। उसका भी एक रहस्य है। वे इसकी जांच कर रहे थे कि उसी बीच में उनका सांभर तबादला हो गया। वे रहने वाले जयपुर के हैं। उन्होंने देखा कि अगर इसकी रिपोर्ट जल्दी पेश कर दी तो उनका जयपुर आना जाना बन्द हो जावेगा, इसलिये उन्होंने इस मामले को ऐसा खत्ते में डाला कि कई दिनों तक रिपोर्ट नहीं पहुंची और इस रिपोर्ट के नाम से वे सप्ताह में ४ दिन जयपुर में रहते थे। इसके लिए आप रिपोर्ट मंगवा कर देखेंगे तो आपको मालूम होगा। जब वे हमारे आमेर में एस० डी० ओ० थे और आमेर में ही मौजूद थे उस समय भी वे इसके बहाने महावार में ४ मुकदमों का ही फैसला करते थे। योग्य माने जाते हैं और अब उनको एक्सटेन्शन ब्लॉक्स के काम पर भेजा गया है। वे बहुत काबिल एस. डी. ओ. माने जाते हैं। उनकी काबलियत का नमूना तो यह मुकदमों का फैसला महावार करते थे। अगर इनमें गलती हो तो आप कलेक्टर और कमिश्नर की रिपोर्ट मंगवा कर देख सकते हैं कि कन्हैयालाल बर्डिया ने महावार चार मुकदमें ही फैसल किये या इससे ज्यादा। आज ८–१० सेर का भाव है और इस भाव में आप यह उम्मीद करते हैं कि १७ रुपया प्रति बीघा लगान और उन गांवों में जैसे चारनवास, चक जिनमें कूओं में पानी नहीं है, वहां पर किसान १७ रुपये नहीं दे सकेंगे और इसका नतीजा यह होगा कि लोग लगान नहीं दे सकेंगे और नहीं देंगे। इससे राजस्थान को घाटा होगा। इसलिये सरकार को चाहिये कि इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करे। मैं जमुआ रामगढ़ के लिये किसी तरह का पक्षपात नहीं चाहता मैं यह चाहता हूँ कि जो चीज बिल्कुल वाजिब हो उसको मान कर सरकार को कार्य करना चाहिये।

सेटलमेंट के अलावा मैं थोड़ा सा शिक्षा विभाग के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूँ, जिसके बारे में भी हमारे यहां असंतोष है। हमने यह देखा है कि रियासतों के समय शिक्षा के मामलों में इतना भ्रष्टाचार नहीं था। आज शिक्षा विभाग में १६–१७ साल के बच्चे मास्टर बना दिये जाते हैं। एक गांव में एक ही मास्टर रहता है। शिक्षा विभाग में जो मास्टर लिये गये हैं उसकी उम्र १८ साल की है उसका मेरे पास प्रमाण मौजूद है और अगर शिक्षा मंत्री चाहेंगे तो मैं बताऊँगा। मैंने यह शिकायत डिप्टी डाइरेक्टर को की है वह नियुक्ति डाइरेक्टर साहब की सिफारिश से हुई है। अगर आप इसमें कुछ कर सकें तो कुछ कीजिये। इस पर डिप्टी इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स को जांच के लिए भेजा गया। वे जांच कर लेते हैं। इस जांच में यह साबित होता है कि उनकी उम्र बहुत कम है। उनके आने से पहले उस स्कूल में ४० लड़के आते थे और आज ७ लड़के उस स्कूल में होते हैं। जांच करने के लिये आये तो मास्टर कहते हैं कि कुल लड़के १५ है और आज ८ गैर हाजिर हैं। तीन महीने डिप्टी इन्सपेक्टर को जांच किये हुए हो गये, लेकिन आज तक उस जांच का क्या हुआ, कोई पता नहीं। यह एजूकेशन का नमूना पेश करता हूँ। अगर आप चाहें तो सैकड़ों मिसालें दे सकताहूँ। श्रीमन् राजप्रमुख ने भाषण दिया है। उसके धन्यवाद के प्रस्ताव का हम सपोर्ट

[श्री गुरुदयालसिंह सिंधु]

तो करेंगे ही, लेकिन हमारी अन्तर्आत्मा दुःख पाती है, इसलिये यह बात कहता हूँ । तो शिक्षा विभाग के मुतल्लिक मुझे यही कहना है ।

दूसरी विचित्र बात यह है कि पिछली दफा जमुआ रामगढ़ के अन्दर हाई स्कूल खोलने के लिये वहां की जनता से वायदा किया गया था । उन्होंने कहा कि मकान बढ़ा लो । नक्शे बना लिये और यह कहा गया कि वहां पर अगले जुलाई में हाई स्कूल खोला जावेगा । यह काम करने के बाद भी वहां हाई स्कूल नहीं खोला गया । दुर्भाग्यवश मैं भी शिक्षा सचिव से इस सम्बन्ध में मिला । उन्होंने कहा कि हाई स्कूल का प्रॉपोजल आया हैं । जुलाई में जब देखा तो वहां के बजाय लालसोट हाई स्कूल कर दिया गया । जब सरकार ने ऐसा किया तो जमुआ रामगढ़ में जिन लोगों ने हाई स्कूल के नाम से चन्दा इकट्ठा करके इमारत बनाई, उसका क्या होगा ? इसी प्रकार का हाल कोटला का है ।

अब इससे ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाकर मैं मेडिकल एन्ड हैल्थ का नमूना पेश करूँगा ।

कुछ विभागों के अन्दर मैंने एक ऐसी चीज़ देखी है जो शायद किसी एम० एल० ए० ने अब तक नहीं देखी होगी । वह चीज़ क्या है ? रामगंज बाजार में आयुर्वेद का दफ्तर है । वहां चले जाइये । उस दफ्तर में कोई अफसर नहीं है । एक ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट बैठे रहते हैं । दुर्भाग्य की बात है कि सारे महकमे में कोई अफसर नहीं है ।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—आपको मालूम नहीं हुआ होगा । (हंसी)

श्री मानसिंह महार—मुझे मालूम है । भ्रम फैलाने वाली बात मेरे मित्र ने कही है । लोकल सेल्फ डिपार्टमेन्ट के मन्त्री हैं...

("सचिव" इस प्रकार की आवाज)

सचिव है । मैं हिन्दी में गलत बता गया, उन्हें सौ, दो सौ रुपया मिलता है और वहां भी काम करते हैं । इस विभाग से भगवान ने वास्ता कभी नहीं पटका, लेकिन दुर्भाग्यवश अब यह हुआ कि मेरे गांव में एक औषधालय है । जब जागीर का चार्ज दिया तो औषधालय को भी सम्हाला । दुर्भाग्यवश मैं मारा मारा गया रामगंज बाजार में । एक दिन होता है अध्यक्ष महोदय, (हंसी) कि मैं गया रामगंज बाजार में...(हंसी)

तो ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ड साहब विराजमान थे । उनका नाम किशनलाल जी है । सेक्रेटरी साहब नोट करना चाहे तो कर लें । वे विराजमान थे, कागजों को धड़ाधड़ निकाल रहे थे । मैं जाकर बैठ गया कि यहां की भी रंगत देख ले मानसिंह । वे कागजात निकालते रहे, अध्यक्ष महोदय । सचिव महोदय उन दिनों ट्रावनकोर-कोचीन गये हुए थे और उनकी जगह श्री जयरामदासजी आयुर्वेद कालेज के प्रिन्सिपल दो से चार बजे तक, दो घन्टे काम करते थे । तो वे विराजमान थे । ऑफिशियेटिंग डाइरेक्टर साहब आ गये, कागजों को निकालते रहे । डाईरेक्टर साहब के आते ही ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट

[श्री मानसिंह महार]

साहब कहिये, पी० ए० कहिये सर्वेसर्वा वे ही थे, क्या व्याख्या करूँ, मैं नहीं जानता। मैं ऑफिशियेटिंग डाईरेक्टर साहब से मिला, औषधालय के कागजों के बारे में कहा। उन्होंने चपरासी से कहा कि उन्हें जाकर बुला लाओ। उन्होंने जवाब दिया कि मैं सुबह से पिस रहा हूँ। चाय पीकर आऊँ गा। १५ मिनट हो गये, मुझे देरी हो रही थी। उनसे जवाब आ गया कि महार के औषधालय के कागज आज नहीं मिल सकेंगे क्योंकि क्लर्क जिसके पास ये कागज है छुट्टी में गया हुआ है। मैं उठकर चला आया। सोचा, मानसिंह यहां तेरी नहीं चलेगी। यह हाल है। हम चाहते हैं कि आयुर्वेद की तरक्की हो, सस्ती दवाइयां जनता को मिले, लेकिन उस विभाग का यह हाल है।

हॉस्पिटल के डा० शर्मा ऑपरेशन करने में निपुण हैं। उनको डाईरेक्टर; मेडीकल एन्ड पब्लिक हैल्थ सर्विसेज बना दिया गया है। मैं वहां एक काम से चला गया कि शर्मा से सलाह-मशिवरा करूँगा। फिर मुझे वहां पता लगा कि वे तो सेक्रेटेरियेट में चले गये हैं। योग्य आदमियों को क्लेरिकल काम दे देंगे तो योग्यता का क्या होगा। ये चन्द बातें हैं जिनका मैं वर्णन करना चाहता था। बहुत सारी बातें हैं। यह ही एक ऐसा डिपार्टमेन्ट है।

रिश्वतखोरी हरएक डिपार्टमेन्ट में हो रही है, जिसके बारे में कहना है। पहले भी रिश्वतखोरी होती थी किन्तु वह बहुत कम मात्रा में थी। अब तो बढ़ रही है। राजस्थान में एक नई बीमारी शुरू हुई है और वह यह है कि हर एक विभाग के अन्दर सरकारी कर्मचारी सरकार का पैसा लेकर भाग जाते हैं और फिर कुछ नहीं होता। इस प्रकार सरकार का लाखों रुपया चला गया और कल ही मेरे एक मित्र ने जिक्र किया था कि एक व्यक्ति ने गबन किया और वह धौलपुर से पाकिस्तान चला गया। राजस्थान में केवल यही एक असेम्बली डिपार्टमेन्ट है जो बचा हुआ होगा, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए कई विभाग है।

श्री अध्यक्ष—Thank you vary much.

श्री मानसिंह महार—गबन के केसेज़ होते हैं। इसमें कई मिसालें हैं। एक साहब रेलवे मजिस्ट्रेटी में थे। २१००) का गबन कर लिया। रुपया बरामद कर लिया गया, रुपया रोक लिया गया, उनका कुछ नहीं हुआ। वे रिइन्स्टेट किये जाकर काम कर रहे हैं। केस तो नहीं चला। कोर्ट अगर बरी कर देती तो समझते कि अदालत में कुछ कर लिया। केस नही चला, वार्निंग तक नहीं हुई उस शख्स को। भ्रष्टाचार का महकमा है उसमें उनके कागजात जरूर हैं। वहां भ्रष्टाचार होता है या निरोध होता है, इसका फैसला बाद में देखा जायगा। इस प्रकार की बातें होती है। आप ध्यान देंगे। कुछ मामलों में देखा कि सरकार कोशिश करती है पर नीचे के कार्यकर्ता सुनते कम हैं। तो कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए। ऐसी बातें सरकार कर लेगी और जनता को फायदा पहुँचा तो हम सहर्ष धन्यवाद देंगे।

एक बात और है। (घंटी)

प्रिविलेज का मामला है, निवेदन करना है। श्रीमन् राजप्रमुख हमें १-२ बार अवश्य यहां दर्शन देते हैं। उनके सेक्रेटेरियेट का यहां कोई है या नहीं, मैं नहीं जानता। सेक्रेटेरियट की यह हालत

[श्री मानसिंह महार]

हो रही है कि एम. एल. एज. की कोई भी कार्य है तो उन्हें उसी प्रकार इग्नौर (ignore) किया जाता है जैसे घी में से मक्खी को बाहर निकालना। धन्यवाद मांगते हैं, छः महीने में या साल में वे धन्यवाद मांगते है और हम उनको धन्यवाद देते है तो वे भी हमको धन्यवाद दें । (हंसी) और मंत्री जी को निवेदन करूंगा कि जागीर डिपार्टमेन्ट की जो दुर्दशा है, उसको अवश्य ध्यान में रखें । चाहिएगा उतनी मिसालें दूंगा, आगे जब मिनिस्टर ध्यान देंगे। एस. डी. ओ. कलेक्टर सब अपनी सिफारिशों में मग्न रहते हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं जानना चाहूंगा ट्रेजरी बेंचेज़ से कि कितने मिनिस्टर जवाब देना चाहेंगे । अभी दस मिनिट और हैं। कल रखें या आज शाम को रख दें? ऐसा है कि ४ तारीख तक का प्रोग्राम है, ४ तक हमें सप्लीमेन्टरी डिमान्ड्स लेनी है। चाहें तो फिर ५ को बैठें, किन्तु ५ को सन्डे है। यदि अधिक बोलना चाहें तो सेटर्डे को बैठ जांय ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री)—मेरा ख्याल है कि सप्लीमेन्टरी डिमान्ड्स पर ज्यादा बहस नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष—या तो फिर बजट पर बोला जाय या सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड्स पर कम बोला जाय ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कल सप्लीमेन्टरी डिमान्ड्स पेश हो जाय।

श्री अध्यक्ष—राजप्रमुख के भाषण पर बहस समाप्त न हो जाय तब तक सप्लीमेन्टरी डिमान्ड्स नहीं ले सकते।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कल का आधा टाइम।

श्री अध्यक्ष—कितने मिनिस्टर जवाब देंगे?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—तीन तो बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष—कितना टाइम लेंगे?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—चीफ मिनिस्टर १ घंटा लेंगे।

श्री अध्यक्ष—वे ४० मिनट लेंगे ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—और सब मिला कर ४० मिनिट और समझ लीजिये।

श्री अध्यक्ष—कल फिनिश कर दें, नहीं तो we will meet on the fifth, saturday

श्री जवानसिंह—शनिवार चूंकि होली की छुट्टियों से पहले पड़ता है इसलिये उस रोज तो अवकाश रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—या तो आप ऐसा करिये कि बोलने वालों की संख्या कम हो या दोनों समय कार्यवाही जारी रखें।

श्री हिम्मतसिंह—बोलने वालों की संख्या में कमी की जा सकती है।

श्री रामकिशोर व्यास—माननीय अध्यक्ष, गवर्नमेन्ट की तरफ से केवल दो ही मन्त्री बोलेंगे, एक तो श्री कुम्भाराम जी और दूसरे स्वयं मुख्य मन्त्री।

श्री ईश्वरीसिंह—अध्यक्ष महोदय, राजप्रमुख के भाषण में जो बातें आई हैं उनमें राजप्रमुख ने यह बात कही है कि आज कुदरत ने उनका साथ दिया है; ठीक है। कुदरत ने भी साथ दिया, गवर्नमेन्ट का हाथ मजबूत किया। सरकार ने हमारे इलाके में १०८ गांवों को लगान की छूट दी है। वह किन किन को दी गई, यह देखने की बात है। हमारे इलाके में दो तहसीलें हैं; एक तो सीकर और दूसरी फतेहपुर। फतेहपुर तहसील में कांकड़ हैं; जैसे असेम्बली में अध्यक्ष के समीप। तो नवलगढ को इलाको है और दरवाजा तक जो छेटी है उनमें कांकड है इस पचास मील के फासले में जो १०८ गांव हैं उनमें लगान की छूट दी गई है। सीकर को एक गांव लियो है होणासूं ठीक है। कुदरत को खेल है कि इण इलाका में पानी की कमी फसल अच्छी हुई और कुदरत कांग्रेस के हाथ में आयगी। राजप्रमुख रे भाषण में आ बात हो कि वे कल्याणकारी राज बना रह्या है ठीक है कल्याणकारी राज्य इणी तरह सूं बण सके है। जो भूमिहीन किसान हा ठावा सूं कितना तीन सालों में बसा दिया गया। आज जो कुछ रह गया है वे भी जल्दी ही चौपट होजावण वाला है। आज कई भूमिहीन किसानों की जमीन उजाड़ दी गई है। बांके वास्ते कोई इन्तजाम आज तक सरकार नहीं कर पाई है। और राजप्रमुख के भाषण में क्या इसी तरह से कल्याणकारी राज्य को बनाने के लिये कहा गया है। अगर ऐसा राज्य बनाने के वास्ते धन्यवाद दियो जा रयो है तो म्हारो ओ कहणो हैं कि इतनो अन्याय तो राजा कंस के राज में भी नहीं हुयो, रावण के राज्य में भी इतनो अन्याय नहीं हुयो। हमारा अठे कलेक्टर है राजपूत जाति रो बड़ो भलो आदमी है, पर म्हारो कहणो है कि उण गांवों की जांच करा ली जाय कि बठे आ हालत है या नहीं। तहसीलदार की ड्यूटी है कि वो दरखास्त ले, पण अटा सूं आर्डर चल्यो जाय तो वो दरखास्त ने फाड डाले है। म्हारो ओ कहणो है कि पचास गांवो की जांच करवा ली जाय। छूट क्यों दी गई क्यों कि वे कांग्रेस ने वोट दियो। इण वास्ते लगान की छूट दे दी गई और जिन लोगों ने किसान सभा ने वोट दिया व जगहां में ज्यादा काल होता हुआ भी लगान की छूट नहीं दी गई। जो इण प्रकार को अन्याय करे है आखिरकार पाप को घडो कदे न कदे तो फूटेला ही, जद भर जायगो तो फूट जासी। म्हारा तो ओ कहनो है कि इन गांवों की जांच करा ली जाय, जब ही कल्याणकारी राज्य समझ लियो जाय।

इनी तरह सूं डाकुओं की भी बात हुई है। डाकु मानसिंह है, जीरे वास्ते काफी पुलिस लगा रखी है। उणा ने सरकारी आदमियों ने भी मार डाल्या है फिर भी वो डाकू पुलिस पकड़ नहीं सक रही है। प्रत्यक्ष ने प्रमाण की जरूरत नहीं। आज सैकडों गांवां ने लगान री छूट दी है, उण में भी भेद है। आज बीकानेर रे कुम्भाराम री मिनिस्टरी है इण वास्ते बीकानेर का कई गांवों ने लगान माफ कर दीनी है। इण वास्ते म्हारो तो ओ कहणों है कि इण गांवा में छूट दी गई है उणरी जांच करवा ली जाय। यदि वो सही जान पड़े तो कल्याणकारी राज्य समझो जाय।

[redacted]

श्री अध्यक्ष—जवाब के लिए कल रक्खें।

श्री श्रीदास गोयल—बाकी स्पीकर्स के लिए क्या होगा साहब ?

श्री अध्यक्ष—कल जवाब के लिए रक्खेंगे।

(विराम)

We Can sit upto one today.

श्री श्रीदास गोयल—अध्यक्ष महोदय, जहां तक राजप्रमुख के भाषण से सम्बन्ध है, उसका जिक्र करते हुए बहुत से मित्रों ने फरमाया उसको दोहराने से तो कोई लाभ नहीं, लेकिन वस्तु स्थिति का सही ज्ञान हो ऐसी आलोचनाओं का स्वागत करते हुए माननीय मन्त्री महोदय भी जब उन तमाम आलोचनाओं, प्रत्यालोचनाओं का जवाब दें तो जरूर ध्यान रक्खेंगे, ऐसी आशा है, कि जो कुछ भाषण में इसमें है और यह होगा, वह होगा; ऐसा लम्बा चौड़ा बयान है, पर आज की सही स्थिति क्या है; आज इसका करीब करीब नहीं के बराबर जिक्र किया गया है। तो इस स्थिति में एक बात तो हमें माननी ही पड़ेगी कि जिस गति के साथ राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहिये था इस पंचवर्षीय योजना को लेकर और इसके लिए जो जागरूकता और उत्साह हममें होना चाहिये था वैसा नहीं रहा। इसका प्रमाण एक नहीं अनेकानेक बातों से मिलता है। आपकी चंबल योजना को ही ले लीजिये। मैं मध्यभारत गया तब काटजू साहब योजना का उद्घाटन करने वाले थे और आने वाले थे। मैंने वहां देखा कि चंबल का नारा इतना बुलन्द किया जा रहा है कि लोग "जय चंबल" उसी उत्साह से बोलते हैं जिस उत्साह से "भारत माता की जय", "महात्मा गांधी की जय" और "जवाहरलाल नेहरू की जय" बोलते हैं। जहां मध्यभारत में यह हो रहा है वहां हमारे राजस्थान में हम देखते हैं तो नाम मात्र का उत्साह लोगों में मिलता है। सरकार सही ढंग से इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि मध्य-भारत में काफी प्रगति इस दिशा में हो गई है। भाषण जरूर काफी हुए और एक सुनहला स्वप्न, भविष्य को सुनहरा संसार दिखा दिया गया कि चंबल योजना इस तरह बनाई जा रही है, इससे इतनी राहत लोगों को पहुंचेगी, इतनी बिजली की पैदावार हो जावेगी; इतनी अनाज की उत्पत्ति बढ़ जावेगी, राजस्थान धनागार बन जावेगा, लेकिन वह राहत कब व किस तरह से पहुंचेगी वह धानागार कब व किस तरह से बनेगा, वह बिजली का जाल कब व किस तरह से फैलेगा ? इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय कोई भी आश्वासन दें तो अपनी जिम्मेदारी को समझकर दें और सफल कदम उठाने की निश्चयात्मक भावना से दें। क्योंकि इसके बारे में प्रगति का सुनना तो दूर रहा भ्रष्टाचार के सिलसिले में हमारे इसके कड़वे अनुभव हैं। सरकार इसके लिए कमेटियां बिठाती हैं, वे कमेटियां पहले भी बिठाई थीं और आज भी बिठा रही हैं। पर यह कोई सफल कदम नहीं है भ्रष्टाचार को रोकने का। इसको रोकने के लिए तो अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा, अपने चरित्र बल को मजबूत बनाना होगा और जो भलाई की चीज है उसको कार्यान्वित करने के लिए सबल निश्चय की जरूरत होगी। तो मैं केवल ये दो शब्द कहकर सरकार से निवेदन करूंगा कि वे संगठित होकर इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ करें, वरना इन कमेटियों से कुछ होने जाने का नहीं है।

इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये हमें और तरीके अपनाने होंगे। भेष बदलकर मिनिस्टर महोदय दौरा करें और प्रत्यक्ष देखें कि पुलिस में, थानों में, अदालतों में व अन्य जगहों में किस

[श्रीदास गोयल]

प्रकार लोगों को लूटा जा रहा है और किस प्रकार की गड़बड़ियां होती हैं। जहां कहीं हम दौरे में जाते हैं तो भेष बदलकर नहीं जाते और अधिकारी गण सही स्थिति इस कारण हमारे सामने नहीं आने देते। अगर इस भ्रष्टाचार को हमें देखना है और इसे मिटाना है तो हमें अपनी भावनाओं को बदलना होगा और भेष बदलकर यह सब देखना होगा। तभी भ्रष्टाचार का सही रूप हमारे सामने आवेगा। मैं मिनिस्टर महोदयों से निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और इस भ्रष्टाचार को मिटाने में वे आजतक जितने सफल हुए हैं उसका तो उनको अनुभव है ही। अब भविष्य में ज्यादा सफल बनने के लिए कम से कम वे राजस्थान के कोने कोने का भेष बदलकर दौरा करें और फिर देखें कि वास्तव में क्या होता है और कैसे होता है। यह भ्रष्टाचार ही एक ऐसी चीज है जो हमारी हर प्रगति के रास्ते में रोड़ा अटकाती है। अगर आलोचना सही है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिये। उस पर कुपित नहीं होना चाहिये। बहुत से ऐसे व्यक्ति सरकार में हैं जो सरकारी रुपया अपने खुद के उपयोग में लेते हैं। यह एक तथ्य है और इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। हमें अपनी प्रगती के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए, इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे। इसके बिना हमारी प्रगति सम्भव नहीं।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि सरकार के कई विभाग जो विकास की ओर ले जाने वाले हैं उनकी तरफ हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। वन विभाग के बारे में मैं एक निवेदन करूं कि एक तरफ तो हम यह कह रहे हैं कि वृक्ष उगाओ और अधिक मात्रा में उगाओ, ताकि हमारे इस रेगिस्तानी प्रदेश का जो निरन्तर तेजी से विस्तार बढ़ता जा रहा है और जो एक खतरा हमारे सामने पैदा हो गया है, वह रुक सके, हमारे वन समृद्धशाली हों ताकि हमारी भूमि समृद्ध बने, रेगिस्तान रुके; लेकिन दूसरी तरफ सवाई माधोपुर जिले का मुझे कम से कम अनुभव है कि वहां कई जंगल साफ किये जा रहे हैं और बड़ी तेजी से जंगल काटे जा रहे हैं। बहुत सम्भव है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला होने के बाद कुछ उपाय किया जा सके, पर आज उसको रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये।

केवल ये शब्द कहकर मैं निवेदन करूंगा कि राजप्रमुख के भाषण में जो हमें एक सुनहरा संसार बनने की संभावनाएं नजर आ रही हैं और उसके लिए जो आशाएं व्यक्त की गई हैं उनको कम से कम ध्यान में रखते हुए हमें धन्ययाद का यह प्रस्ताव पास कर देना चाहिये। और हिन्दी भाषा में बोलने का जो खयाल इस बार रक्खा गया यह बहुत शुभ है। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रक्खा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

पिछले सालों में राजप्रमुख के भाषणों में जो हमें एक विश्वास और आशा का सन्देश दिया गया था उसके बाद जो राजस्थान प्रदेश की प्रगति और उन्नति हुई है उसमें आर्थिक स्थिति का विश्लेषण कानून और व्यवस्था की उचित प्रगति और पंचवर्षीय योजना की प्रगति इन तीन चीजों को मद्दे नजर रखते हुए ही यह सम्पूर्ण भाषण है।

[श्री मोतीलाल चौधरी]

मैं पिछले साल जो जो सरकार ने किया है, उसकी सराहना करता हूं और वास्तव में कई मुद्दों के अन्दर काफी उन्नति हुई है।

सबसे पहले मैं क़ानून व व्यवस्था की ओर, माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा इस हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले जब हम इस हाउस में आये थे यानी जब चुनाव खत्म हुआ उसके बाद में पहली बार जब हम असेम्बली में मिले थे उस समय कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में जो, जो भाषण इस तरफ और उस तरफ के माननीय सदस्यों के हुये थे, उस समय जो वातावरण था, उसके बाद पिछले दो सालों में जो वातावरण था और जो आज वातावरण है, इसको अगर सही नज़र से देखा जाय तो उसके बारे में किसी की दो राय नहीं होंगी कि यहाँ कानून और व्यवस्था के अन्दर कितनी उन्नति हुई है।

उसके बाद में आर्थिक दृष्टिकोण से कितनी उन्नति हुई है, और पंचवर्षीय योजना सफल हुई है या नहीं हैं, इस संबंध में इस तरफ और उस तरफ बहुत से माननीय सदस्यों ने, कइयों ने, क्रिटिसाइज़ भी किया और सहमत भी हुए। मैं तो सिर्फ एक उदाहरण देकर ही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वास्तव में दो साल पहले राजस्थान के अन्दर खाद्य समस्या जो थी वह खाद्य समस्या किस तरह सुलझ गई है, और पंचवर्षीय योजना के अन्दर "Grow more food" "ज्यादा धान पैदा करने" का जो प्रोग्राम था वह पहले ही पूरा हो गया है। बाजार में धान के भाव जो इतने गिरे हैं इसका कारण यह है कि धान ज्यादा पैदा हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि पंचवर्षीय योजना का जो प्रोग्राम था कि किसी तरह से अन्न ज्यादा पैदा करके अन्न के अभाव को मिटाया जाय, वह पूर्ण हुआ है। वह ज़ाहिर करता है अपने आप ही कि धान ज्यादा पैदा हुआ है।

एक माननीय सदस्य—आँकड़े बताइये।

श्री मोतीलाल चौधरी—आँकड़े की ज़रूरत नहीं है वह बाज़ार के भाव से मालूम पड़ जायगा।

श्री अध्यक्ष—No such matter has been dealt in the Rajpramukhs Address.

श्री मोतीलाल चौधरी—साथ ही साथ जो मुझसे पूर्व बोलने वाले वक्ता साहब थे उन्होंने पंचवर्षीय योजना को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा है कि सरकार शिथिलता से काम कर रही है। उन्होंने क्रिटिसाइज़ करते हुए चम्बल पर जो मध्यभारत ने किया है उसकी प्रशंसा करते हुए जो भाषण दिया हाउस के मार्फत उस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वास्तविक उन्नति पंचवर्षीय योजना के अन्दर हुई है या नहीं हुई है। वह तो भाखरा डेम से जो पानी आया है उससे ज़ाहिर हो सकता है कि वास्तविक उन्नति हुई है और साथ ही साथ जिस तरह की टेक्नीकल डिफिकल्टीज़ के अन्दर वर्तमान पंचवर्षीय योजना चल रही है उन डिफिकल्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए राजस्थान के अन्दर जिस तरह की उन्नति हुई है उसको कम्पेयर किया जाय तो मेरे ख्याल से कार्य की प्रगती बहुत ही संतोष-जनक है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कितना पर्सेन्टेज खर्च हुआ है प्लान्ट के ऊपर ?

श्री अध्यक्ष—This is not a question hour.

श्री हरिकृष्ण व्यास—सीखा सिखाया बोल रहे हैं ।

श्री मोतीलाल चौधरी—वह सीखा हुआ तो आप बोल सकते हैं । माननीय अध्यक्ष, ऐसे माननीय सदस्य जो कि खुद सिखाया हुआ बोलते है इसलिये दूसरों को भी यही समझते हैं ।

लेकिन इतनी उन्नति होते हुए भी जो भी कार्य हुआ है, माननीय अध्यक्ष, उसके अन्दर एक चीज़ की कमी इस भाषण के अन्दर पाई है । सरकार की जो नीति है उस नीति के दो दृष्टिकोण दिखते हैं । भाषण में आर्थिक दशा के विषय में कहा है । उस आर्थिक दशा को किस तरह से राजस्थान में सुधारा जाय, किस तरह से अगला कदम उठाने का सरकार ने सोचा है, उस पर मेरी थोड़ी सी आपत्ति है । वह इस तरह की है कि पिछले भाषण के अन्दर यह आवाज़ पाई जाती है कि राजस्थान का आर्थिक सुधार करने के लिए राजस्थान सरकार खेती पर ज़ोर कम देकर इन्डस्ट्री पर ज़ोर दे रही है । माननीय अध्यक्ष, उसके साथ साथ यह भी आवाज़ इसमें पाई जाती है कि गावों की उन्नति कमती करके अरबन (शहरी) एरिया का (इम्प्रूवमेन्ट) ज्यादा किया जाय । उससे एक आभास पाया जाता है, उसके साथ साथ, कि किसानों की उन्नति कमती की जाय और पूंजीपतियों की ज्यादा उन्नति की जाय । इन तीन तरीकों से राजस्थान की आर्थिक उन्नति हुई या नहीं, मैं यह कहना चाहता हूं । मैं यह नहीं कहता कि अरबन एरिया का इम्प्रूवमेंट नहीं किया जाय, मैं यह नहीं कहता कि इन्डस्ट्री का इम्प्रूवमेंट नहीं हो, मैं यह नहीं कहता कि देश में पूंजीपति आगे बढ़ें नहीं; लेकिन उसके लिए क्या करना है, अगला कदम क्या हो सकता है, यह मालूम होना चाहिये । चाहता हूं मैं भी कि देश के अन्दर राजस्थान की उन्नति सब तरह से हो, इन्डस्ट्री में, अरबन एरिया में । लेकिन सबसे पहले किस जगह में किस तरीके से उन्नति हो, उसके लिये निवेदन है कि देश के अन्दर रहने वाली जहां ज्यादा जनता है उनको मदद मिलनी चाहिए । सरकार की नीति वर्तमान रूप में जिस तरह से चल रही है उससे मेरी आपत्ति है, माननीय अध्यक्ष, । इसीलिए मैं माननीय जोधपुर से आने वाले सदस्य को आंकड़े देकर बताउंगा । देश के अन्दर १०० में से ६० फी सदी के साथ में कमती हमदर्दी की भावना इस भाषण के अन्दर ज़ाहिर होती है । सबसे पहले मैं यह कहूंगा कि इन्डस्ट्री के मुनाफे के अन्दर कोई कमी होती है तो गवर्नमेन्ट सब्सिडीज़ देती है, लेकिन राजस्थान की उन्नति के लिए १,५५,००,००० में से १, ३०,००,००० किसान हैं । किसान ही नहीं हैं बल्कि ज़मीन की इन्डस्ट्री से खाते हैं । ज़मीन से डाइरेक्टर या इन्डाइरेक्टर खाते हैं । उस इन्डस्ट्री की पैदावार के भावों में गिरावट आई है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में गिरावट आई है । उनकी पैदायश में रुकावट आती है तो कोई सब्सिडी देने के लिए भाषण में ज़िक्र नहीं है । माननीय अध्यक्ष, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वर्तमान भावों में जो गिरावट आई है वह राजस्थान के इलाके में ही नहीं हिन्दुस्तान भर में है; लेकिन राजस्थान के अन्दर जिस तरह की गिरावट आई है उससे वास्तविक रूप में देश का आर्थिक ढांचा बिल्कुल ही परिवर्तित हो जायगा । गत वर्ष इसी महीने में जिस मोट का भाव एक रुपये का साढ़े चार सेर था उसका भाव अब एक रूपये का ११ सेर है । जिस गेहूं का गत वर्ष के इसी महीने में जो भाव था वह आधा होगया है । भावों में

(श्री मोतीलाल चौधरी)

गिरावट इतनी आ चुकी है कि २० रु० मन का १० रू० मन हो गया है और जिस बाजरी का भाव एक रुपये का तीन सेर था वह आज ६ सेर का हो गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—६ सेर।

श्री मोतीलाल चौधरी—तो, माननीय अध्यक्ष, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो गिरावट आई है अगर उस गिरावट को नहीं रोका जायगा और सरकार इस इन्डस्ट्री को मदद नहीं करेगी तो इन्डस्ट्रीज राजस्थान में पनपेगीं या न पनपेगीं; क्योंकि इसके लिए खुद पूंजीपति रुकावट डालते हैं। उसके लिए तो मैं और आगे मौका मिलेगा तो बजट पर कहूँगा, लेकिन जिस इन्डस्ट्री पर राजस्थान का सारा आर्थिक ढाचा खड़ा हुआ है वह है खेती और कांश्तकारी, जिसमें १६५ लाख के अन्दर १३५ लाख जनता लगी हुई है। वह खेती नष्ट हो जायेगी। सरकार का जितना बजट है उसके अन्दर ८० प्रतिशत इस खेती पर निर्भर करता है। देश की उन्नति खेती पर निर्भर करती हैं। इसलिए खेती की पैदायश के भाव गिरेंगे तो देश की आर्थिक स्थिति गिरेगी। इन्डस्ट्रीज को बढ़ाने और और इन्डस्ट्रीयलिट्स को बढ़ाने के लिए जो प्रोग्राम है वह पड़ा रहेगा और जनता गरीब से गरीबतर होती जायगी। उसके उदाहरण बहुत हैं। माननीय अध्यक्ष, इसी भाषण में १ करोड़ का लोन इन्डस्ट्रीज़ को देने का प्रोग्राम रक्खा है। लेकिन मैं नही देखता कि खेती की पैदायश की, उस इन्डस्ट्री की जो चीजें हैं, उनके भाव गिर रहे हैं, उनकी मदद की जाय; उसका किसी तरह का उल्लेख नहीं है, और कुछ रुपया जो केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को दिया है भावों को गिरावट को रोकने के लिए उससे, कुछ सामान खरीदा जाय और किसानों के पास से सामान खरीद कर बाज़ार के भावों को निम्न स्तर पर लाने से बचा लिया जाय, लेकिन हमारी सरकार ने उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया है। (विरोधी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि) मुझे अफसोस है कि केन्द्रीय सरकार के आदेश के बाद भी यदि देश की आथिक स्थिति को सुधारने में सरकार हिम्मत से काम नहीं लेगी तो मैं कहूँगा कि सरकर को किसानों के प्रति हमदर्दी नहीं है (हीअर हीअर)। (हीअर, हीअर) की आवाज उस तरफ से आती है इस वजह से मैं जोश के साथ नहीं बोल रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble member should not be disturbed.

श्री हरिकृष्ण व्यास—We Wish that the Compliment paid to him should be heard.

श्री मोतीलाल चौधरी—जो वास्तविक स्थिति है उस पर मैं बोल रहा हूँ। मैं आपके जरिये हाउस और हाउस की मारफत सरकार से निवेदन करूंगा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जो पैसा भेजा है उसका सदुपयोग नहीं हुआ तो पंचवर्षीय योजना के पूरा होने के बाद भी देश की हालत गिर जायगी और उसकी राहत का कोई ज़रिया नहीं रहेगा।

दूसरी बात, मैं आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

[श्री मोतीलाल चौधरी]

सरकार जिस तरह से जनता को आर्थिक उन्नति करना चाहती है उसके लिए उसके पास कोई प्लान नहीं है। कुछ बात इधर से पकड़ली और कुछ उधर से पकड़ली, कोई चीज मध्य भारत की लेली तो कोई बंगाल की; इससे नहीं चलेगा। वास्तव में राजस्थान की स्थिति जो हैं राजस्थान के ढंग ही की अलग ही स्थिति है। दूसरी रियासतों के अनुसार नहीं हैं, जहां की जनता की स्थिति दूसरी तरह की है। उनकी दशा सुधारने के लिए राजस्थान की प्रगति करनी होगी। मैंने नहीं देखा कि राजस्थान की प्रगति हो रही है। हां, एक तमाशा अवश्य देखा और वह यह है कि राजस्थान के विकास के लिए जो मण्डल बना है उसके १८ सदस्य हैं, जिनमें से ९ सदस्य गवर्नमेंट के हैं और ९ जो नॉन ऑफिसियल्स हैं उनमें से ७ पूंजीपति हैं। मुझे अफसोस है कि इस जमाने में पूंजीपति जो राजस्थान में रहते नहीं हैं और दूसरी जगह रहते हैं, और जिनको राजस्थान की स्थिति मालूम नहीं है; वे चाहेंगे कि अपनी पूंजीपति भावना को पनपावें। वे अपने लिए यहां पर स्वर्ग उतार लाना चाहेंगे। वे लोग राजस्थान के हित के लिए कुछ नहीं कर पायेंगे। राजस्थान एक माने में बहुत आगे बढ़ा हुआ है। राजस्थान में पूंजीपति की प्रोबलम नहीं है। राजस्थान में सबसे बड़ी प्रोबलम जागीरदारों और राजाओं की थी। जिसको तो किसी तरह से कानून द्वारा हटाया गया। पूंजीपतियों की प्रोबलम यहां पर नहीं थी। उसको यहां पर क्यों पनपाया जा रहा है? क्या उससे विकास होगा (हिअर, हिअर) यदि आप इस नई प्रोबलम को यहां लायेंगे तो मसला सुधारना मुश्किल हो जायगा। राजस्थान की जनता को जो तकलीफ है उसको वे ही लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं जिनको जनता ने चुन कर भेजा है, और जिनको जनता चाहती है। उन्हीं में से बोर्ड बनाया जाना चाहिये था, न कि बाहर के आदमियों का जो कि जनता की तकलीफ को नहीं महसूस करते हैं, जिनको मालूम नहीं कि जैसलमेर और शेखावाटी कैसी है। क्या वे ही लोग निर्णय करेंगे हमारे विकास के लिए। इस लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि विकास के लिए केवल जन्म या खून होना ही काफी नहीं है। इससे जनता की उन्नति नहीं हो सकेगी।

सबसे बड़ा एक काम जो सरकार का है वह मैंने भाषण में नहीं पाया इसलिए मैं कहता हूं कि किसी भी देश और स्थान को यदि उन्नति करनी है तो वहां की बहु संख्यक जनता की आर्थिक स्थिति सुधारनी पड़ेगी, न कि कुछ आदमियों की ही। फंडामेन्टल प्रिन्सिपल्स डेमोक्रेसी के क्या हैं? वे यही कि बहुसंख्यक लोगों की स्थिति सुधारी जाय, नहीं तो पहले भी देश में राजा लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, एक तरह की गवर्नमेन्ट थी जिसमें थोड़े से आदमी मिलकर अपनी ही उन्नति करते थे, लेकिन आम जनता की उन्नति नहीं कर पाते थे इसलिए तो डेमोक्रेसी यहां आई। इस राज्य में, इस देश में, १ करोड़ ५५ लाख जनता रहती है जिसमें सिर्फ कुछ हजार आदमी ही पूंजिपति हैं जो बाहर रहते हैं और राजस्थान के नाम से कमाते-खाते हैं। मैं कहता हूं कि १ करोड़ ५५ लाख आदमी इसमें जो रहते हैं उनमें से १ करोड़ ५० लाख जनता गरीब है। सिर्फ ४० हजार लोग; बड़े बड़े जागीरदार पूंजिपति हैं; बाकी सब लोग गरीब हैं। जिस तरह वे लोग राजाओं के कानून से जर्जरित थे, फ्युडलिज्म से जकड़े हुए थे उसी तरह से आप देखेंगे कि मनी लैंडर्स गांवों और शहरों में गरीबों को तंग करते थे। उन्हीं मनिलेन्डर्स से आज भी जनता तकलीफ पा रही है। इस तरफ भाषण में कोई इशारा नहीं किया गया कि जो पिढ़ियों से जर्जरित लोग हैं उनको किस तरह से राहत देंगे, उनके लिए सरकार

[श्री मोतीलाल चौधरी]

ने कोई रास्ता नहीं निकाला (हीअर हीअर) । इस तरह के क़ानून ८ साल में ही नहीं बल्कि कई प्रान्तों में ब्रिटिश गवर्नमेन्ट के टाइम में आज से १० साल पहले भी बन चुके थे, कर्ज़ा मिटाने के कानून बन चुके थे । ३ साल बाद राजस्थान गवर्नमेन्ट नोंद में से उठेगी । राजस्थान बनने से पहले जोधपुर रियासत में डेट रिकंसीलियेशन क़ानून था लेकिन उसमें भी गरीब जनता को पूरी राहत देने की गुन्जायश नहीं ।

श्री अध्यक्ष—Is the Hon'ble member supporting the motion or speaking aginst it.

श्री हरिकृष्ण व्यास—He is not able, to resist his feeling, sir.

श्री मोतीलाल चौधरी—I am supporting the speech, but there are some suggestions which are assential.

श्री अध्यक्ष—By one o'clock the Hon'ble member should conclude his speech.

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय अध्यक्ष, इस देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये उन गरीबों को, जो कर्ज़दारी में फंसे हुए हैं, कर्ज़े के भार से बचाने के लिये कुछ न कुछ करना ही होगा । किसी के पड़-दादे ने उसके खड़-दादे का मौसर करने के लिये कुछ रूपये उधार लिये थे और उसने हज़ारों रूपये ब्याज़ के चुका दिये हैं, चक्रवर्ती ब्याज़ दे दिया है; लेकिन अब तक वह खाता खत्म नहीं हो पाया है । उस पर हमेशा इन्ट्रेस्ट बढ़ता ही जा रहा है । इसकी रूकावट के लिये सरकार को जल्दी से जल्दी क़दम उठाना चाहिये । लेकिन इस भाषण में इस सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं है इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार की गरीबों के प्रति इमदाद कम है । (हीअर, हीअर)

दूसरी बात मैंने यह पाई कि सरकार बाहर की चीजों पर नजर रखती है, लेकिन यहां क्या हो रहा है यह नहीं देखती । फाइव ईयर प्लान बना; भाखरा, चंबल, जवाई के लिये प्लान बने दूसरे प्रदेशों से संबंध रखते हुए । लेकिन हमारे लिये राजस्थान की स्थिति अलग है जिन इलाकों में पानी नहीं जा सकता है, नहरें नहीं बन सकती हैं उनके लिये कोई प्रबन्ध नहीं है । (हीअर, हीअर) मैं नागौर जिले का रहने वाला हूं । उस जिले में कहीं भी नहरें बनने की गुन्जायश नहीं है । न आज गुन्जायश है और न १०० वर्ष बाद होगी । किसी तरह उसकी प्रगति के लिये कुछ नहीं सोचा गया । ऐसी बात नहीं है कि उसकी उन्नति नहीं हो सकती । उसकी उन्नति दो तरह से हो सकती है । यहां पर खेती कुए खोदने से हो सकती है । कुए खोदने का कोई प्रोग्राम नहीं है आपके पास । इस तरह के और भी इलाके हैं राजस्थान में जिनमें ५ साल में न तो बिजली पहुँचेगी और न पानी पहुँचेगा और न नहरें पहुँचेगी । इसलिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जिन इलाकों में नहरें नहीं पहुँच सकती उन इलाकों को ग्रान्ट इन एड देकर वहां पर कूए खुदवाये जायं । कम से कम आप उनको इतना तो दे ही सकते हो जितना कि आपको वहां नहर लाने में खर्च करना पड़ता । जब गवर्नमेन्ट

Page No.70

[श्री मोतीलाल चौधरी]

ने दूसरे स्थानों के लिये एरेन्जमेन्ट (प्रबन्ध) किया है तो जहां नहरें नहीं आ सकतीं वहां तकावी ज़्यादा देकर कूए बनवाने का प्रबन्ध तो करना चाहिये। इसके आगे, माननीय अध्यक्ष, दो शब्द और कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा।

गवर्नमेन्ट का एक अभी (समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय यह बताना चाहता हूं कि सरकार की एग्रीकल्चर की प्रगति की तरफ किस तरह की शिथिल भावना है। यह इससे ज़ाहिर होता है कि सरकार ने इन्डस्ट्री के डेवेलपमेंट के लिए तो काफी बड़ी रकम भी निर्धारित की है और इसके लिये जो कमेटी स्थापित की है उसका चैयरमैन भी एक टॉप रैन्किंग इन्डस्ट्रियलिस्ट को बनाया है, पर जहां कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ को मदद करने की कमेटी बनाई है वहां एक कॉटेज इन्डस्ट्री का भला चाहने वाले को चेयरमेन बनाने के बजाय यहां भी एक इन्डस्ट्रयलिस्ट को ही चेयरमेन बनाया है, जो अपनी बड़ी इन्डस्ट्री का खयाल रखते हुए कॉटेज इन्डस्ट्री का क्या ख्याल रखेगा? फिर इन्डस्ट्री में जहां जितना रुपया सरकार ने दिया हैं उतना एग्रीकल्चर की उन्नति के लिए सारे राजस्थान की तकावी की रकम मिला कर भी कम होता है, अगर हम कम्पेअर करें टोटल अमाउन्ट ऑफ तकावी और इन्डस्ट्रियल फाइनेन्सियल कॉर्पोरेशन को जो रकम दी गई है उसको तो इन्डस्ट्री का अमाउन्ट दुगुना होता है। फिर इस इन्डस्ट्री में बोर्ड बनाते हुए यह कहा गया है कि लोकल इन्डस्ट्री को पनपने के लिए भी लौन देंगे। पर माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़े अफसोस की बात है कि इस स्माल स्केल इन्डस्ट्री की कमेटी का चेयरमेन बनाया गया हैं एक लार्ज स्केल इन्डस्ट्री वाले को जो सैद्धान्तिक रूपसे उसका एन्टी होता है वह क्या पनपने देगा इस स्माल स्केल इन्डस्ट्री को। अगर स्माल स्केल इन्डस्ट्री पनपती हैं तो लार्ज को नुकसान होता है, और लार्ज स्केल इन्डस्ट्री का नुकसान जब होता है तो पूंजीपति बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सैद्धान्तिक दृष्टि से ऐसा करने से कॉटेज इन्डस्ट्री के विरुद्ध यह बात पड़ती है।

इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा......

श्री हिम्मत सिंह—अब तो खतम करें। काफी समय हो गया है।

श्री मोतीलाल चौधरी—...आपके द्वारा सदन और श्री मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर ध्यान देकर विचार करें।

श्री अध्यक्ष—आप कई बार निवेदन कर चुके हैं।

(विराम)

Now we adjourn till tomorrow at 8-30 A. M.

(विधान सभा की बैठक १ बज कर ४ मिनट मध्यान्होत्तर में, कल प्रातः साढ़े आठ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक २ मार्च, १९५५ ।

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।